

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

1964-66

अनुरांसाओं का सारांश

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

1964-66

अनुशासकों का सारांश

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

1964-66

अनुशासकों का सारांश

शिक्षा विभाग राजस्थान के लिए
चित्रगुप्त प्रकाशन
पुरानी मण्डी अजमेर
(राजस्थान)



राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद्, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद् नई दिल्ली का स्वीकृति से शिक्षा
विभाग राजस्थान द्वारा प्रवृत्त एवं
प्रकाशित ।

यह पुस्तक या इसका कोई भी
परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना
पुनर्मुद्रित न किया जाए ।

पृष्ठ 3 50

प्रकाशक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
क निष्
चित्रगुप्त प्रकाशन
पुरानी मण्डी अजमेर

मुद्रक शक्ति प्रकाशन
आयुधमाज भाग, अजमेर

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

1964-1966

अनुशासकों का सारांश

लेखक

जे. पी. नायक

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई
दिल्ली द्वारा श्री जे. पी. नायक की प्रस्तावित पुस्तक
रिपोर्ट अर्द्ध शताब्दी के समारोह 1961-66
-समस्त शिक्षक-संघों का हितो अनुसार।

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, सभी क्षत्रा एवं सभी स्तरों की शिक्षा के विकास की नीति तथा शिक्षा के सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सलाह प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1964 को एक प्रस्ताव द्वारा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया।

शिक्षा आयोग ने अक्टूबर 2, 1964 को कार्यारम्भ किया।

(1) विद्यालयी शिक्षा, (2) उच्च शिक्षा, (3) प्राविधिक शिक्षा, (4) कृषि शिक्षा, (5) प्रौढ शिक्षा, (6) विमान शिक्षा एवं अनुसंधान, (7) शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षक का स्तर, (8) छात्र कल्याण, (9) नवीन तकनीक तथा पद्धतियाँ, (10) जनबल, (11) शैक्षिक प्रशासन, तथा (12) शैक्षिक वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में सामग्री तथा समस्या के विशद अध्ययन हेतु बारह इतिष दल (Task Force) का शिक्षा आयोग द्वारा गठन किया गया। इसके अतिरिक्त इसा उद्देश्य से सान कायकारी दलों (Working Groups) का भी गठन किया गया जिनका कायक्षेत्र इस प्रकार है (1) महिला शिक्षा, (2) पिछड़ी जातियों की शिक्षा, (3) विद्यालय भवन, (4) विद्यालय तथा समुदाय के सम्बन्ध, (5) साक्षरता, (6) पूर्व प्राथमिक शिक्षा और (7) विद्यालय पाठ्यचर्चा।

उक्त इतिष दल तथा कायकारी दलों के विस्तृत प्रतिवेदनों के आधार पर निम्नविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों शिक्षा शास्त्रियों, प्रशासकों तथा छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर, लगभग 9,000 व्यक्तियों (जिनमें प्रमुख समाजसेवी उद्योगपति बहानिक तथा अग्रशास्त्री सम्मिलित हैं) से साक्षात्कार तथा लगभग 2400 का सख्या में प्राप्त आपन-पत्रों के प्रकाश में शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 21 माह की अवधि में बाद जून 29 1966 को भारत सरकार को सौंप दिया।

शिक्षा आयोग के इस प्रतिवेदन के प्रकाशन की आज दो वर्षों से अधिक समय बीत गया है। इस बीच इस प्रतिवेदन को लेकर केंद्र तथा राज्य स्तर पर जो चर्चा हुई है शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं उनमें इस दलन में क्वि रगन सान व्यक्ति सामान्य धनमिष नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वरूप निर्माण में तो इस प्रतिवेदन की प्रमुख भूमिका रही है। और इगतिष यह और जो आवश्यक हा गया है कि एतिहासिक महत्त्व के इस दलनक का यथामम्भव अधिक गहराई में जाकर अध्ययन किया जाय।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के समय से ही शिक्षा विभाग राजस्थान की यह प्रबल इच्छा रही है कि यह प्रतिवेदन शिक्षा में रुचि रखने वाले तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों का सुख हो। क्योंकि मूल प्रतिवेदन अंग्रेजी में है और अधिक मूल्य का होने के कारण अधिकांश की संभवतः पहुँच के बाहर है अतः अभिप्रेत यह रहा कि इसका कोई संक्षिप्त हिन्दी स्पा-तरण जरूरतमंद व्यक्तियों को सुलभ कराया जाय। गौमाय्य से इसी बात थी जो पी नायक, जो शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव थे और जो आजकल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सलाहकार हैं 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली' के लिए शिक्षा आयोग के इस विंगल प्रतिवेदन का अंग्रेजी में संक्षिप्त-तरण किया। यह अंग्रेजी संक्षिप्त संस्करण यद्यपि हर तरह में उपयोगी है तद्विहिंदी में न होना के कारण हिंदी के माध्यम से ही शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समाधान ढोजने में सक्षम बग इसका लाभ बठिनाई से उठा पा रहा था। इस बग की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त जो पी नायक की रिपोर्ट अथवा द एम्प्लूव्मन्ट कमीशन 1961-66-ममरी अथवा रिक्मण्डेशन' (प्रकाशक-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली) का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का कार्य इस विभाग ने किया है। आशा है कि यह पुस्तक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय में स्थान प्राप्त करगी तथा सभी अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं था जो पी नायक तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की प्रकाशन इकाई का विशेषतः आभार है कि उन्होंने इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के लिए स्वादृति दन का अनुमोदना की।

बीकानेर

1 अगस्त 1968

हरिमोहन माधुर

अवर निदेशक

शिक्षा आयोग के सदस्य

अध्यक्ष

- 1 प्रो डा एम कोठारी अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

सदस्य

- 2 श्री ए आर दाऊद, भूतपूर्व कायवाहक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कामगम निदेशालय, नई दिल्ली ।
- 3 श्री एच एस एन्विन निदेशक, इस्टीमेट एवं एग्ज्यूकशन, सदन विश्वविद्यालय, लन्दन ।
- 4 श्री आर ए चापासास्वामी निदेशक, व्यावहारिक जनकाल शोध संस्थान नई दिल्ली (सभी से सवानिकृत) ।
- 5 प्रा सादातामी इहारा, स्कूल एवं सादन एण्ड इंजीनियरिंग, वासुदा विश्वविद्यालय, ताबयो ।
- 6 डा वा एम भा भूतपूर्व निदेशक, कामनवेल्थ एग्ज्यूकेशन स्थापन यूनिट लन्दन ।
- 7 श्री पी एन विरपाल, निगा मन्त्रालय तथा सचिव भारत सरकार, निगा मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
- 8 प्रा एम बी भापुर, अध्यक्ष एवं जन प्रशासन के प्राध्यापक, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (वर्तमान उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय) ।
- 9 डॉ बी पी पाल, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली (वर्तमान महानिदेशक तथा उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा ग्राह्य एवं कृषि मन्त्रालय में भारत सरकार के अवर सचिव) ।
- 10 कुमार एम पननन्धर, अध्यक्ष शिक्षा विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाह (सभी से सवानिकृत) ।
- 11 प्रो रोजर रिबन, निदेशक, सेंटर फॉर पापुलेशन स्टडीज, हावर्ड स्कूल एवं एग्निर हेल्थ हावर्ड विश्वविद्यालय, बर्किंग, संयुक्त राज्य ।
- 12 डॉ व जी गदगन, भूतपूर्व निगा मन्त्रालय भारत सरकार, एवं निगा एनियार्ड भवन आयाजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (अब सेवानिकृत) ।

- 13 डॉ डा सेन उपकुलपति जाल्मपुर विश्वविद्यालय बलकत्ता ।
 14 प्रा एम ए शुमाय्स्की निम्नव, मयाडॉलिड्रिल डिडिजन,
 मिनिस्ट्रा ग्रव हायर एण्ड स्पॉल सक्ण्डरा एज्युकेशन, धार एस
 एफ एम धार धोर भोनिनशास्त्र व प्राध्यापन मास्को विश्व
 विद्यालय, मास्को ।
 15 एम ज्यो टामस, इमपक्चर जनरल ग्रव ए-यूबेसन, फ्रांस, तथा
 महायन्त्र महानिर्देशक, यूनेस्को पेरिस ।

सदस्य सद्विष

- 16 श्री जे पी गायन, अध्यक्ष, शक्ति आयोजना प्रशासन तथा वित्त
 विभाग, गायले इन्स्टीट्यूट ग्रव पालिटिक्म एण्ड इकानामिक्स,
 पूना ।

सहयोग सद्विष

- 17 श्री ज एच मक्लूगन महायन्त्र निर्माण, डिपार्टमेण्ट ग्रव स्कूल
 एण्ड हायर एज्युकेशन, यूनेस्को पेरिस ।

अनुक्रम

अध्याय 1	पृष्ठ	पृष्ठ
भूमिका	1-2	1
अध्याय-2	3-23	2-13
शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन का स्पातरण	4-5	2-3
1 शिक्षा का उत्पादनो-मुग्धी बनाना	6-15	4-8
2 सामाजिक एवं राष्ट्रीय एवता की प्रगति	7	4
(i) राष्ट्रीय चेतना	8	5
(ii) सामाजिक भयका राष्ट्रीय सेवा	9-11	6-7
(iii) जन विद्यालय प्रणाला (बॉमन स्कूल सिस्टम)	12-13	7-8
(iv) अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव	14	8
(v) हिन्दी तथा अंग्रेजी	15	8
(vi) प्राधुनिक भारतीय भाषाएँ	16-17	9
3 मूल्य अनुस्थापन (वैल्यु ओरिवटेसन)	18-20	10-11
4 शिक्षण तथा मूल्यांकन की प्राधुनिक विधियाँ	21-23	12-13
5 लचोलापन तथा गतिशीलता	24-80	14-41
अध्याय-3	28-29	15-16
गुणात्मक सुधार	30	16
1 सुविधाओं का लयन उपयोग	31	17
2 अध्यापक	32	18
(i) पारिभनिक	33	18
(ii) भय लाम	34	19
(iii) काय एवं सेवा सम्बन्धी शर्तें	35-38	21-22
(iv) व्यवसायिक तयारी	39-45	23-24
3 विद्यालय पाठ्यचर्या	46-47	25-26
4 विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम का पुनगठन	48	26
5 विद्यालय पाठ्यपुस्तकें	49	27
6 उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें एवं भय	50-58	27-30
साहित्य		
7 धारों म पुस्तक निवरण		
8 शिक्षा प्रणाला म सुधार		

9	शक्ति सस्यामा के आधार तथा अवस्थिति सम्बन्धी योजना	64-69	78-81
10	गुणिपादा की व्यवस्था	60	81
11	छात्र सेवाएँ	61-63	83
12	प्रतिमादा की ग्राज एवं विकास	64-70	84-86
13	शक्ति सस्यामा में गुणार के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम	71-73	86-87
14	नव परियोजनाएँ	74-80	88-91
अध्याय-4			
शक्ति अवसरों के विस्तार तथा समन्वय सम्बन्धी समस्याएँ		81-110	92-91
1	प्राथमिक शिक्षा	83-85	92-93
2	श्रीर निरक्षरता का परिसमापन	86	94
3	शिक्षा तथा जनजन सम्बन्धी आवश्यकताएँ	87-89	95-97
4	असाक्षरता प्रश्न	90-91	97-99
5	असाक्षरता शिक्षा तथा स्वाध्याय	95-96	99-101
6	विभिन्न स्तरों पर नामांकन	97	101
7	शिक्षा तथा सेवायुक्ति	98-99	104-105
8	शक्ति अवसरों का समन्वय	100-110	105-110
	(i) विशुद्ध शिक्षा	101-102	106
	(ii) छात्रवृत्तियाँ तथा छात्र महायन्त्रा व अन्य प्रकार	103	106
	(iii) अल्प आयकों के लिए शिक्षा	104	108
	(iv) क्षेत्रीय असाक्षरता	105	109
	(v) शक्तिपादा का शिक्षा	106-109	109-110
	(vi) विद्यार्थी जातियों की शिक्षा	110	110
अध्याय-5			
कुल विद्यार्थी कार्यक्रम		111-174	112-114
1	प्राथमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण	112-120	112-118
	(i) इति शिक्षा	114	113
	(ii) उद्योग व कृषि शिक्षा	115-120	115-118
2	उच्च अध्ययन के अन्दर तथा प्रमुख विश्वविद्यालय	121-124	118-121

	पृष्ठ	पृष्ठ
३ नवीन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय	१२५-१२७	७१-७२
४ विश्वविद्यालयों के मुख्य बताना	१२८-१३५	७२-७६
(i) विश्वविद्यालय स्वाधीनता	१२९-१३०	७३
(ii) विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था	१३१	७३
(iii) उपबुलपति के कार्य तथा उसकी नियुक्ति	१३२	७४
(iv) विश्वविद्यालय के भीतर स्वाधीनता	१३३	७५
(v) विश्वविद्यालयों के लिए कानून	१३४-१३५	७६
५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	१३६-१४०	७७-८०
६ विज्ञान एवं तकनीकी	१४१-१६२	८०-८७
(i) विज्ञान शिक्षा	१४२-१४६	८०-८१
(ii) शैक्षणिक अनुसंधान	१४७-१५१	८२-८३
(iii) राष्ट्रीय विज्ञान नीति	१५२	८३
(iv) कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय	१५३-१५७	८३-८४
(v) इंजीनियरी का शिक्षा	१५८-१६२	८५-८७
७ शैक्षिक ढाँचे का पुनर्गठन	१६३-१६८	८७-८९
८ प्रौढ शिक्षा	१६९-१७१	९०-९१
९ दूर प्रारम्भिक शिक्षा	१७२	९१
१० शैक्षिक भवन	१७३	९१
११ शैक्षिक अनुसंधान	१७४	९३
अध्याय-६		
शैक्षिक आयोजना, प्रशासन तथा वित्त	१७५-२१०	९५-११८
१ शैक्षिक आयोजना	१७६-१७८	९५-९६
२ नियंत्रण प्रणालियाँ	१७९-१८८	९८-१०३
(i) राष्ट्रीय सरकार का कार्य	१८०-१८४	९८-९९
(ii) स्थानीय प्राधिकरणों का कार्य	१८५-१८७	१००-१०२
(iii) निजी प्रयत्नों का कार्य	१८८-१९०	१०३-१०४
३ राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का पुनर्गठन	१९१-१९३	१०४-१०५
(i) शिक्षा मन्त्रालय	१९२	१०४
(ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	१९३	१०५
४ राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का पुनर्गठन	१९४-२०५	१०६-११३
(i) राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन	१९५	१०७

(ii) जिला निम्नस्थान	196	107
(iii) जिला स्तरीय संगठन	197	108
(iv) राज्य जिला मस्थान	198	109
(v) राज्य विद्यालय जिला बाड	199	109
(vi) भारतीय जिला सेवा	200	110
(vii) राज्य निम्न सेवा	201	111
(viii) शक्ति प्रशासन का प्रशासन	202	112
(ix) शक्ति प्रशासन का निमित्त राष्ट्रीय कर्मचारी महाविद्यालय	203	112
(x) जिला निम्न	204	113
(xi) जिला निम्न	205	113
5 शक्ति व्यय	206-210	114-118
(i) जिला पर व्यय (1950-1965)	206	114
(ii) जिला पर व्यय (1966-1985)	207	114
(iii) विगत नति	209-210	115-118
अध्याय-7		
सतत एवं दीर्घकालिक प्रयत्नों की क्रियाविवृति परिणाम	211-215	119-121
1 अध्यायों का वृत्त वृत्त		122
2 विद्यालय पाठ्यक्रम		125
3 जिला म नामांकन (1950-55)		127
4 मस्थान तथा अनुदान		129
5 सार्वजनिक-1 शक्ति व्यय		136
" 2 भारत म (विभिन्न) स्तरों द्वारा जिला पर व्यय		137
" 3 भारत म मस्थान पर आधारित जिला पर व्यय		138
" 4 जिला पर व्यय		139
" 5 भारत म मस्थान पर आधारित जिला पर व्यय		140
" 6 प्रतिष्ठान योग्य बाधित सामान		141
" 7 उच्च जिला म प्रतिष्ठान योग्य बाधित सामान		142

भूमिका

1. जिन्ना का मन्त्र मन्त्र म हा स्वीकार किया जाता रहा है लेकिन जगत् जितना महान् धातु है उनका मनुष्य व उन्नितम म बमो नहीं रहा । जिन्ना पर निम्न धातु व विरम लव लमा मुक्ति जिन्ना तथा लतमम्बो धी धनुमथात का आवश्यकता है जिन्ना लोपा व जावन म जगत्ता धीर धारी लमा म धनिष्ठ सम्यध ॥ । जग व मन्त्रुण विराम की धनिष्ठा, उमके मन्त्राण उन्नित तथा उमका मुक्ता व निण जिन्ना का श्रेय मन्त्र है ।

2 शक्ति पुनर्निर्माण के तीन पक्ष

यदि मन्त्र का मन्त्रवादी, जनताधिन तथा धानुनिर धनान की मांग का पूरा करना है तो मन्त्र म प्रचलित जिन्ना-धरम्या म धूनधून परिवर्तन करन हानि । धननुन जिन्ना म लव लमा धानि की धावग्यता है जो राष्ट्रीय मन्त्रा की धानि व निण धानिध मन्त्राधिर, धानिध तथा मन्त्राधिर धानि का मन्त्र धनो मन् । इस धानि व धानि मन्त्र धन है

—धानिध धानिध जग धानिध धानि का मन्त्र व धानि उन्नित धानिध-धानि लव धानि लमा मे मन्त्र व मन्

—धुगातमक धुगात धानि जिन्ना मन्त्र का धानि किया जाय व धानि लव धानि ॥, निरन्तर उन्नित-धानि है धीर वम म धम धुद्ध धीर म धम धानिध-धानि मन्त्र व धानिध है धीर

—धानि धानिध का धानिध पर धन धीर धन धन की धानिध-धानि व धानिध पर धानिध धानिध का धानिध ।

शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन का रूपान्तरण

३. इन तीन पक्षों में प्रथम पक्ष की प्रमुखता या प्राथमिकता स्पष्ट है। शिक्षा राशाय विज्ञान और सुरक्षा में सीधे सम्बन्ध रखती है। जबकि राज्य उचित धर्मान पर उचित प्रकार का तथा उच्च गुणसम्पन्न शिक्षा की व्यवस्था करे। समग्र ही समस्या का मूलनत्व है क्योंकि शिक्षा का परम्परित व्यवस्था के हर विस्तार के साथ उसमें बहुत परिणाम अपना विशिष्टता में सामने आता है और इन प्रकार शिक्षा का रूपान्तरण अधिक कठिन अधिक गर्वीना होता जाता है। अतएव सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था में रूपान्तरण करना उस रास्ता के जावन तथा आवश्यकताओं में सम्मिलित करना और यह प्रकार हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक अधिक और सामूहिक रूपान्तरण में हम शक्तिशाली साधन बनाता। इस रूप में हमें म किया जा सकता है

—शिक्षा का उत्पादना-मुद्रा बनाकर

—सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता में अनिवृद्धि करके

—समूहों में शिक्षा व्यवस्था में मूल्य अभिव्यक्ति द्वारा

—सूचक एवं शिक्षा के साधनों के पद्धतियों अपनाकर,

—शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य एवं गतिमान बनाकर।

१. शिक्षा के उत्पादनो-मुद्रा बनाना

परम्परागत समाज व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा सामाजिकता एक एक मूल्य के अन्तर्गत वय के निमाण करती है जिनके पाठ्यक्रमों होता है और जिसका मूल्य का एक मूल्य है। लेकिन जो स्वयं अपने हाथों में कार्य करती है। और जिसके लिए हमें एक एक मूल्य बड़े मूल्य के कार्य शिक्षा के लिए जाना जा सके। हमें समझना पड़ता है। दूसरा धारा औद्योगिक समाज व्यवस्था में शिक्षा हमें एक उत्पादना-मुद्रा बनाता है जिसके लिए हमें एक एक मूल्य बनाना पड़ता है और जिसके लिए हमें एक एक मूल्य बनाना पड़ता है। समाज में शिक्षा में विकास होने में राष्ट्रीय मूल्यों का विकास होता है जिसमें एक साधन उपलब्ध होना

हैं जो शिक्षा के विकास में और अधिक महयोग्य हैं। इस प्रकार शिक्षा और उत्पादकता दोनों एक दूसरे का दूसरा दन हुए ऊपर चले जाते हैं। भारतवर्ष में जहाँ एक ओर नागरिकों के जीवन स्तर का उन्नत करना है और दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था का आम तौर पर विस्तार करना है ता इस प्रकार शिक्षा का उत्पादन में सम्बद्ध करना सर्वोच्च प्राथमिकता का वाच्य बन जाता है।

1. हम दृष्टिकोण में निम्नलिखित वाच्यता का विवरण दिया जाता है।

(1) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान

प्राथमिकता हमें बताने की है कि अधिक एक सामूहिक आधार पर विज्ञान शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाय। दृष्टि एक उद्योग में विस्तार तथा राष्ट्रीय स्तरों में वृद्धि औद्योगिकी में प्रगति पर निर्भर करती है। इससे अर्थव्यवस्था में अर्थनियम पर ज्ञात है नये अवधारणाएँ, नए विचार तथा निष्कर्षों का समर्थन हो जाता है और निम्न महत्वपूर्ण में अनुपम की शिक्षा या प्रतिक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। इसलिए विज्ञान-शिक्षा का समूचा शिक्षा का अग्रिम ध्येय बनाया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षा के स्तर में भी सुधार अपेक्षित है ताकि सूत्र शिक्षा का समर्थन की शक्ति बढ़ सके और अधिक नए प्रयोगों का जीवन पर हो तथा विज्ञान सामग्री कुशलतापूर्वक और सम्पूर्ण शिक्षा की माँगों का विकास हो। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि हमारे जीवन एवं समाजी संस्कृति का एक अग्रिम ध्येय बन जायेगी। इसी तरह हम वैज्ञानिक अनुसंधान की परमावश्यकता है जो मुख्यतः उद्योग एवं दृष्टि के विकास का प्रभावित करने वाला है।

(11) कार्यानुभव

विद्यार्थी, घर, कार्यालय, मन आरोग्य या उत्पादन सम्बन्धी किसी भी स्थिति में उत्पादन कार्य में भाग लेने का कार्यानुभव को मिला ले जाना है और हम सभी तरह की सामाजिक शिक्षा का अग्रिम ध्येय समझा जाना चाहिए। इसमें आधुनिक व पारंपरिक दोनों के अन्तर्गत का और हमें एक आधारित सामाजिक व्यवस्था का काम करने में सहायता हो जाना चाहती है। हमें सुझाव है कि हमें प्रकाश करने का सुविधा प्राप्त होगी और सामान्य व नौकरी मिल सकेगी। सुझाव है कि हमें प्रसार उत्पादन को प्रेरित व विज्ञान के उत्पादन का ध्यान रखने का विवेक सामाजिक व्यवस्था के प्रति उच्च सम्मान प्राप्त होगा। अतः और उत्तमता का काम करने की क्षमता

पनपता और ताता पन यह हागा कि आर्थिक उन्नति में महायता मिलनी, और प्रत में बुद्ध ता व्यक्ति और मभूह में सम्बन्ध गहर हान व कारण और बुद्ध पापम्भवग और आमवग में आपता ममभ बटन व कारण सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकगा। छात्रा का आयु व समझ की परिपक्वता का दृष्टिगत रगत हुए बायानुभव का मात्रा व प्रवृत्ति का निश्चित करना हागा इसलिये शिक्षा व एन स्तर में दूसरे स्तर अवका एन बग में दूसरे धन व तिए निर्धारित बायानुभव की मात्रा व प्रवृत्ति में अंतर हागा। सरित यह आवश्यक है कि बायानुभव न रगत आधुनिक औद्योगिक म मर्षा पा हा हा अपितु चरमप्रति मम्भन्न भी हा।

(iii) व्यवसाय व धंधा की शिक्षा

कृषि एवं उद्योग व त्रिण वाग्य व्यक्तिया व निर्माण काय का उद्य प्राथमिकता हो जाय। अत समय समय पर अनुमानित जनवत की आवश्यकतामा का ध्यान में रखा हुए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर धंधा का शिक्षा तथा विवरविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय। उन्त्यान के ममम्भ मगा में विशेषकर कृषि और उद्योग व वायवर्तमा व त्रिण अन्त्यानित व पनायार शिक्षा तथा मति पाठयक्रम का माध्यम से, बहुत बडे पमाने पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। धंधा की शिक्षा व गुणात्मक स्तर का उन्त्या और कृषि में और ता पनिष्ठ सम्बन्ध है तथा एन पर बल दिय जान का आवश्यकता है।

6 सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्रगति

पाठ्याभ्यास और मगर्गिक मण्ड व निर्माण व त्रिण सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का बहुत बडा मन्त्र है हर प्रकार की उन्नति व त्रिण यन पून रगत है। एम उन्नति में सि ता मन्त्ररूपीन वाग द सकगा है। इस दृष्टि में त्रिण वायवर्तमा का विरमिण किया जाता है यह दूसरे प्रकार है

7 राष्ट्रीय चेतना

पाठ्याभ्यास व धनयन एम प्रकार व विशेष प्रयत्न रिय जाये कि पाठ्याभ्यास का विरमण हो। हमारा माध्यमिक पाठ्या व प्रति उन्नित योग्य का पाठ्या उन्नित हो एवं त्रिण प्रकार व महात् महिष्य का हम अपन त्रिण निर्माण कर सका। उमर प्रति हमम शिक्षात्मक एवं निष्ठा जागृत हा। यह त्रिण रगत है जब माध्यमिक धन धम माध्यमिक शिक्षा व पाठ्याभ्यास और माध्यमिक पाठ्याभ्यास मूर्तिता विरमण मगा और और माध्यमिक

आदि की सुगति रूप में शिक्षा दी जाय। 'मन' अतिरिक्त प्रत्येक छात्र का उसकी आयु एवं परिपक्वता व अनुस्यू नागरिकता का एकी शिक्षा दी जाय, जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता मन्त्रालय मन्त्रालय सविधान की प्रस्तावना में उन्निमित्त महात्माने मानव मूल्य, जिस प्रकार व नागरिक एवं समाजवादी समाज का रचना करना हम चाहते हैं उसकी प्रवृत्ति, दत्त व समग्र मानवानी विविध अन्वयाने तथा दोषनालेन समझाए उनका अस्थायी निम्न तथा राष्ट्रीय विचार में सम्मिलित पञ्चर्षीय योजनाओं द्वारा विषयों का अध्ययन सम्मिलित किया जा सके। मन्त्रालय में मन्त्रिण रहें ता उपर्युक्त कार्यक्रम का अन्तराष्ट्रीय सद्भाव में तथा सम्पूर्ण मानवजाति व प्रति पृथ्वी शिक्षा से सामञ्जस्य रहता जिन पर भी हम विचार कर देने की आवश्यकता है।

६ सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सेवा

विभी न विभी प्रकार का सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। एमो नेत्र हर स्तर की शिक्षा का अनिवार्य अंग है। विद्यार्थ्य तथा महाविद्यार्थ्य में समुदाय रूप में रहना तथा सामुदायिक सेवा अथवा राष्ट्रीय पुनर्रचना का मायका व पुनीतीपूर्ण गति विधियाँ में भाग लेना छात्रों कायक्रम सामाजिक सेवा अथवा राष्ट्रीय सेवा व अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह कार्यक्रम का उद्देश्य होगा—उचित उपायों द्वारा समाज सेवा पर विचार दत्त देने हुए समाज और विद्यार्थ्य व छात्र अन्तिम सम्बन्ध स्थापित करना। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर यह उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है। प्रथम माध्यमिक विद्यालय का प्रास्ताविक किया जाय कि वह समाज में अन्तिम सम्बन्ध स्थापित कर तथा समाज-सेवा में सम्मिलित हम समुचित कार्यक्रम बनाव जिसमें छात्रों के छात्र भाग ले सकें। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ कुछ माध्यमिक विद्यालयों में समूह के लिए सामाजिक सेवा एक श्रम विहारा की वृत्तीय रूप में व्यवस्था का जाय और व अनिवार्य होना चाहिए कि निम्न माध्यमिक शिक्षा-स्तर का प्रवेश छात्र कम से कम 30 दिन तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर का छात्र 20 दिन इन विहारा में व्यतान कर। विशेषविद्यार्थ्य स्तर पर यह कार्यक्रम एक या दो का विवक्षित है। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक मर्यादा का यह दान के लिए प्रास्ताविक किया जाय कि यह समाज और उनका उपयुक्त अथवा अलग सेवा कार्यक्रमों का विवक्षित कर। लेकिन जहाँ यह सम्भव न हो ता वहाँ प्रत्येक छात्र के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह अपनी प्रथम रचनाओं जाति द्वारा करने के पूर्व शिक्षा

क्याय रूप में मंचानित किमी सामाजिक एवं धर्म विधिर में कम से कम 60 दिन व्यतीत करे। इस प्रकार कार्यक्रम में राष्ट्रीय तन्त्रों के विचारों में समिवृद्धि होना होगा। इसमें माय माय जापस्थ श्रेणियों के लोगों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा होगी और जन सेवा के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी।

॥ जन विद्यालय प्रणाली (वॉमन स्कूल सिस्टम)

एक समय शिक्षा व्यवस्था में जो कम भूत चल रहा है उस अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए। आज एक धार मजबूत स्थिति अपने अपने बान्धवों का एक अल्पमध्यम शिक्षा (प्रोवेट) विद्यालयों में पढ़ने का भजन है जो अधिकांशतः धनवान् वर्ग है और अल्पमध्यम वर्ग के बन्धु-स्वन्तर्गत है। जबकि दूसरी धार बहुमध्यम जनसमूहों का अपने बान्धवों का एक विद्यालयों में अध्ययन हेतु भर्त्ता पड़ता है जो मजबूत द्वारा तैयार ज्ञान है और जहाँ बाद गुल्म (अथवा पुनरावर्तन) दृष्टिकोण में सामान्य का गुल्म नहीं दिया जाता। तबिन जितना स्तर बहुत गिरा हुआ जाता है। अतएव शिक्षा नीति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह जन शिक्षा का एक जन विद्यालयों की व्यवस्था करे।

—जहाँ जहाँ धन-मजबूत धर्म आधारित शिक्षा अथवा सामाजिक स्तर का एक भाव का बिना समी प्रकाश का दशा का लिए प्रकाश तत्ता मजबूत हो गई,

—जहाँ अधिकांश शिक्षा प्राप्त करने का लिए धन या धन का तत्ता अधिकांश सामान्यता का आधार माना जाय

—जितना किमी प्रकार का शिक्षक गुल्म में दिया जाय और

—जिसमें अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय धार्मिक स्तर का बताया गये गये तथा एक उचित अनुपात में तत्ता अधिकांश एक अल्पमध्यम मजबूत पदों में कि सामान्य समीभावित अपने बान्धवों का अधिकांश विद्यालयों में भजन का आधारकता अनुभव हो न करे।

10) यथासंभव शीघ्र पन्ना विद्यालय (नवम्बर १९५०) का धारणा का विचारमजबूत दिया जाय सामान्य धर्म है कि एक निश्चित पन्ना का धारणा उचित लिए बन हुआ विद्यालय में अध्ययन करने का लिए जाये। एक व्यवस्था का धारण्य में प्राथमिक और मजबूत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लागू किया जाय। सामान्य लोगों का भाव एक प्रकार जावन का धर्म कर जाता एक अधिकांश शिक्षा का धर्म है। एक अधिकांश एक व्यवस्था का अन्तर्गत धर्म मुक्तिधर्म तथा — अधिकांश धर्म का सामान्य धर्म विद्यालयों की व्यवस्था

म दक्षि तन व निह आध्य हा जायेंगे । इस प्रकार भीम सुधार सम्भव हा मरणा ।

11 शिक्षा की जनविद्यालय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अङ्ग यह भी है कि सरकारी महायन्त्र प्राप्त सम्पत्ति शिक्षण मन्त्रालय (जिनमें स्वतन्त्र या अर्धस्वतन्त्र प्राप्त विद्यालयों के अनिवार्य सभी शिक्षण संस्थाएँ सम्मिलित हैं) का उनका प्रबन्ध किया भी प्रकार का कभी न हो, शिक्षा में एका कुट्ट निश्चित समान विषयताएँ हा जो 'पूततम स्तर का बनाय रण मक्' । इस समय इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । प्रबन्ध के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में एक प्रकार की बग व्यवस्था प्रचलित है । राजकीय शिक्षण संस्थाओं में सम्भवतः अध्यापकों के लिए सर्वोत्तम सेवा सम्बन्धी शर्तें प्राप्त हैं । सुतन्त्रतात्मक दृष्टिकोण में दणों का उनका आर्थिक साधन भी उत्तरदायकतापूर्ण उपाय है, लेकिन सेवा की अधिकतम सुरक्षा तथा स्थानांतरण (जिसे कारण व संस्था के प्रति नया श्रेणी के प्रति निष्ठावान रहन है) समुदाय में जीवन सम्बन्धी के अभाव तथा स्वतन्त्रता पर कुछ प्रतिबंधों के कारण यह एक प्रकार में बन्धनमय है । स्थानीय स्वायत्त शिक्षण संस्थाओं में यह सब कटिनाद्यों का है जो इनके अतिरिक्त स्थानीय राजनीति के कारण अध्यापकों को मिलनसारता सेवा सुविधाओं की अभावजनक हानी हैं । अतः निजा विद्यालय यात्रा एवं निष्ठावान अध्यापकों का आकर्षित कर सकते हैं समाज अथवा समुदाय से अनिष्ट सम्बन्ध बनाय रण मक्न हैं तथा वे अपनी स्वतन्त्रता भी बनाय रण मक्न हैं । लेकिन उनका आर्थिक आधार निम्न होता है जो राजकीय विद्यालयों में नहीं होता । एक अधिनाज विद्यालयों में इस प्रकार का अभाव कटिनाद्यों की हानी है—अध्यापकों के लिए अथवा सर्वोत्तम सेवा सम्बन्धी शर्तें तथा शिक्षा में अधिकतम प्रबन्ध । इन जीवन सम्मानताओं का दूर करने की आवश्यकता है । प्रबन्ध काट कने हा हा, इन सम्पत्ति संस्थाओं में कुछ समान विषयताएँ निर्मित करने की आवश्यकता है—यथा अध्यापकों के समान स्तर समान कीम प्रवेश सम्बन्धी समान नीति जिसमें बग नद समाप्त हा और यात्राओं के आधार पर सभी शारीरिक संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा हा स्थानांतरण समुदाय में सम्पूर्ण नवान विषयों अन्तर्गत तथा प्रयोग करने की स्वतन्त्रता ।

12 अंतर्राज्यीय सद्भाव

शिक्षा का एक प्रयत्न होता था कि वह भाग्य के विभिन्न भागों में एक दूसरे के विषय में अधि जागरण अधि सद्भाव और अधि योग्य पूर्ण भाग्यपूर्ण का निर्माण हा नया अगर रिश्तेदार का कर । यह वाप

उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दस वर्षीय श्रमिक नायक (केजट प्रोग्राम) बनाया जाय तथा आवश्यक माहित्य के निर्माण-कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाय । उद्धृष्ट शोचनीय भाषा नहीं है, इसे उचित प्रास्तावक दिया जाना चाहिए । ग्रह-नी रोमा में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित ऐसी समस्याएँ हैं, जो हिन्दी का माध्यम भाषा के रूप में अपनाता चाहती हैं, उन्हें भी उचित प्रास्तावक दिया जाना चाहिए ।

10 मूल्य अनुस्थापन (वैल्य ऑरियन्टेशन)

चरित्र निर्माण शिक्षा का सदा से ही महत्वपूर्ण प्रयोजन रहा है । महत्त्व धातुनिर्माण समाज में और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि धातुनिक समाज का कुशलक्षेम ऐसे व्यक्तियों का अभिप्रेरणा पर आधारित है जो जीवनयापन का गहराई से परिचित रहें हैं तथा जिनके समग्र जितनी विभिन्न दृष्टियों में से भाव्य बरतन की स्वतन्त्रता है जितनी भूतकाल के श्रमों में समय में नहीं थी । वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का मुख्य प्रयोजन ज्ञान देना है । मुख्यतः ज्ञान पर ही सारा ध्यान केन्द्रित करने वाली वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत इस महत्त्वपूर्ण प्रयोजन पर दुर्भाग्य से कम ही ध्यान दिया गया है । अतएव यह आवश्यक है कि इस शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था में जीवन मूल्यों का अनुस्थापन किया जाय तथा उभरती हुई पानी में नतिर, सामाजिक और भाषात्मक मूल्यों को स्थान दिया जाय ।

11 जन्म में कुछ आवश्यक मूल्यों को पहचानना ही गिनता जा चुका है जिनमें मानविक मानविक स्वभाव तथा विभिन्न गैरमानविक—धातुनिक विश्व में रहने बहुत महत्ता प्राप्त कर चुकी है, शारीरिक श्रम के प्रति आदर तथा लक्ष्य प्रतिन लक्ष्य उत्तरदायी कार्य करने की क्षमता जो उत्पादन में वृद्धि कर, धनता सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और समाज सेवा की भावना के प्रति लगाव तथा विद्यमान जिनमें नि सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि है । एक मूल्य भी समाज रूप में ही महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक जीवन यापन के तराज के रूप में विभिन्न कर सबों और अन्य प्रकार के (सार्वजनिक) मानव प्रणाली के रूप में मा समर्थन देना मनें, जिस दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान के लिए सर्व तत्पर रहना, विचार विमर्श सम्मानना पुमाना, सम्मोक्षा तथा एक ही कार्य शक्तिपूर्ण उपायों में जगता को तय करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना, तथा दूसरे सामाजिक समुदाय की समृद्धि का सम्मान और उसका आदर करना । हमारे गवर्णमेंट की प्रस्तावना के अनुसार हम व्यक्ति का महानता स्वीकृति तथा सम्मानना एक साथ सम्बन्धी मूल्यों

मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे परम्पारित महान् मूल्य भा समान रूप से ही महत्वपूर्ण हैं, जसे नि स्वायत्ता वतव्यपरायणता, सहिष्णुता शातिप्रियता तथा जीवमात्र के प्रति सम्मान। अथ मूल्य भी बनाये जा सकते हैं। लेकिन उन सबका यद्वा विस्तार देना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही। हम मन्दम म तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान में रखा जाना चाहिए—पहला इन मूल्यों का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमों में सम्मिलित करना तथा विद्यार्थियों के वातावरण एवं अध्यापकों के व्यवहार और उनके व्यक्तित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अभिवृद्धि करना। दूसरा यह याद दिलाना है कि विविष्ट प्रकार के प्रत्यक्ष दिशा निर्देश तथा महानिर्देशों के उपयोग के बाद म हमें प्रयत्न की महत्ता मिले। तीसरा, इन मूल्यों का प्रवर्धन करने के लिए जो प्रयत्न किये जायें उनमें हम अपनी परम्परा के सत्त्विक की आवश्यकतानुसार पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन करें तथा दूसरे दशा में हम प्रकार के जो उद्धारक मूल्य प्रयत्न हुए हैं उनका भी लाभ लें, उदाहरणार्थ काम की राखरक्षात्मक भावना का दान तथा समाजवाद का उद्धार। हम प्रकार के सतुलनशील प्रभाव का उन क्षेत्रों में और भी विशिष्ट महत्व है जहाँ भारतीय परम्परा अपनाहुन गायन नहीं रहा है जग समानता तथा सामाजिक न्याय का क्षेत्र।

19 शिक्षण तथा मूल्यांकन की आधुनिक विधियाँ

आधुनिक तथा परम्पारित शिक्षा-व्यवस्था में एवं महत्वपूर्ण अंतर उनका शिक्षण तथा मूल्यांकन का रीति का अंतर है। परम्पारित समाज में ज्ञान का वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। अतएव धीरे-धीरे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बना बनाया या गढ़ा हुआ व्यक्तित्व निर्मित करना। सुख के जीवन यात्रा का स्पष्ट मानचित्र दे देना शांति का परिष्कार करना तथा आत्मपरात्मता या गजनात्मता गतिविधि के विकास का अपना ज्ञान का स्मरण करने की प्रवृत्ति गमना ज्ञान के प्रति मान सम्मान प्रवृत्ति करना तथा उस पक्ष का ध्यान धारण करना पर विचार करना। प्रचलित व्यवस्था में शिक्षण पद्धति तथा मूल्यांकन के द्वारा हमें का अनुसरण होता है। मरित आधुनिक समाज में ज्ञान का वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तेज होता है। अतएव शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता चाहिए उचित रीति में अभिवृद्धि तथा मूल्यों का निर्माण करना न कि बना बनाया या गढ़ा हुआ व्यक्तित्व पैदा करना। सुख के जीवन-यात्रा के लिए शिक्षा मूल्य के द्वारा न कि मानचित्र, ज्ञान का

परिदल ही नही उमम वृद्धि भी करना । अतएव शिक्षण की ऐसी आधुनिक पद्धति (मूल्यांकन की तत्सम्बन्धी तकनीक के साथ साथ) का उपयोग करना आवश्यक है जो जिज्ञासा वृत्ति के प्राप्तादन, अध्ययनप्रियता, स्वाध्याय की भावना, चिन्तन व स्वयं निरूपण की क्षमता एवं समस्या निदान की क्षमता का विशेष महत्त्व देनी हो । अध्ययन के क्षेत्र में यह वांछित और उमका उसा मूल्यांकन ही हमारी नयी शिक्षा-व्यवस्था की मूल आवश्यकताएँ हैं तथा मही व मूल तत्त्व हैं, जो आधुनिकीकरण की गति का तीव्र करेंगे ।

19 मुख्य समस्या है शिक्षण तथा मूल्यांकन की ऐसी नयी पद्धतियाँ के आवरण तथा प्रचार प्रसार करने का, जो बच्चा में शिक्षण राय को आधुनिक रूप प्रदान करें । इसका सतोषप्रद निदान कई कारणों पर निर्भर करता है, जो अध्यापक की स्तन-व्रता तथा उनकी क्षमता, अनुभव-बोध का विकास सुचारु के लिए सामान्य साक्षात्करण को बनाय रचना, प्रशामन की भाँ में महत्वा तथा गन्तुभूति, साथ करने के लिए सनापप्रद परिस्थितियाँ तथा प्रभावकारी शिक्षण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धि । यह भी ध्यान में रचना है कि बच्चा में क्या जान वाद अध्यापक अभी भी विज्ञान स्तर पर नही अपनाय जान और न ही समा अध्यापक तथा विज्ञान एव एव हाकर प्रगति में और बढ़ने ही हैं । शिक्षण मृजन के लिए उपयुक्त क्षेत्र की आवश्यकता की बजाय सेवा सुरक्षा का अधि महत्त्व न वात, कमजोर एवं सामान्य शिक्षक ना उम मनायता का स्वागत करेंगे, जो उह विस्तृत पाठ्यचर्या तथा पुस्तक परीक्षाओं में बार-बार हान जाने निरोधता तथा सुधारिमापित नियमों में प्राप्त हान वाता है । सर्वत्र यह मव्येष्ट शिक्षा की विभागीय विनिर्दिष्ट नियमों से हटकर वाय करने के लिए स्वैच्छिक, प्रामाण्य तथा महत्वा नही लिया जाना, ना उनका शिक्षण-वाय में एक तरह में बाधा ही उत्पन्न हागा । अत मूल वात यह है कि एवं समा वायवम अपनाया जाय जो उचितोता है तथा जिसके अंतर्गत मन्त्रे विद्यालय और अन्त्रे अध्यापक का प्रगति करने के पर्याप्त प्रसार मनुम हा एवं निबन्ध मस्यामा तथा यत्तिता का सुचारु कर करने की शिक्षा में आवश्यक महत्वाय भी प्राप्त हा ।

20 इस सन्दर्भ में ही और विदुषा पर ध्यान देने की आवश्यकता है । पाता हा यह है कि मूल्यांकन और शिक्षण की नयी तकनीक व प्रचार प्रसार की गति बहुत तीव्र हा, अर्थात् दूसरे मन्त्रा में उद्घाटनीय समस्याओं द्वारा नयी स्तरों पर प्रथम बार अपनाये जान व मध्यम गुणों पर अध्यापकता इससे अत्यंत पर्याप्त व विज्ञान तर व बीज का समय मूलनम हा । दूसरे यह मानना

गतन हाया रि तबनीत म यह मुधार हमसा ब निण हा गया, यम्तुन इमरे
गान् पुननवावरण वा भावयवता है। बार्द 'प्रगति'गीत धारणा सम्पूर्ण
गिगा-म्यवस्था म साम्राय रूप से अपनार्द जाने याग्य वनेती है। इसत पूव ही
यह एत प्रसार की नया 'दृष्टि' का रूप धारण कर लेती है अथवा गान म
अभिगृष्टि या सामाजिक परिवर्तन ब धारण उमरी मुगमति नष्ट हा युका
हाती है। अगतिन कुछ अर्थ अधिक प्रगतिज्ञात तबनीत ब सन्ध म उस
सम्पूर्ण प्रगति का फिर दाहरना हाता है। यह एत अपरिहाय नया शासन
ममत्या है जिगसा सामना शिक्षा का करना है।

21 लघुलिपयन तथा गतिशीलता

इसने लिए आवश्यकता है एक सच्चाती तथा गतिज्ञान शिक्षा व्यवस्था की। विगत एक आधुनिक समाज में तो अवश्य ही जहाँ नात व विस्फोट व साथ-साथ समाज का गति स परिवर्तित हो रहा है। परम्परागत समाज में एक बार जैसे जमा लेने वाली शिक्षा व्यवस्था यहाँ हो रहा है। सचिया तो प्रभावशाली रह सकती थी। अब यह सम्भव नहीं है और आज व समाज में जहाँ एक तीर स भविष्य के बारे में कह सकना निश्चिन्त नहीं है वहीं एक मात्र अवसर निश्चित है कि भूतनाम का शिक्षा व्यवस्था वनमात की आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर सकना और भविष्य का आवश्यकताओं की तादिकुन रही। अब आवश्यकता है कि वनमात व्यवस्था की गठार स्थिति में पुनरावृत्ति प्राप्त किया जाय, सच्चापन तथा गतिज्ञानता का महत्व दिया जाय और इस शिक्षा व्यवस्था व भीतर एक एकी काय पद्धति का जन्म दिया जाय जो परिवर्तित परिस्थितियों में सगलान्तर सामञ्जस्य स्थापित करती रहे।

[illegible]

२५ गमना क्षमा म गमना क्षमा पर गमना प्रताप क क्षमिन् क्षम्यमाना म

तबोलैयन तथा गतिशीलता का व्याप्त हो जाना होगा। उदाहरणार्थ सभी क्षेत्रों के विद्यालय तथा महाविद्यालयों की कक्षाओं के स्वरूप में अभ्यास एकरूपता पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप विकास कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने की पर्याप्त छूट दी जानी चाहिए। पाठ्यचर्या में विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं की विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए। इन पाठ्यचर्याओं की नवीनतम जानकारी का समावेश कर अक्सर संशोधित किया जाता रहना चाहिए। विषय अथवा विषय समूह का निर्वाचन एक किंवा एक प्रकार या श्रेणी से दूसरे प्रकार या श्रेणी के विद्यार्थी वर्गों के लिए आज जितनी आवश्यकता उपलब्ध है, उससे बड़ी अधिक स्वनियंत्रण दी जानी चाहिए। यह भी सम्भव होना चाहिए कि प्रत्येक शैक्षणिक समस्या को एक व्यक्तित्व समझा जाय, जिस इस बात की छूट हो कि वह अपनी तुल्य की विसा विशिष्टता में जो कुछ उसकी अपनी बढ़िया रचना है, उसमें उन्नति कर सके। स्पष्ट है कि हमें परिवर्तन और सुधार सभी सम्भव हैं जबकि—

- अध्यापक तथा शैक्षणिक प्रशासक सतत हो अपने क्षेत्र के सवानतम विकास से परिचित हों और अनुसंधान एवं निरंतर मूल्यांकन में रूचि रखते हों।
- सामान्य वातावरण प्रयोग व पहन का प्रवृत्ति तथा गृहनिर्माणता को समिष्ट बनाना हो।
- प्रशासन का इस तरह विकसित हो गया हो कि विचारों का प्रभावी उन्नति सम्भव हो सके।

गुणात्मक सुधार

24 ऊपर बताया गया तराका में शिक्षा प्रणाली में धार्मिक परिवर्तन लाने तथा उसे लोगों की आवश्यकताओं या भावनाओं के जीवन में धर्मिक रूप में सम्मिलित करने के प्रयत्नों के साथ साथ यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में समान स्तर पर शिक्षा के मानक या स्तर पर्याप्त रूप से ऊँचे उठें और लगातार उन्नतिशील बने रहें तथा कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे भी क्षेत्र हों जिनमें ये अनर्गलक्ष्य मुनाबिले में भी लगे हो सकें।

25 यह एक सामान्य शिक्षागत रहा है कि मुख्यतः हमारे गरीब क्षेत्रों में शिक्षा विकास की सुविधाओं में सीखने की क्षमता के परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर गिरा है। उदाहरणार्थ, मुख्यतः दोषपूर्ण प्रायोगिक तथा प्रायोगिक साधनों के अभाव के कारण निम्नस्तरीय स्थापनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आयी है क्योंकि तात्कालिक शिक्षा की अवधि में प्रवेश संख्या की वृद्धि के अनुपात में अच्छे अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं होती और निम्नस्तरीय उपलब्धियाँ देने विद्यापिथों की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है। हालाँकि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पाठ्य सामग्री के विद्यार्थियों हेतु ध्यान के कारण सामाजिक भाव की दृष्टि में स्वाकारणिक व्यवहार की अपेक्षा रम्य हैं। शिक्षा में शिक्षा की अवधि में लगे होना आवश्यक है और सामाजिक भाव के दृष्टि कारण में इनके कुछ लाभ भी हैं। दूसरी ओर विविधता अपेक्षा इन्जीनियरिंग में व्यवसाय तथा मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शिक्षा के स्तर में घटिवृद्धि हुई है। इनके अनिश्चित अर्थों में संभाव्य एवं वरदान प्राप्त अब अधिकांश संख्या में हैं और गुणवत्ता स्तर में गिरावट पड़ने के साथ ही उनमें ध्यान भी है यद्यपि अधिकांश अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार हमारे सामने शिक्षा का जो चित्र है वह उज्ज्वल भी है अंधेरा भी है यद्यपि स्तर का उन्नत करने का सपना तथा सीखने की अवसरों को बनाना बनाना नहीं है जो हमें उठाने का सपना होगा यदि हम गरीब क्षेत्रों की गुणात्मक उन्नति के लिए समुचित कार्य में उठना कर दें क्योंकि यह ही हमें सक्षम बनाएगा जो सामान्य जीवन में सम्पूर्ण प्रभाव करेगा।

26 शिक्षा का पुनर्बना के सम्बन्ध में मूल प्रश्न यह पड़ता है कि क्या हम मानक तिर रहे हैं अथवा उन्नत हो रहे हैं और यह हमें दंगना है कि वह पर्याप्त है कि नहीं। निश्चित है कि नहीं तथा अनर्गलक्ष्य आधार पर

तुलनीय है कि नहीं। इहीं महत्वपूर्ण मापदण्डों के अनुसार उन्हें जीवन की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित मानक इस कार्य को करने के लिए उन्हें प्रयुक्त किया जाना है। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि यदि वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं का भलिभांति उपयोग किया जाता, तो ये मानक कहीं अधिक अच्छे हो जाते। जहाँ मानक में उन्नति हुई भी है उनकी गति औद्योगिक देशों के विकास में अनुपम नहीं रही है। परिणाम यह हुआ कि उनका धीरे-धीरे मानक के बीच गति बीच वर्षों में खड़ी चोड़ी हुई है। अतएव शिक्षा नीति का प्रयोजन यह होना चाहिए कि वह गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों को महत्व दे ताकि उपलब्ध सुविधाओं के स्तर के अनुरूप यथासम्भव श्रेष्ठ मानक स्थापित हो सकें जिन कार्यों के लिए उन्हें नियमित किया गया है, उनके लिए व उत्तरोत्तर उठते हुए स्तर की अपेक्षा करता है उसने अनुरूप में बढ़ते रहे कम से कम उन मुख्य क्षेत्रों में जहाँ तुलना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वहाँ 27 नीचे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें

गिना में मानक के सुधार के लिए विकसित किया जाना चाहिए—

- सुविधाओं का समुचित उपयोग,
- शिक्षकों की गुणात्मकता, क्षमता तथा उनका चरित्र,
- पाठ्यचर्या में सुधार तथा पाठ्यक्रम का पुनर्गठन,
- पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मकता सुधार तथा उनका नि:शुल्क वितरण
- अथवा पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण
- प्राप्ति प्रणाली में सुधार,
- शिक्षक संस्थानों में आकार तथा उनकी स्थिति के सम्बन्ध में उचित आयोजना,
- आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था,
- छात्र-सेवाओं की व्यवस्था
- प्रशिक्षणों का अन्वेषण एवं विकास,
- शिक्षा में राष्ट्रव्यापी सुधार और कार्यक्रम का गठन
- सुनिश्चित संस्थाओं का अधिकतम सीमा तक अथवा भाग-दशक के रूप में उनका विकास करना, और
- परिष्कारण में सुधार करना।

28

सुविधाओं का सघन उपयोग

जिन मसल तत्वों पर मानक निर्भर करते हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपूर्ति के बिना श्रम तथा निष्ठा के वातावरण में निर्माण के साथ साथ प्रचलित सुविधाओं का सघन उपयोग करना। स्वयं तीव्रतापूर्वक चलने वाली विचारों की निष्ठा भावनाओं के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम वर्तमान

निविष्ट स्तर में कुशलता की सुधारा जाय। उपलब्ध सुविधाया का अधिकतम मोमा तब उपयोग किया जिना ही यदि उनमें और वृद्धि करदी जाती है। यह मात्र अपेक्ष्य हो हागा, जो निघन तथा विकासशील राष्ट्र शायद। वर्गीकृत कर पायें।

29 इस दृष्टिकोण से कई उपायों को अपनाना होगा। पहला। भारतीय छुट्टियों की संख्या तथा परीक्षाओं के बारम्बार अध्यापन दिवसों व हानि का कम करना तथा काय शिक्षा की संख्या में वृद्धि करना (विद्यालय में वर्ष में 216 तथा महाविद्यालयों में वर्ष में 216 अध्यापन दिवस से कम है)। काय शिक्षा की अवधि लम्बी हो। पाठ्यचर्चा तथा पाठ्य सामग्री का समुचित गठन द्वारा अवरोधकों का पूरा उपयोग किया जाय। ऐसे भावना पैदा की जाय कि शिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थियों की तरह हैं जिन्हें कामों से बचाना ही रखा जाना चाहिए—जैसे पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि। वर्ष भर और एक दिन में अधिक नहीं तो कम से कम आठ घण्टे तक खुला रहें। स्वाध्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण के 'समय' बानाओं की धारण के कुल काय भार घटने हुए अनुपात में व्यवस्था की जाय। शिक्षा के भारतीय स्तर पर सम्यक बानाओं की संख्या अधिक है तथा जमे जमे कई धारण उच्च स्तर प्राप्त करता जाय सम्यक बानाओं का संस्था घटती जाय। उदाहरण के लिए स्नानरूपक स्तर पर कुछ काय भार के एक तिहाई या एक चौथा सम्यक बाना है तथा स्नानरूपक स्तर अधिमान स्वच्छताय हेतु निर्धारित है। इन प्रयासों (सर्वाङ्ग अध्यापन अध्ययन वृत्त पुस्तकालय प्रयोगशाला आधुनिक भारतीय साहित्य निर्माण जिसमें आधुनिक भारत भाषाया में पाठ्य पुस्तकालय सम्पूर्ण साहित्य के निर्माण का सम्मिलित है आदि) को उच्च प्राथमिकता दी जाय।

30 अध्यापक

विभिन्न स्तरों का शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हैं उनमें अध्यापक का स्तर उसकी क्षमता तथा उसका चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव यह ध्यानरक्ष है कि प्रतिक्रिया विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापन गमाप्त करने निश्चयने माने कुशल वृद्धि तथा एक मुक्तिपूर्ण के महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा का शिक्षण-वृत्ति के क्षेत्र में धारणित करने के लिए मन्त्र महरे प्रयत्न किए जाने रहें तथा उन्हें निदानान उपायों तथा समुचित कायकर्तों के रूप में समर्थ रणों के लिए धारणित काम उपायें जायें। इस प्रयासों का उपाय के लिए अनिवार्य है कि हर स्तर पर अध्यापकों का परीक्षा मान्यता पत्रोपस्थिति के अधिनियम के समर्थ मान तथा वृत्ति प्रतिज्ञा के अवसर एक कायों तथा तथा-सम्बन्धी गणितज्ञान के क्षेत्रों की सुविधा हो।

अध्यापक। व लिए एसा व्यवस्था भी है कि व अपने बतनत्रम की अधिवनम सोमा का निर्धारित समय से कम समय में ही प्राप्त करेंगे ।

1967-68 के भूतय स्तर को आधार मानकर अध्यापक व निमित्त निम्नित बतनत्रम का परिशिष्ट 1 में विवरण दिया गया है । राज्य सरकारें यह कार्यविन कर मई दसविए आवश्यक है कि वे उन्तरनापूर्वक प्राधिक साहायता दे ।

32 आय लाभ

अध्यापक के लिए बतयाएल सेवाभा का विनिमित्त दिया जाय । सरकार एवं अध्यापक समुत्त रूप से इसमें हाथ बतयें तथा विभाग एवं अध्यापक व प्रतिनिधि समुत्त रूप से ही इसका कार्य संचालन करें ।

सका निवृत्ति की आयु 60 बय है तथा याय्य व्यक्तिया व मामला में 65 बय तक की आयु का प्रावधान है ।

समस्त राज्य कमचारिया तथा अध्यापक व लिए सेवा निवृत्ति व समद मितन घात लाभ व सम्प्रचित व्ययका एवं समान है । अन्तर्भासी उपाय य है भवता है कि त्रिगुणाय लाभ याजता का विमान पमा पर समानार दिया जाय अविव्य निरि व रूप में तथा पूजा पर व्याज की दर में समुचित वृद्धि का जाय और यह याजता व संचालन की विधि का बहिया बनाव जाय ।

एक याजता एसी भी बनाव जाय त्रिगुण अन्तगत अध्यापक व नागतय व रिगी भा निग में ता व लिए तीन बय में एक बार रिपायता रतय नाम मि । इससे लिए उम अपने बतन व उचित अनुगत में ही पता मुताता रहे ।

प्रयत स्तर व विगत मगारिघातया तथा विस्त्रविघातया व अध्यापक व लिए आराम स्थाना में पयान वृद्धि करा व प्रयत दिय जायें ।

निगता का राष्ट्राय एक स्न का याजता में रिगार दिया जाय तथा सम्य सम्प्रित प्रमाता का ठार कर में बतया जाय ।

1. बाय लय सेवा सम्प्रधी गने

अध्यापक व बाय लय सेवा सम्प्रधी गनों में मुत्तार दिया जाता बाह्य या मन्तारा स्थाना प्राधिकरण निमित्त तथा निता मरयादा व अध्यापक व लिए एक है ।

अध्यापना की शक्ति स्वतन्त्रता की पर्याप्त सुरक्षा हो तथा व उन जमस्त नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकें जिनके अन्तर्गत चुनावों में भाग लेना भी शामिल है तबिन सभी सामान्य परिणामों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए जा तबिन आम अमरिका जन नीतान्त्रिक राष्ट्रा में विस्तृत हुई हैं।

अध्यापकों के माहिरों की प्रोत्साहन तथा माहिरों का जाय और उन्हें हम तरफ का अधिकार भी है कि जिनमें विद्यालय शिक्षा सामान्य तथा अध्यापना की वृत्ति में शिक्षा एवं उनका बनन तथा बाय एवं सेवा सम्बन्धी शर्तों में सम्बन्धित मामलों पर उनका राय भी जा सक।

प्रत्येक राज्य में शिक्षा मन्त्रि की अध्यापना में समुक्त अध्यापक परिषद् का स्थापना की जाय जिनमें अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधि तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल ह। बाय तथा सेवा में सम्बन्धित सभी मामलों इन परिषद् का सीमा और बाय क्षेत्र के अन्तर्गत ह। य परिषद् परामर्श उन बायी परिषद् हायी तबिन उनकी बढती में लिए जान बाय निगमों का साधारणतया स्वाकार किया जाय तथा बनन एवं मत और बाय के घण्टा तथा छुट्टी के मामलों में सम्बन्धित निगमों का पूर्ण अधिकार प्रशासन का ह।

3। व्यावसायिक तयारी

अध्यापकों का व्यावसायिक तयारी में सम्बन्धित कुछ मुख्य बायक्रम निम्नांकित हैं जिन्हें शक्ति पुनरचना के अन्तर्गत सूच क्षेत्र समझा जाना चाहिए।

(1) प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुका ह। तथा दा बाय का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त ह। प्रवर माध्यमिक विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक उक्त विषय का स्नातक ह जो विषय उक्त पढ़ान को दिया जान बाता है तथा जिनमें उनका लक्ष्य-वर्षों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया ह। सम्बन्धित महाविद्यालय के कनिष्ठ व्यावसायिकों की जो बायनाएँ हती हैं वे बायनाएँ प्रवर माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की हानी चाहिये गया हम बाय ह। प्रशिक्षण प्राप्त ह।

समस्त उक्त प्राथमिक विद्यालयों में गया 200 या 200 से अधिक अधिकारों बाय बड़े प्रवर प्राथमिक विद्यालयों (साधारण प्राथमिक स्कूलों)

के प्रधानाध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हैं। इसी तरह भवर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के अध्यापकों का एक निश्चित अनुपात उतनी माध्यता का हो और उनी वेतनक्रम में वाय कर रहा हो, जितने उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्यापक।

समस्त विद्यालयों में इतनी या इमने अधिक माध्यता के अध्यापकों का पूर्ण परत के लिए सामान्य शिक्षा की सुविधाओं मुख्यतः स्नातकोत्तर स्तर के लिए तथा वृत्तिगत प्रशिक्षण की सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार देना होगा।

(ii) विद्यालय अध्यापकों का प्रशिक्षण देने की वर्तमान प्रणाली में दोष इसलिए है कि जिन विद्यालयों के लिए उन्हें तैयार किया जाता है उनके सम्पर्क में बिना ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण देने वाला विभिन्न प्रकार का सत्यापन एक दूसरे के सहयोग में नहीं आता बल्कि काम करते हैं। इस अन्तर्गत की ताड़न के लिए शिक्षा की एक स्वतन्त्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा, प्रथम एक दूसरी स्नातकीय उपाधियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम में केवल एक विषय के रूप में शिक्षा विषय का प्रारम्भ किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण प्रकार एक अनुमान से सम्बन्धित उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए सुनिश्चित विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाय जहाँ जहाँ माधन तथा अध्यापक उपलब्ध हैं तथा तथा समस्त प्रशिक्षण गत्यापकों का महाविद्यालय स्तर पर उन्नत किया जाय ताकि अध्यापक शिक्षा अन्तर्गत विश्वविद्यालयों की सामाजिक भा जाय। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित गत्यापकों विद्यालयों के मध्य सत्यापन छात्राध्यापकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण का व्यवस्था विद्यालयों में विस्तार सेवाओं के विभाग, प्रशासनिक आवश्यकताओं का स्थापना और महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के सम्पर्क-क्रम में केन्द्र स्तर की व्यवस्था के द्वारा तथा सर्व-ग्राह्य सम्पूर्ण प्रशिक्षण गत्यापकों के निर्माण के द्वारा भी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अध्यापकों का समाप्त किया जाना चाहिए।

(iii) अध्यापकों का व्यावसायिक तयारी से सम्बन्धित कार्यक्रमों का स्तर बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ पर्याप्त स्तर पर उन्नत करने के लिए आवश्यक है कि विषयगत से सम्बन्धित विशिष्ट पाठ्यक्रम का समर्थन शिक्षा के व्यावसायिक अध्ययन का कुछ बनाया जाय पाठ्यक्रम में सुधार तथा उच्च पुनर्निर्माण किया जाय शिक्षण और व्यावसायिक नयी तथा

गतिशील पद्धति का अपनाया जाय और छात्र शिक्षण में सुधार किया जाय।
 सेवारत शिक्षा की व्यवस्था, द्वारा चयन की अधिन अधी पद्धतियों को लागू
 करके नया पाठ्यक्रम में वृद्धि के माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण के स्तर में
 सुधार किया जाय और उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था
 की जाय। इसमें अनिवार्य समस्त प्रशिक्षण संस्थाएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त
 हों तथा छात्र अध्यापकों का छात्रवृत्तियों के निमित्त अधिक प्रावधान
 उपलब्ध हों।

(iv) समस्त अध्यापकों को सेवातन्त्र शिक्षा का पर्याप्त सुविधा हो।

(v) विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नव नियुक्त
 बनिष्ठ व्याख्याताओं के (शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान के) अनुस्थापन के लिए समुचित
 व्यवस्था करें।

(vi) प्रत्येक राज्य सभी प्रकार के अध्यापकों में सम्बन्धित अपनी
 आवश्यकताओं का नियमित रूप से अनुमान लगाय और उनका मामात्र शिक्षा
 तथा सेवापूर्व एवं सेवातन्त्र व्यवसायिक तयारी सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं
 का प्रदान करने के लिए एक योजना तय करें। ऐसी योजनाएँ इन पूर्ण-
 वार्षिक शिक्षा सुविधाओं के साथ-साथ पाठ द्वादश और पन्नास पाठ्यचर्या
 सम्बन्धी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी करें।

(vii) अध्यापक की शिक्षा व विचार तथा इनका योगदान के
 लिए प्रत्येक राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड का स्थापना करे। विश्वविद्यालय
 अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के स्तर तथा उच्च सगति
 बनाय रखने के उत्तरदायित्व का स्वयं अपने ऊपर ले तथा इस हेतु राष्ट्रीय
 शैक्षिक अनुमान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से एक स्वयंसेवक समिति
 का निर्माण करे।

35 विद्यालय पाठ्यचर्या

प्रमुख आवश्यकता यह है कि विद्यालय पाठ्यचर्या में सुधार तथा उसे
 उन्नत किया जाय, उसमें जन भा रहे निरर्थक तत्वों का दूर किया जाय,
 उनके ज्ञान पर में वृद्धि की जाय, बाधित बुद्धिमानों के विचार हेतु तथा
 सहा रचिया, अनिवार्यता एवं मूल्य उत्पन्न करने के लिए समुचित व्यवस्था
 की जाय।

36 इस गान में दो मुख्य नीतियों को अपनाया जाता है

(1) प्रथम यह है कि राज्य भर में समस्त स्तरों पर एक सामान्य
 पाठ्यचर्या अपनाया जाये। इस प्रकार का दिना सोच वाली व्यवस्था

उन्नति में बाधक मिट्टी होती है, क्योंकि उगाया पानन करना कमजोर मस्याप्रा के घात का घात नहीं हानी तथा दूसरी छार अच्छी मस्याप्रा के लिए यह पाठ्यचर्या काई चुनौति स्वस्थ नहीं होती। इन आवश्यकताएं एर ऐसी तबीयती व्यवस्था की है जिससे छात्रगत पाठ्यचर्या उपरान्त नेत्र के गुण तथा साधना में धाम्निवि रूप में जुने हागी। तात्पर्य यह है कि एर ही माय एर से अधिक पाठ्यचर्या अपनाने के साथ-साथ एर एगी तबीयती प्रजातनिक व्यवस्था भी लागू की जाय जो विद्यालय का नयी मूह मूह के साथ करन के लिए प्रागाहित कर।

(11) एमी तरह मगाहित अथवा उनका पाठ्यचर्या का सभी मस्याप्रा में एक साथ अपनाय जाने की चर एनी रानि का भी छात्रना हागा, क्योंकि एगा लिए न ता प्रशिक्षण द्वारा पर्याप्त मस्या में अध्यापन की छौर न मुनिपात्रा का व्यवस्था होना सम्भव है। अध्यापन का सटया तथा उपरान्त मुनिपात्रा का ध्यान में रखत हुए गुरा हुइ पाठ्यचर्या का एक से अधिक विषया या समय रूप में अपनाने का छूट विद्यालय को भी जानी चाहिए और एर एगी मुनिपात्रित वायत्रम भी बनाया जाना चाहिए कि ममा विद्यालय हुइ हो वगी में पाठ्यचर्या में आवश्यकता मुपार कर गये। इस अन्तरनी अथवा में एना ही प्रकार की पाठ्यचर्या के अन्तर्गत परिक्षा लो जाय।

37 एम समय विद्यार्थनी की गिता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बरता की में आरम्भ हो जाना है यह बहुत जना है। वादनाय यह है कि जब तक छात्र प्रथम स्वर्णीय विद्यालय गिता समाप्त न करने तक तब तक समाप्ताना के लिए सामान्य गिता के समाप्त पाठ्यक्रम उपरान्त कराये जायें तब दूसरे बार ही उच्चतर माध्यमिक स्तर में विद्यार्थनी की गिता आरम्भ हो जाय। इस प्रकार के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम का बराबर स्वरूप परिगणन 2 के अनुक्रम हागा।

38 विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण करन समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रित हो जाना चाहिए—

(1) पाठानुक्रम तथा समाप्त गवा सभी स्तर का शिक्षा के अन्तिम अंग हो।

(2) एर 10 का समाप्त तब एग छात्राग्रा का पाठ्यचर्या में गिता प्रकार का हो करन का काई धारमरता गता है गिताय उन धरणिता रिगता के का बरानुक्रम के अन्तर्गत निर्धारित रित जायें तथा आगाहित रूप रवार्थन रित में भी उपरान्त परिषदाय रित का मतत है।

(iii) विज्ञान एवं गणित की पाठ्यचर्या में आधुनिकता परिवर्तन किया जाये तथा उसे आधुनिक बनाया जाय ।

(iv) इस समय छात्रों पर भाषा साधन का जो भार है उसे शान्तिपूर्ण रूप से कम किया जाना आवश्यक है । त्रिभाषा सूत्र में सुधार करना तथा भाषा शिक्षण में आधुनिक पद्धतियों का अपनाना जाना भी आवश्यक है ।

(v) घर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का स्तर पर निर्धारित की जाय—सामान्य तथा उन्नत (एडवांस्ड) ।

39 विद्यार्थिबिद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन

विद्यार्थी स्तर पर तथा प्रथम स्नातक उपाधि के लिए निर्धारित विषयों का अध्ययन सम्बन्ध कम बढ़ाया तथा छात्रों को इस बात का दृष्टि हो कि वह अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन करे और इस प्रकार उन विषयों का भी लक्षण हो जो उन्नत विद्यार्थी-स्तर पर नहीं लिए जायें । इसी तरह प्रथम तथा द्वितीय स्नातक उपाधि हेतु विषयों का मनाने वाला विषयों का चयन भी उन्नत अधिन लेखाया जायें सामान्य ध्यान प्रचलन में है । यह विषय-मयाजन दोनों ही बातों तथा विज्ञान विषयों के लिए आवश्यक है क्योंकि वे विषय जो अब तक एक दूसरे में सम्मिलित शिक्षा देते थे अब अधिन घटित रूप में सम्मिलित लगने लगे हैं । उच्च स्तर की शिक्षा पर ता यह परम्परा दृष्टि होना चाहिए ।

40 प्रथम स्नातक उपाधि के लिए पाठ्यक्रम का प्रकार का हो—सामान्य तथा विशिष्ट । सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र एक ही सामान्य स्तर के तीन विषयों का लेता है—इनमें भाषा और शैक्षणिक क्षमता—उत्तरीय तथा प्रमाण । प्रथम प्रकार स्तर पर ही विशिष्ट पाठ्यक्रम को व्यवस्था हो । विश्वविद्यालय के उन विशिष्ट पाठ्यक्रमों तथा प्रयोग स्तर के विभिन्न सामान्य पाठ्यक्रमों का व्यवस्था करें । अध्ययन की मर्यादा का तथा प्राप्त गुणवत्ता का दृष्टिगत रखते हुए सम्बद्ध महाविद्यालय तथा स्तर के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं । अन्य भाषा का काम सर्वोत्तम बनाना के लिए सामान्य (प्रमाण) तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अनुक्रम प्रदान करना निर्धारित हो जाना चाहिए ।

41 राजभाषा उपाधि के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तीन प्रकार के होंगे—

(i) उच्चतराध्ययन तथा अनुसंधान के लिए तैयार करना,

(ii) विद्यानया के लिए अध्यापना को तयार करना, और

(iii) उन छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करना जो इस स्तर पर भा विस्तृत एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। और जो बाद में पाएच डी स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रथमिए एा विषया पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऐसे सयोजन-पाठ्यक्रम भी आरम्भ किए जाय, जिनमें कोई एक मुख्य और एक या दो सहवर्ती विषया सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं।

12 पीएच डी उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के चयन में बदाई करने की जाना चाहिए तथा मूल्यांकन की पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। निम्नो द्वितीय विषय भाषा जल रूमी जयन तथा प्रच भाषा का अध्ययन वर्जित है। निदेशना का मापना तथा आवश्यक गुणधर्मों को ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

13 यह भा वादनाय है कि कम से कम एक भाषा में पीएच डी का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम उपाधि आरम्भ की जाय। इसी तरह यह भी वादनाय है कि पाठ्यक्रम में से ऊपर के स्तर की उपाधि जिन विषय विद्यानया में आती है वही उन आरम्भ किया जाय।

14 ऐसे विविध प्रयत्न भा किये जान आवश्यक हैं जो बता तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अत्यन्तविध विषयों के अध्ययन को उत्प्रेरित करें। इसमें विभिन्न विषय तथा क्षेत्रों तथा विभिन्न समस्याओं के अध्ययन विभागों के बीच सहयोग के लिए तथा पद्धति तथा नये प्रकार के अध्यापन वगैरे की आवश्यकता होगी। इसमें साथ-साथ यह भा आवश्यकता है कि वर्तमान यानिर्ण, औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की आवश्यकताओं में सम्बन्धित विषयों के प्रतिभाओं के लिए आवश्यक (अथवा समुचित अवधि के) विविध पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाय। पाठ्यक्रम का प्रवृत्ति अथवा उन्नत धर्मिक का ध्यान में रखा हुआ प्रकाश सम्बन्धी मापना भी समझा कम समझा अथवा कृषि या इतरातिर्माण की प्रथम उपाधि होगी। जो इस पाठ्यक्रम के मफयतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रयास-यत्न दिनामा अथवा रनातन-यत्न प्रदान किया जा सकता है।

15 विद्यालय स्तर पर भा सुधारों में तथा प्रविष्टि पाठ्यचर्चा के समय समय पर पुनर्विचार तथा सुधारे का भा आवश्यकता है। यह पुनर्विचार का बार बार किया जाना चाहिए। यह है कि विनियोजन अधिनियम द्वारा निर्मित

पुनर्विरोधन ममितिषा के कामधर्म को अधिक गतिशाली तथा विस्तृत बनाया जाय ।

40 विद्यालय पाठ्य पुस्तकें

शिक्षा के स्तर का उपरन करन के लिए उच्च प्रकार की पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था-माध्यमों कायम करना ही प्रभावशाली सिद्ध होगा । अध्यापक निर्देश पुस्तिका तथा अन्य अनुशासक सामग्री का भी अधिक मात्रा में विमोक्षण किया जाय । निम्नलिखित उपायों द्वारा इसका विस्तार किया जाना चाहिए

(i) प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम तीन या चार स्वीकृत पुस्तकें हानी चाहिए तथा अध्यापक की इन ज्ञान की सूची हानी चाहिए कि यह उनमें से विद्यालय के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त पुस्तकें ही चुन सकें । जहाँ विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकें प्रचलित हैं जहाँ प्रत्येक उपरर पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित बहुत सी पुस्तकें में से चुनाव करने की उम्र सूची हानी चाहिए ।

(ii) पाठ्य-पुस्तक का विमोक्षण एवं मनुष्य प्रक्रिया है जिससे आरम्भिक उत्पादन प्रयत्न तथा उन्हें क्षतिग्रस्त एवं दूना आदि गन्मिनि हैं । पाठ्य-पुस्तक-निर्माण के लिए अथवा सर्वोत्तम व्यवस्था प्रत्येक पुस्तक के लिए इन उपायों का अन्तर्गत में समर्थ हानी चाहिए । यह ज्ञान भी निश्चित हानी चाहिए कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का मनुष्य पुनरीक्षण किया जा चुका है और यह आपुनित्वम जानकारी सम्पन्न है तथा बार बार नहीं तो कम से कम पांच वर्षों में एक बार या उसका सम्पूर्ण समायोजन कर दिया जाना चाहिए ।

(iii) यथासम्भव अधिक क्षेत्रों में अच्छी पाठ्य-पुस्तकें विपणन के प्रयत्न की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए । पुस्तकें विपणन के लिए कुछ चुन हुए लोगों का काम देने के अन्तर्गत अन्य ज्ञान में भी पाण्डुलिपियाँ तथा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाना चाहिए एवं विद्यार्थियों के उपयोग के लिए गणित द्वारा चुने हुए अथवा स्वीकृत पाठ्य पुस्तक का काम में लाया जाना चाहिए ।

(iv) पाठ्य-पुस्तकें विपणन के लिए अध्यापक का विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

(v) विश्वविद्यालय एवं विद्यालय समारंभ का चाहिए कि वे धीरे धीरे पाठ्य पुस्तक का मनुष्य व्यवस्थापित मायना प्रदान करें ।

(११) तत्पत्रा का पारिश्रमिक दान के सम्बन्ध में उदारनीति अपनायी जानी चाहिए। गरबारी क्षेत्र में तो इस विशेष रूप से स्थान दिया जाना चाहिए।

17 पाठ्य-पुस्तका का सुधारन के निमित्त मजिनीरी का यदि समुचित रूप से विकसित कर दिया जाता है तो पाठ्य पुस्तका के सुधार काम में महत्त्व बहुत बड़ा योग दे सकती है। यह काम ही राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक स्वायत्त समन्वय होना चाहिए जो व्यापारिक आधार पर पुस्तका का निर्माण करवाये। शिक्षा विभाग के महायोग से न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय गति अनुमोदन एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन सी ई आर टी) राष्ट्रीय आधार पर पाठ्य-पुस्तका का निर्माण करनी है। अपने अपने क्षेत्र की पाठ्य-पुस्तका में सुधार करने के लिए राज्य सरकार का एक कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाना चाहिए तथा आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें अपने क्षेत्र में उपयोग में लाना चाहिए। इस माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तका के निर्माण के लिए भा व्यापारिक आधार पर एक स्वायत्त समन्वय को बनाया जावे की आवश्यकता है। एक समन्वय का मुख्य उद्देश्य होगा उच्च शिक्षा के लिए तैयारी एवं विज्ञान विषया में सम्बन्धित शिक्षा या उच्च मत्ता पाठ्य-पुस्तका का निर्माण करना जिनके लिए विभिन्न राज्यों द्वारा पृथक् पृथक् प्रयत्न करना सामर्थ्य नहीं है। इस समन्वय के कार्य का एन सी ई आर टी में सामर्थ्य विज्ञान होगा। ये दोनों समन्वय राज्य स्तरीय समन्वय के पूर्ण होंगे।

18 उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य साहित्य

इस तरह यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य साहित्य का विविध प्रकार का आधुनिक भारतीय भाषाओं में, निर्माण किया जाय। यह दृष्टिकोण में—

(1) अधिकांश भाषाओं में अधिकांश विषयों के लिए उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक न किम सामग्री पर जोर साहाय्य (Subsidised) पाठ्य पुस्तका के निर्माण की योजना में विस्तार दिया जाना चाहिए। उक्त प्रयत्न रूप से विस्तार दिया जाय

(2) भारतीय तत्पत्रा द्वारा विभिन्न पुस्तकों के लिए इस तरह के उत्पन्न किए जाने का पर्याप्त ध्यान दे क्योंकि बहुत बड़ा मात्रा में श्रेष्ठ

पाठ्य पुस्तकें गरीबी हानी हैं उनका निर्माण में विश्वी मुद्रा की उत्तमता व अनिरुद्ध व बौद्धिक विचारों व दृष्टिकोण में भी अनुपमता होती है। यह प्रथम श्रेणी की पुस्तकें के निर्माण के लिए आवश्यक मापना एवं योग्यता की कमी नहीं है लेकिन क्या है सुनियोजित एवं सुन्दर प्रयत्न की

(111) वित्तविकार पारिभाषिक गणित के निर्माण काय की गति से जानी चाहिए और

(12) या 10 वर्षों में ही अथवा स्नातक स्तर के निमित्त आवश्यक पुस्तकों में से अधिकांश पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें जिनमें विज्ञान तथा औद्योगिकी में सम्बंधित पुस्तकें भी सम्मिलित हैं का दायें भी निर्माण किया जाना चाहिए। इन पुस्तकों के निर्माण में विश्वी स्तर का पूरा ध्यान उठाया जाना चाहिए।

19 छात्रों में पुस्तक वितरण

प्राथमिक स्तर के समस्त छात्रों को नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें व वितरण का व्यवस्था की जानी चाहिए।

माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक ज़रूरतमन्द छात्र को पर्याप्त मात्रा में तथा नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें।

प्रत्येक वर्ष के प्रथम 10 प्रतिशत कुशल बुद्धि छात्रों को पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार की पुस्तकें सरोजित के लिए उपयुक्त का याचना भी की जानी चाहिए। यह याचना का विश्वविद्यालय स्तर में आरम्भ करके फिर विद्यालयों तक विस्तार दिया जा सकता है।

20 शिक्षा प्रणाली में सुधार

शिक्षण की प्राथमिक पद्धतियों का अध्ययन जान के विषय में पहिले ही विचार दिया जा चुका है। इन पद्धतियों का प्रभावकारी ढंग से समाप्त करना जा सकता है जहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अत्युत्तम सुधार किए जायें। मूल्यांकन का नया पद्धति के अन्तर्गत यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों पर बाह्य परीक्षाओं का बोझ कम हो। शिक्षित परीक्षा का इस तरह सुधार जाय कि यह अनिवार्य उपयुक्त का वास्तविक माप बन जाय तथा छात्र के विचारों सम्बन्धित जिन मन्त्रपूज्य पक्षों का शिक्षित परीक्षाओं द्वारा नहीं जाना जा सकता, उनका जीवन के लिए नयी उन्नति सम्पन्न हो जाय।

51 प्रथम प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 4) की अव्यक्त या अवर्गीकृत व्यवस्था के निमित्त अध्यापका को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 से 7) से लिखित परीक्षाएँ आरम्भ की जा सकती हैं लेकिन अधिक महत्व भौतिक परीक्षा का दिया जाय। नदानीय परीक्षाएँ तथा संचितवृत्त (Cumulative Record) पद्धति मरन किन्तु प्रथम ढंग से आरम्भ की जाएँ। प्राथमिक स्तर पर बाह्य अनियमित परीक्षा नही होना चाहिए लेकिन छात्रवृत्तियाँ प्रथम या प्रथम प्रमाण पत्र देने और माध्यम निधारित करने के उद्देश्य से ऐसी सामान्य परीक्षाएँ ली जाय, जो प्रमाणपत्र तथा परिपत्रन जाँच पर आधारित हो। प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यालय प्रमाण पत्र दें। जिनके साथ संचितवृत्त पत्र लगा हो तथा यदि कोई सामान्य परीक्षा ली गयी हो, तो उसका परिणाम का विवरण भी दिया जाना चाहिए।

20 माध्यमिक स्तर पर दो बाह्य परीक्षाएँ हों—पहली कक्षा 10 के अन्त में और दूसरी कक्षा 12 के अन्त में (जब तक कि विद्यालय पाठ्यक्रम का कुछ अवधि 12 वर्ष का न हो जाय) अन्त में अन्तर्गत काय में यह परीक्षा कक्षा 11 के बाद भी ली जा सकती है)। प्रथम पथ निमाताओं की क्षमता में विभाग के द्वारा प्रथम पत्रों का बतलाना प्राप्ति हो न हो यत्कि प्रथम उद्देश्य की जाँच के अनुकूल बनाकर प्रथम में सुधार करके तथा अथ प्रथम करने का अनिवार्य पद्धति अपना कर प्रथम प्रथम उपाय से बाह्य परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

53 किसी निरीक्षक आधार पर कक्षाप्रति दिन के साथ साथ मापनिक आधार पर परीक्षा परिणामों के अनुसार मापनिक निर्धारित की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष प्रथम धरणा छात्र उन प्रथम 20 प्रतिशत छात्रों में से एक है जिन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

54 यह अवश्य अनिवार्य है कि परीक्षाओं के समाप्त होने तथा उनके परिणामों के घोषणा के साथ ही समय-समय-समय-समय कम हो। इससे लिए हर सम्भव उपाय आरम्भ करना चाहिए अथवा उत्तर पुस्तिकाओं का जाँच के लिए परीक्षा के एक ही स्थान पर एकत्रित करना या उपयुक्त करना, प्रथम परीक्षा के दो दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना इत्यादि। 10

10 परीक्षा कक्षा 12 के 51 तक बाह्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में जो सुधार किए गए हैं उन्हें अथवा परिवर्तन सन्धि निम्नलिखित स्तर पर भी लागू की जाय।

55 राष्ट्रीय मानका का तीन स्तरों पर स्पष्ट पारिभाषिक करने की आवश्यकता है—प्राथमिक स्तर का समाप्ति पर (बंदा 8), श्रम माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर (बंदा 10) और उच्चतर माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर (बंदा 12)। स्थानीय परिस्थितियाँ तथा विकास के उपलब्ध स्तर का ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य सरकार का उक्त तीनों स्तरों पर प्राप्त नियम जान योग्य शक्ति मानक निर्धारित करने चाहिए। इन शक्ति मानकों का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया जाय तथा एक एक राष्ट्रीय स्तर के शक्ति मानकों का निर्धारण किया जाय जिसमें निम्न स्तर की शिक्षा सामान्यतया किसी भी राज्य में न दी जाय, यद्यपि कुछ राज्य कम-यूननम स्तर से ऊँचा स्तर प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकें हैं। विद्यालय जिना राज्य तथा राष्ट्रीय आधार पर प्राप्त किया जान वाला आन्तरिक शक्ति मानक या स्तर का मूल्यांकन करने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। ये भी प्रयत्न किये जाय कि राष्ट्रीय शक्ति मानक उत्तरोत्तर उन्नत हात रहे और इस दृष्टिकोण में समय-समय पर एक मुनिपाकृत स्तरों का स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाय, जिन्हें विकास की एक निश्चित अवधि में प्राप्त कर लेना है।

56 सभी शक्ति संस्थाओं में आन्तरिक जाँच का व्यवस्था का आरम्भ किया जाय। यह व्यवस्था सब तरह से पूर्ण हो तथा इसके अंतर्गत छात्र के उन पत्रों का मूल्यांकन किया जाय, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनकी बाह्य परीक्षा द्वारा जाँच नहीं की जाती है। यह मूल्यांकन विवरणात्मक ही नहो मापनमक भा हो। बाह्य परीक्षामात्र में प्राप्त अंकों का इन परिणामों में साधारणतया नहो जाना जाना चाहिए। बाह्य परीक्षामात्र में प्राप्त अंकों का अलग रखा जाय तथा प्रतिम प्रमाण पत्र में उनका उल्लेख न कर दिया जाय। आन्तरिक जाँच तथा बाह्य परीक्षामात्र में अलग-अलग उत्तरण होना आवश्यक होता चाहिए और उनमें प्राप्त अंकों भी अलग-अलग ही दिखाए जाने चाहिए। प्रतिवर्ष आन्तरिक एक बाह्य जाँच के बीच सह-सम्बन्धों का ध्यानपूर्वक पुनर्विचारित किया जाय और यह प्रत्येक संस्था के लिए अलग-अलग हो। आर्थिक अनुमान देने के लिए गतिमान संस्थाओं का वर्गीकरण करने समय इन बिंदुओं का ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो संस्थाएँ अपने छात्रों के मूल्यांकन में आधुनिक मापदण्डों नहीं रखती उन्हें न केवल स्तर के दृष्टिकोण में, बल्कि आर्थिक संशयों के दृष्टिकोण में भी हानि भुगटनी पड़े। निम्नलिखित परीक्षाओं के मापदण्डों में उनकी भाषाओं अथवा सम्बन्धों का समावेश कर दिया जाय।

वर सत्रों आदि । जिस विश्वविद्यालय से यह महाविद्यालय सम्बद्ध है, उसका काम हागा सामान्य परीक्षाएँ तथा उपाधि वितरण । इन महाविद्यालयों को यह विषयाधिकार हमसा के लिए नहीं दिया जा सकता इन प्राप्त करने के लिए ता उच्चतम प्रयत्न करने होंगे और क्षमता एवं योग्यता का प्रदर्शन करना हागा । स्थिति का ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद यदि यह पता लग कि बिना महाविद्यालय के स्तर में गिरावट घान रहा है, तो विश्वविद्यालय का अधिकार हागा कि वह उसका स्वायत्तता सम्बन्धी अधिकार का समाप्त करे । विश्वविद्यालय के मंत्रिधान में ऐसे स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयों को मान्यता देने का प्रावधान किया जाय तथा एस प्रयत्न क्रिय जान चाहिये कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कम से कम 50 प्रतिशत उत्तम महाविद्यालयों का ब्राह्मण न होजाये ।

७९ शैक्षिक संस्थाओं के आकार तथा अवस्थिति सम्बन्धी योजना पिछले कुछ वर्षों में छोटी तथा अधिक रूप में हानिप्रद संस्थाओं में वृद्धि हुई है । शिक्षा के सभी स्तरों पर इन संस्थाओं में अनुशासन का परिचय दिया है । यह आवश्यक है कि इस बड़नी हुई संख्या में गुणवत्ता का परिचय तथा समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक योजना बनाया जाय ताकि परस्पर व्यापक अनुक्रमण द्वारा वृद्धि तथा अपव्यय को रोका जा सके और अधिक गुणवत्ता तथा सामान्यक संस्थाओं का स्थापित किया जा सके । प्राथमिक स्तर की संस्थाओं में बार में ता इन विचारों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि प्राथमिक संस्थाओं में हम दृष्टिकोण से पानी जाता है कि व्यावहारिक रूप से जितना सम्भव हो प्राथमिक शालाओं का बालकों के घर के निकटन में होना जाय, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह विचार अधिक महत्व रखता है तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ता यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है । अतएव यह आवश्यक है कि सभी ब्राह्मणों की शिक्षा संस्थाओं में स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में सुविचारित मापदण्ड बनाया जाय और इन मापदण्डों के आधार पर प्रत्येक दिन के लिए पृथक् रूप से आगामी 10-15 वर्षों के शैक्षणिक विकास के सम्भावित कार्यों का याचना तथा करीबी रूप से एकी याचनाओं के निर्माण तथा समय समय पर अपनाना जान बाली पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारित किया जाना चाहिए । इन याचनाओं के आधार पर वर्तमान स्थिति का समीक्षण किया जाय एवं नया मापदण्ड तैयार करने दिया जाना चाहिए ।

६० सुविधाओं की व्यवस्था शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार प्राप्त साधना की सुचना

म कही अधिक तीव्र गति से हान व क्षरण वृद्धि-मो गतिव मस्थाप्रा म सुविधाप्रा सम्बन्धी स्थिति बढ्ना ही धर्मतोषजनक है। वे उन यूनानम आवश्यकताप्रा का बढ्ना पूर्ति भी नहीं करती, जो गिशा विनाग और विरय विद्यानया व प्रयत्न नियम म निर्दिष्ट हैं। वृद्धि मो सस्थाएँ बढाया म छात्रा की मर्या आवश्यकता में बढा अधिक हान की ओर प्रवृत्त हैं। गिशा का अधिक प्रभावगामी बनान व त्रिण इन स्थिति म सुधार विय जान की आवश्यकता है।

विद्यालय स्तर पर कला म छात्रा का अधिकतम सत्या निर्धारित की जाना चाहिए तथा इनका बढोरना स पानन रिया जाना चाहिए (यह मर्या धर्म प्राथमिक स्तर पर 50 उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 तथा माध्यमिक स्तर पर 10 है)। विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय का उपनय सुविधाप्रा का ध्यान म रगत हुए छात्रा व प्रवेश सम्बन्धी नियम विस्तृत रूप में निर्धारित करने चाहिए तथा उनका हक स पानन करना चाहिए।

उत्तरण गुणवत्ता तथा प्रयोगागाराप्रा सम्बन्धी सुविधाप्रा की समुचित उपस्था बढ्ना महत्व रगना है तथा नन सुविधाप्रा व सम्बन्ध म उपयुक्त स्तर की आवश्यक रूप म बनाय रगा जाना चाहिए।

व्याख्यान तथा पयात गात्र सामान ग सम्पन्न भवना की ध्यरस्था की बढ्ना कम महत्व रिया गया है। स्थानीय भवन निमाण नामग्री व उपभाग, मित्रध्वषिता, भवन व छात्रा तथा निमाण म सामग्री एवं पवित्रता व द्वाग मय म अधिकतम कगीता करक ही भवन एवं मय उक्त सुविधाप्रा का जुगना हागा। इन हनु स्थानाय समान में प्राथमिक स्तर पर विशेषतः मर्याग रिया जाना चाहिए।

वायानुमय सम्बन्धा वायनम की भी इन मर्या म बढाया जा सकता है कि इनक रगिगामम्बन्ध निगल व त्रिण वृद्ध आवश्यक उपकरण तथा मर्याग मापन मागाना म प्राप्त है। जाय। ध्यायतः व। तथा प्रगिगाम रिया जाता चाहिए कि वे स्थानीय सामग्री म कम कीमता निमाण महापरा मापन संसार कर गये। अधिक मूल्यवान तथा जटिल उपकरणों व सम्बन्ध म तम उपयुक्त वायनम का धरनाया जाना चाहिए कि जिनक धनगतन मस्थाप्रा का मर्या उद् ममानक्य ग काम म ला गये।

मापन की मापितता व क्षरण गति बढ्ना बढार निगय मना हो पड़े, तो कम ग कम प्राथमिक स्तर की गि ता म उगगता म काम रिया जाय जहाँ रि विगार की मबाधिक प्राथमिकता भी जानी है। निगिन माध्यमिक

और मुख्यतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा-सम्बन्धी 'यूनतम आवश्यकताओं' में किसी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिए और यदि बहुत ही आवश्यक हो, तो नयी समस्याओं की स्थापना तथा प्रवृत्ति सम्बन्धी वृद्धि पर समुचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए ।

61 छात्र सेवाएँ

छात्र सेवाएँ बखल करवाएँ वायव्य नहीं हैं अपितु वे शिक्षा का अनिवार्य भाग हैं क्योंकि स्तर का बनाया रखना का समस्या मुख्यतः उन्हीं पर आधारित है । पाठ्य-पुस्तक का निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में पहले ही जिन विचारों का ज़ुका है । इससे साथ-साथ कई और प्रकार की सेवाओं की भी आवश्यकता है ।

62 उदाहरण के लिए विद्यालय स्तर पर यह आवश्यक है कि निर्देशन तथा परामर्श सेवाएँ और धारम्भ की जाएँ । प्राथमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम का अन्तर्गत सीधे तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए—जैसे अध्यापकों की नैतिक जाँच तथा व्यक्तिगत अन्तर-सम्बन्धों की जाँच सम्बन्धी प्रशिक्षण इत्यादि एक भाग की शिक्षा के सम्बन्ध में चुनाव करते समय छात्रों तथा माता-पिताओं की सहायता करना । माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएँ ऐसी होनी चाहियें जो विचार-छात्रों की माँगों तथा उनकी क्षमताओं का एक दृष्टिकोण के विकास में सहायता करें । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसा 'यूनतम कार्यक्रम' बनाया जाना चाहिए जिसका अन्तर्गत कुछ समस्याएँ एक ही परामर्शदाता की सहायता का भिन्न-भिन्न स्तर पर उठाये जा सकें और कुछ पुनर्निर्देशन विद्यालयों में व्यापक निर्देशन कार्यक्रम धारम्भ किए जाने चाहिए । विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ (जिनमें विद्यालय द्वारा मर्यादित की जाने वाली मानव-व्यवस्था का सम्मिलित है) यथामुक्त अधिक विविधता की जानी चाहिए । कम से कम ज़रूरतमन्द छात्रों के लिए तो यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए तथा योग्य छात्रों के लिए कपड़े जुटाये जाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

63, विश्वविद्यालय स्तर पर सकारण में नये छात्रों का नामांकन सम्मिलित बनाने के लिए छात्र-सहायता के अन्तर्गत अनुस्थापन कार्यक्रम सम्मिलित किये जाएँ । प्रत्येक छात्र किसी शिक्षक-सहायक (शिक्षण सचिव या सहायक का प्रमुख सचिव) के सम्बन्ध में होना चाहिए, जो छात्रों की अपनी अध्ययन-कार्यक्रम सम्पत्ति करने तथा तत्सम्बन्धी योजना बनाने में सम्मिलित हों । विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ विविधता की जानी

चाहिए जिनमें स्वास्थ्य शिक्षा भी सम्मिलित हो। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएँ भी उपरन्व की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष 1000 छात्रों पर कम से कम एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाना चाहिए। सूचना एवं काम निष्ठा केन्द्र मधुसूदन में स्थापित किये जाने चाहिए। केवल अध्ययन व्यवधि में ही नहीं किन्तु अवकाश व्यवधि में भी छात्रों के लिए सुमधुसूदन एवं विविध प्रकार का महत्वाकांक्षी गतिविधियाँ को नियोजित किया जाना चाहिए। छात्रावास में रहने की सुविधा का अधिक उत्तम बनाया जाना चाहिए (स्नातकोत्तर स्तर पर कुल भर्ती के 20 प्रतिशत स्थान अधिस्नातक स्तर पर कुल भर्ती के 50 प्रतिशत स्थान उपलब्ध कराये जाना का लक्ष्य निर्धारित किया जाय)। छात्रावास में बाहर रहनेवाले छात्रों में से कम से कम 20 प्रतिशत छात्रों के निमित्त कम से कम विधिवत् व्यवस्थापित व्यवस्था दिवस अध्ययन केन्द्र (डेस्टीनेटेड) की स्थापना की जानी चाहिए। समस्त विश्वविद्यालयों में व्यवस्था बड़े महाविद्यालयों में एक ऐसा पूर्णकालिक छात्र कल्याण दिनमाध्यक्ष होना चाहिए जो छात्र कल्याण से सम्बन्धित प्रश्नों की दृष्टिगत करे।

6। प्रतिभागियों की शोध एवं विकास

यह अनिवार्य है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों की व्यक्तित्व अभिवृद्धि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तथा पिछड़े हुए एवं कुशाग्र बुद्धि छात्रों के सम्बन्ध में विशेष कायक्रम निर्धारित किये जाएँ। कुशाग्र बुद्धि प्रतिभावान छात्रों में सम्बन्धित कायक्रम का छात्रों की परिस्थितियों में विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय जीवन की प्रवृत्त शाखा में प्रशिक्षित जन बल का समग्र तीव्रता से अनुमन किया जा रहा है और शाखा यहाँ वह सबसे बड़ा कारण है जो हमारे देश का प्रगति में बाधक है। भूमि बुद्धि प्रायः सब में समान रूप में वितरित होती है और यदि देश बुद्धि का समय रहने काज निभाता जाय तब तो विश्वविद्यालयों में हमारे देश का विकास जन मर्यादा निर्धारण है। हमारे देश में मर्यादित नियामन ही सबसे बड़ा है।

65. यह समस्त उपरन्व प्रतिभावादी का अनुमन प्रश्न है। शाखा के विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। अधिकांश प्रश्न में बालावरण अनुमन नहीं होता। अधिकांश प्रतिभावान विद्यार्थी या तो प्राथमिक शाखा में प्रवेश ही नहीं करते हैं या इनमें समय तक नहीं टहर पाते हैं कि वे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा परीक्षा में प्राप्त हुए प्रश्न के आधार पर नैतिक प्रतिभावादी बाधक का निपट कराने का दायर्य प्रणाली के कारण ही निर्दिष्ट होता है। प्रतिभावादी का जना है महा मय वाता, दृष्टि धारणा शिक्षा

प्रतिमा का पता लग भी जाता है उसे विनम्र करने के लिए या तो विगिष्ट
 व्यायाम है हो नही और यदि है तो वा ब अपायम है ।

66 इन सबका बचाना हमारा क्या है शिक्षा का राष्ट्रीय व्यवस्था व मुख्य
 उद्देश्य म से एर उद्देश्य यह भी है कि प्रतिमा का पता लगाया जाय तथा
 उसका विनाश किया जाय । गणित अवसरों के समकरण (Liquorisation)
 मध्यपी वायव्यम, त्रिज पर आय के पृष्ठों में विचार विमर्श किया
 जायगा म किता म बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं । उदाहरणार्थ प्रथम वाक्य व
 विषय पांच वर्षों तक की छात्रों और प्रमाणात्मक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था
 म प्रथममंथर विस्तृत मोमा तब प्रतिमा का पता लगान म बहुत महत्वपूर्ण
 सिनगी । शिक्षा व विभिन्न स्तरों पर । स 15 प्रतिशत छात्रों का छात्रवृत्तिपी
 इन व विज्ञान वायव्यम का वागू करने पर छात्रवृत्ति हृष्टा जा गयेगा कि
 गरीबी व वारण बाइ भी नगणित प्रतिमा-मध्यम वाक्य उच्चतम शिक्षा-
 प्राप्ति म वनित नगा होगा कि यह शिक्षा प्राप्त करने व योग्य है । एक
 गुणवत्ता वायव्यम व द्वारा यह सम्भव है गरीबी कि नगणित प्रतिमा-मध्यम
 छात्र उत्तराध्य ध्यान म गत म मध्यमत्तर कर सकें । "मन साय हा यह
 वाक्यमव ह कि अधिन धमतावाय छात्रों व विषय वनामममय अधिन विद्यालयों
 में और छात्रों प्रथम विद्यालय म मुख्यतः वायव्यम छात्रम विद्य जातें । "म
 उद्देश्य व विषय या तो प्रत्येक गणित मध्यम पृथक् रूप म या तमा मध्यमता व
 गणित छात्रों महत्व म शाखा बाह्य वायव्यम का गणित करें जग—
 धीमतावाय पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला तथा महत्वपूर्ण व अध्यापन त्रिज
 प्रकार व वायो व विषय छात्र विषय वायव्यम प्रथम गति प्रशिक्षण करने है उन
 वायो म उच्च स्तर पर वायव्यम सध्यापका व गार्थ व्यवितान मध्यम छात्र ।

67 यद्यपि प्रतिमा का गान एक सनू प्रविद्या है जा हर स्तर पर गति
 तथा जाता छात्रों, तन्नि माध्यमिक स्तर पर यह वाक्य बहन म नातुर है ।
 छात्रों विषयविद्यालयों के मध्यम म राज्य शिक्षा विभाग माध्यमिक स्तर पर
 प्रतिमा का गान म सम्बन्धित विषय वायव्यम का विनमित करें ।

68 भारतवर्ष म गणित व क्षेत्र म प्रतिमा व विभाग व विषय विज्ञान
 प्रथम विषय जाने छात्रों बुद्धता इतिहास कि विज्ञान म अनुमान व क्षेत्र
 म गणित का महत्व बहना जा गता है और बुद्ध इतिहास भी कि हमारी मय
 की महान् परम्परा भी म क्षेत्र म वम मध्यम नगा है । छात्रों पांच-म
 वर्षों म गान वा वाक्य विषयविद्यालय म गणित मध्यम उच्चतम व्यवितान-वृद्ध
 समाप्ति विषय जाने छात्रों । विषयविद्यालय व गणित मध्यम मुख्य -

विभागा म से एव विभाग का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के ज्ञान व समर्थता का उत्पन्न करने के लिए गणित में क्रमबद्ध अधिगम कार्यक्रम (प्रोग्रेड तर्जि) की सम्भावनाओं की जाँच में सक्षम रहें। जिन विश्वविद्यालयों में गणित तथा भौतिक विज्ञान के विभाग सबसे अधिक सम्पन्न तथा हर तरह से विकसित हैं, उन विश्वविद्यालयों के सहयोग से गणित में प्रसाधारण क्षमतावाले छात्रों को निम्नलिखित निम्नलिखित में एक भयवा दो विशिष्ट प्रकार के प्रवास माध्यमिक विद्यालयों का स्थापित किया जाना चाहिए। यदि इन तथा ऐसे ही कार्यक्रमों का कार्यान्वित किया जाता है तो आगामी दो दशकों में यह सम्भव हो सकेगा कि विश्वव्यापी स्तर पर गणित के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम लिया जा सके।

69 एगो श्रेष्ठ प्रतिभा के विकास सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों का भी पता लगाया जाना चाहिए तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों का विकसित किया जाना चाहिए।

70 बहुत ही अधिक नैतिक प्रतिभासम्पन्न छात्रों के आगामी शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व राज्य का स्वयं वहन करने चाहिए। पाठ्यक्रम अध्ययन की प्रवृत्ति, प्रवेश योग्यता आदि से सम्पन्न नियमों तथा उपनियमों को भी उपयुक्त मात्रा में उत्तार बनाना होगा।

71 नैतिक समस्याओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम

गणित में नैतिक समस्याओं का नैतिक स्तर को उत्पन्न करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए एका परिस्थितियों का निर्माण करना जिनके अंतर्गत प्रत्येक नैतिक समस्या अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्षम प्रयत्न करती रहे। कुछ मुख्य कार्यक्रमों का जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए वे हैं—निम्नलिखित कठिन धर्म करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना अध्यापकों का गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी छात्रों की समस्याओं को समझना तथा गतिशीलता का जिन उत्तरा पुनर्गठन—य कार्यक्रम गणित में नैतिक समस्याओं में सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम में बहुत अधिक सहायक होंगे। इस कार्यक्रमों के जिन उत्तरा पुनर्गठन में परीक्षाएँ ७ पर हों।

72 इस दृष्टि से निम्नलिखित कार्य उठाये जाने चाहिए

(1) प्रत्येक समस्या के रूप में एक सम्पूर्ण इकाई समझी जानी चाहिए तथा छात्रों को जिन में छात्रों को विचार करने में उन्हे सहायता दी जानी चाहिए।

● इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में आगामी महीने में विचार किया गया है।

इस उद्देश्य से अपने अनुकूलतम उपयोग तथा उन्नति के लिए इस स्वयं का निवासा-मूल कायत्रय बनाना चाहिए।

(ii) इन योजनाओं के अंतर्गत भौतिक साधना को बढ़ान पर हो रहा अपितु मानवाय प्रयत्ना का अभिप्ररित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने सर्वोत्तम प्रयत्ना के द्वारा शिवा म सुधार कर सकें।

(iii) दीर्घकालिक प्रयत्नों का एक निश्चित अवधि तक कार्यान्वित करने के प्रयत्ना की मात्रा पर इस कायत्रय की सफलता निर्भर करती है।

(iv) सभी महत्वपूर्ण क्रांति की शक्ति सत्यामा के लिए दो तरह का मूल्यांकन मानदण्ड बनाया जाना चाहिए—न्यूनतम तथा अनुकूलतम। आरम्भ में सम्पन्न सत्यामा द्वारा स्वयं मूल्यांकन के लिए और बाद में विश्वविद्यालय या विभाग द्वारा आधिकारिक निराक्षण के अथवा स्वरूप इन मानदण्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन मानदण्ड के आधार पर भौतिक सत्यामा की त्रिमूर्ती कायत्रय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है

- (अ) अनुकूलतम स्तर की अवस्था उसमें ऊपर की सत्यामों,
- (ब) 'न्यूनतम स्तर की अवस्था उसमें ऊपर की, लेकिन अनुकूलतम स्तर के नीचे की सत्यामों, और
- (स) 'न्यूनतम स्तर से नीचे की सत्यामों।

(v) स क्रांति की प्रत्येक सत्यामा को कम से कम 'न्यूनतम स्तर तक उन्नत करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए—साथ ही साथ 'अ' क्रांति की सत्यामा की श्रेष्ठता की और अधिक ऊँचाई की प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता अनुदान सम्बंधी नियमों में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

२३ इस समय भौतिक सत्यामा की सहायता देने के सम्बंध में मामूली नति समानता पर आधारित है जिससे पीछे सिद्धान्त यह है कि 'या तो प्रत्येक प्रगति करे या कोई भी न करे'। इन परिस्थितियों में होता क्या है कि व्यावहारिक स्तर पर कोई भी सत्यामा प्रगति नहीं करती। भौतिक वस्तुओं तथा जन जन सम्बंधी साधना की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि शिवा-सत्यामा के विकास में चयन पद्धति को अपनाया जाय। समस्त भौतिक सत्यामा के सुधार सम्बंधी कायत्रय के प्रथम चरण के रूप में आगामी एक वर्षों में सभी स्तर का कम से कम 10 प्रतिशत सत्यामा का अनुकूलतम स्तर (या उच्च भौतिक) तक क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। प्राथमिक-स्तर

पर य 'गुणवता' सम्पूर्ण देश व हर भाग में समान रूप से वितरित होनी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय में कम से कम थोड़ा माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा व क्षेत्र में प्रत्येक जिले में कम से कम एक अच्छा महाविद्यालय विकसित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर यह बाध्यता है कि पाँच या छे जुनिदा विश्वविद्यालय मयासम्भव उच्चतम स्तर तक विकसित किए जाएँ। *

74 नव परीक्षण

यदि उक्त प्रकार के कार्यक्रमों का उपयुक्त बनाना है तो यह आवश्यक है कि राज्य शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपनाये गये प्रचलित धारणा को बदलना होगा। पाठ्य नव परीक्षाओं को मुख्य विशेषता होगी उमरों के लक्ष्य, इस निम्न श्रेणी की समस्याओं का सहयोग तथा निर्देशन देना होगा सामान्य वाणिजी समस्याओं का उत्पत्ति के लिए शिक्षासूचक देना आवश्यक होगी तथा अच्छी समस्याओं का प्रयोग करने का स्वतन्त्रता देना होगी। जहाँ मुख्य कार्यक्रम उमरों के सम्बन्धों का नियंत्रण में रहना नहीं होगा जिससे उनका सहयोग करना तथा उन्हें निर्देशन एवं विस्तार से कार्य उपलब्ध कराना।

75 नव परीक्षाओं के विद्यालय-स्तर पर सम्भव बनाने के लिए कुछ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना होगा जिनमें निम्नलिखित कार्यक्रम भी शामिल हैं

(i) विभागीय मण्डल के अंतर्गत शिक्षा कार्यालय का मुख्य द्वा द्विमान पर विद्यालयों तथा विभाग में यह निम्न सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिये।

(ii) परीक्षाओं का प्रशासन से शुरू किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा विभाग अधिकारों और उमरों के समन्वय-युक्त अधिकार के परीक्षाओं पर हानि करके कार्य शुरू करने में सुधार अध्यापकों के निर्देशन उनमें लिए आवश्यक कार्यक्रमों का गठन तथा विद्यालयों के निमित्त विस्तार देना की आवश्यकता।

(iii) बनाने तथा अपने-अपने में सुधार करने परीक्षाओं अधिकारियों में गुणवत्ता सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें समुचित प्रशिक्षण भी देना होगा।

* एक महत्त्वपूर्ण एक विज्ञापन सम्बन्धों पर ध्यान के लक्ष्य में विस्तार-पूर्वक विचार किया जायगा।

(iv) प्रधानाध्यापक का भा परिवीक्षण काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। उनका चयन ध्यानपूर्वक करना होगा तथा उनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम निधारित विषये जान चाहिए।

76 इस समय प्रत्येक विद्यालय गृहक रूप से काम कर रहे हैं और वे सीधे बच्चों के माता-पिता से ही सम्बन्धित होते हैं। इसकी अपेक्षा यह अधिक वाछनीय होगा कि कुछ विद्यालयों का जाइकर सगम (या छोटे तथा छात्रागारों से सम्बन्धित) गहनवात विद्यालय समूह, जिनके बीच की दूरी सहजगम्य हो) बनाए जाएं ताकि सगम के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अपना एक छोटा समूह बना सकें जो प्रत्येक सम्बन्धों के आधार पर काम कर सकें और जो योजना तथा निदेशन सम्बन्धी विशेष क्षमताओं से सम्पन्न हों। प्रत्येक सगम में एक माध्यमिक विद्यालय का जिनके अंतर्गत निम्न पदान्तर्गत चार या पाँच उच्च प्राथमिक विद्यालय हों तथा प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदान्तर्गत चार या पाँच निम्न प्राथमिक विद्यालयों का बँट रहा। प्रत्येक सगम के लिए समस्त उच्च प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों की एक समिति होगी जो कि जिनके अध्यक्ष बँट्टीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हों। इसी तरह प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक इसी तरह की समिति होगी जो कि विद्यालय सगम के अंतर्गत सभी विद्यालयों में मासिक रूप से काम करेंगे तथा उन समितियों के माध्यम से उक्त विद्यालयों के अध्यापक अपना सभी सम्बन्धों के सुनियोजित विभाग के लिए उत्तरदायी होंगे।

77 विद्यालय सगम प्रसारणों के रूप से काम कर सकें इससे अधिक आवश्यक है कि यह पर्याप्त शक्तियों प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ—

(i) मूल्यांकन की अधिक अच्छी पद्धतियों का प्रारम्भ करने तथा छात्रों का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवास एक विद्यालय स्तर से दूसरे विद्यालय स्तर में प्रगति देने में सम्बन्धित विद्यार्थी का कार्य एवं देने के सम्बन्ध में विद्यालय सगम का एक इकाई समझा जाय।

(ii) सगम के अंतर्गत सभी विद्यालयों का समुच्च रूप में उपकरणों सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएँ दिया जाना सम्भव होना चाहिए। इनके अन्तर्गत एक प्राचर तथा एक जनरल भी सम्मिलित है जिन्हें एक विद्यालय में दूसरे विद्यालय में भेजा जा सके। इसी तरह प्रत्येक केन्द्र के उच्च विद्यालय में एक मुख्यस्थित प्रयोगशाला हो सकती है, जहाँ प्रयोग या छुट्टी के दिनों में सगम के आनुषंगिक प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की प्रयोग कार्य प्रपत्रों

प्रदर्शन के लिए लाया जा सके। केन्द्रीय उच्च विद्यालयों के अनगत अध्यापकों को छात्रों के निमित्त एक ऐसे परिमचरण पुस्तकानय की भी व्यवस्था की जा सकती है जिससे पुस्तकें पढोस के विद्यालयों को भेजी जा सकें। विशेष योग्यता प्राप्त अध्यापकों की संस्था का भी समा विद्यालयों द्वारा काम उठाया जा सकता है। उदाहरणार्थ प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक श्रम करना शिक्षा के लिए पृथक् पृथक् अध्यापकों का नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन ऐसे अध्यापकों को उच्च विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है, और यदि नियोजित रूप से व्यवस्था की जाय, तो यह सम्भव होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का पथ प्रदर्शन करने तथा उनके छात्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने में भी उनकी सेवाओं का काम उठाया जा सके।

(111) विद्यालय समय का यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए कि यह सामान्य अध्यापकों को नकारते शिक्षा देने तथा मुख्यतः कम योग्य अध्यापकों का अधिक योग्य बनाने का काम करें।

(112) समय के अनगत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मिल जुल कर विचार विमर्श द्वारा विकास सम्बन्धी मुख्य गिद्धानों का निष्पत्ति लेना चाहिए ताकि जिनके अनुसार प्रत्येक विद्यालय अपने स्वयं के कार्यक्रम की योजना बना सके।

(113) एक या दो अवकाश मारवाही अध्यापकों के केन्द्रीय उच्च विद्यालय से सम्बद्ध करना भी सम्भव हो सकेगा ताकि जब और जहाँ आवश्यकता हो, तो उन्हें समय के अनगत विद्यालयों में भेजा जा सके।

(114) महा पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक निर्देश पुस्तिकाएँ तथा शिक्षण मद्देश्य नामकी को परगने एवं उच्च मूल्यांकन करने में कुछ शुक्ति विद्यालय समयों का उपयोग किया जा सकता है।

(115) विद्यालय समय का यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह निर्धारित परिणामांशों में तथा जिन शिक्षा अधिकारियों की स्वीकृति से प्रचलित निर्धारित पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम में मगापन-परिचयन कर सके।

य समय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व प्रत्येक समय का गुरुत्व नहीं होने चाहिए। कुछ चीजें तो चाहीं तो मुश्किलों की जा सकती हैं तथा फिर उनका क्षय हो और उत्पत्ति के आधार पर उनका सोच गये उत्तरदायित्वों को बनाया-बढ़ाया जाना चाहिए।

78 स्पष्ट है कि इस वायव्य म स दोना ही विभाग तथा विद्यालय का नाम होगा। जिना शिक्षाधिकारी प्रत्यक्ष विद्यालय मगम म मुख्यतः सम्पन्न बनाए रखेगा तथा उक्त एव इकाई मानकर व्यवहार करेगा, उसके वह मुख्य मुख्य आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा और इस प्रकार विभाग का उच्च-स्तराव्य समय देने कम निरीक्षण अधिकारियों का नियुक्त करना पड़ेगा। अन्य विद्यालय भी अधिक शक्ति सम्पन्न होंगे क्योंकि एक अधिक लचीला प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

79 उक्त ही ममान वायव्य का विवर्तित करने के लिए महाविद्यालय का पदार्थ के उच्च विद्यालय स जाह दना 'नामप्र' रहगा। विश्वविद्यालय तथा विद्यालय का इस धान के लिए प्राप्ति किया जाना चाहिए कि व उच्च विद्यालय म स्तर सुधार वायव्य म महापता करने के दृष्टिकोण स प्रयोगशील गस्यामा का संचालन करें, उच्च विद्यालय के अध्यापकों का ग्यारह प्रतिशत दन की व्यवस्था करें पाठ्य पुस्तकें एक शिक्षण-सामग्री का निर्माण करें तथा प्रतिभा का पहिचान एक उमर विराम म महापता करें।

80 सम्बद्धता प्रमाण करने वाले प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय को उक्त आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालय म सुधार करने के विशेष प्रयत्न करने चाहिए। (मामा-यन्त्र एव विश्वविद्यालय पर 30 के अधिक महाविद्यालयों को सम्बद्ध करे का भार न पड़े)। सम्बद्धता के सम्बन्ध म निर्धारित शर्तों का समय-समय पर पुनर्विनिर्माण तथा उनका बहाल ग पालन करवाया जाना चाहिए। सम्बद्ध महाविद्यालय का अधिकृत सम्पूर्ण निरक्षण किया जाना चाहिए—कम से कम तीन साल म एक बार—क्योंकि सम्बद्धता का एक ऐसा विद्याधिकार समझा जाय जिसे प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील तथा योग्य बन रहना आवश्यक है। इस माय-माय ही प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय का सम्बद्ध महाविद्यालय को एक परिपक्व स्थापित करना चाहिए। इस परिपक्व का कार्य हागा विश्वविद्यालय का सम्बद्धता म सम्बन्धित समस्त मामलों पर सम्मति देना, यह सम्बन्ध म विश्वविद्यालय की नीति को लागू करने म गणना देना महाविद्यालय के उचित विराम म महापता के दृष्टि म उनका प्रतिष्ठ सम्बन्ध बनाय रखना तथा महाविद्यालय का स्तर निरन्तर उन्नत हो रहा है धमका नहीं—अगर पता लगान के लिए उनका आधिकारिक प्रोजेक्ट करता।

शैक्षिक अवसरों के विस्तार तथा समकरण सम्बन्धी समस्याएँ

५1 गतिबिधुनयना का कामरा प 1 है ममा स्तरा पर शशिन गुविषामा का विस्तार करवा जिम गतिबिधुनयनरा व समकरण पर विनेष यन न्दिया गया हा ।

५2 एग क्षत्र म मवप्रयम कायनम है शीनन नागरिक व शक्षिन स्तर म उन्नति करना तथा एग हठिकाण म प्राथमिक शिक्षा व दिए पयात माघन जुगाता तथा प्रोड निरक्षरता का समाप्त करना ।

83 प्राथमिक शिक्षा

भारताम गविषान व अनुच्छेद 17 म निवेश है कि 14 यष तन का छातु व ममा छातरा का नि गुन एक अनियाय गिरा दी जाय । यह बयन माया मे सम्बधि पन गही है इमम अच्छा गिरा का प्रावधान भा प्रचुनन रूप मे निमित्त है । निरक्षरता का विनाश मन्वा तथा उन पर ज्ञान वाल गव को ध्यान म रगत हुन एन लय का प्राप्ति निमित्त एक व्यावहारिक कायनम को 20 यषी ता प जाना हागा । समन बारका का 1977 76 तक पचयर्षीय तथा 19५७ ५6 तक मत्तर्षीय अन्ध तथा प्राथमिक शिक्षा दना हमार गन हुना चाहि ।

५1 मवस्थाता प्राथमिक शिक्षा व लय का प्राप्ति व तान परण है, जो मामाघनया परमर छाता है विद्यालय का मवस्थाता व्यवस्था मवस्थाता नागोदन तथा मवस्थाता प्रतिधारण ।

(1) अनुर्ष पचयर्षीय याचना का ममानि मव विद्यालय का मवस्थाता मवस्था कर ना जान चाहि । प्रत्येक कागव का घर म 1 मान को दूरा पर एन प्राथमिक विद्यालय तथा 1 म 3 मान व बाच का दूरा म एन उन प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध जाना चाहि ।

(11) मवस्थाता नागोदन अनु ना मुन कायनमा का छावयचना है ।

प्रथम पन्नी तथा म नामांकन सम्पूर्ण (एक समय नामांकन अधीन विषयस्थ है, क्योंकि इसमें पाँच वर्ष से कम की आयु से लेकर 14 वर्ष में ऊपर तक का आयु वाले बालक का प्रवेश दिया जाता रहा है) है तथा निर्धारित आयु वर्ग (5-6) के बालक का किसी अन्य वस्था में नहीं बल्कि पन्ना में ही नामांकित किये जाने का प्रयत्न है। दूसरा—अन्य प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर छात्रों द्वारा विद्यार्थ्य छोड़े जाने की प्रवृत्ति का समाप्त किया जाय (इस समय लगभग 20 प्रतिशत बालक अन्य प्राथमिक शिक्षा में भाग नहीं लेते) तथा ऐसा प्रयत्न है कि जो बालक इस स्तर की शिक्षा का समाप्त करने में बहुत अनिच्छा रखे स भाग के स्तर की शिक्षा का भी प्राप्त करें। इस प्रयत्न कायम का पूरा करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में बड़े हुए सुविचारित रूप में तथा मध्यम प्रयत्न किया जाय। दूसरे कार्यक्रम को पूरा करने में कुछ अधिक समय लगना।

(11) आवश्यक प्रतिधारण से तात्पर्य है कि शिक्षा में वृद्धि रोध तथा शय का परिणामात् करना तथा एक बाल में आवश्यकता जाना कि प्रत्येक नामांकित छात्र एक वर्ष में दूसरी वर्षा में नियमित रूप से उन्नति करता हुआ तब तक विद्यालय में अध्ययन करता है जब तक कि वह अनिवार्य पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर सके अथवा दूसरे वर्षा में वह सफल है कि प्राथमिक-स्तर की शिक्षा की प्रथमिक तान वर्ष का भीमन अवधि का सान वर्षों का सान अधिक तब बढ़ाया जाय। यह सर्वोपरि कठिन कार्य है और इसका निदान प्राथमिक मातृशिक्षा और शिक्षा है। प्रत्येक भीमन माता पिता प्राथमिक रूप से इनमें सम्मिलित हैं कि वे अपने बालक का बड़े होने तक विद्यालय में ही रखें वह माता पिता का भी स्तना शिक्षा दिया जाय कि वे अपने बालक के लिए शिक्षा के महत्त्व का समझ सकें तथा विद्यार्थ्या के मा उक्त गुणवत्तापूर्ण सुधारों सम्मिलित निम्नलिखित कार्यक्रम का आधार का अपने प्रति आवर्तित करने तथा शैक्षिक गति का समता का बढ़ावा जाय। इस कार्य में लगभग 75 हजार लक्ष मकन हैं।

8. शय तथा वृद्धि शय का समस्या प्राथमिक-स्तर पर बड़ी नयान है। पन्ना वर्षा में नामांकित 100 छात्रों में से केवल 10 छात्र वर्षा में तब पहुँचते हैं और वर्षा में लगभग 10 है। प्राथमिक स्तर पर कुल शय का लगभग आधा भाग भी पहुँचा वर्षा में ही घटित हो जाता है। अतएव एक समस्या पर विचार ध्यान देने का तथा इसका निदान के लिए निम्नलिखित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसका निदान निम्नलिखित उपायों द्वारा सम्भव है

पहली कक्षा (i) जो आगामा वय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उन ममस्त छात्रों के नामों का पूव पंजीकृत करने का व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इस पूव पंजीकरण वय में इन बालकों को गल-बन्दा व माध्यम व अनीपचारिक शिक्षण स्थि जान का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस विद्यालय में आकर पढ़ने की उनमें आत्न पड जायगी तथा इस प्रकार उह औपचारिक शिक्षण के लिए तयार किया जा सकेगा।

(ii) यद्यपि सामां तर उह विद्यालय पूव शिक्षा दी जानी चाहिए। हर स्थिति में पहली कक्षा में गेल पद्धति अपनायी जानी चाहिए।

(iii) पहला और दूसरी कक्षा में कोई थली विमाजन पद्धति नहीं हुना चाहिए और सम्भव हो ता पहली औरी कक्षा में मा थली विमाजन नहीं किया जाना चाहिए।

कक्षा 2 से 7—इस स्तर पर शय का मुख्य कारण धार्मिक है—बालक (विशेषतः बालिका) ज्या ही धार्मिक दृष्टि से सामकार्य बन जाता है और घर में प्रथमा बाहर कुछ काम करना या कामना प्रारम्भ कर दता है तो उन विद्यालय भेजना सम्भव कर लिया जाना है। अतः प्रथम बालिका (पाठ टाईम) व्यवस्था का यह पमान पर अपनाया जाना चाहिए ताकि बालक पढ़ें एवं और व्योसाजन भी कर सकें।

प्रथम प्रथम रूप से प्राथमिक ज्ञानाभा में वृद्धि राय तथा शय की स्थिति का मूल्यांकन तथा उतके कारणों पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित धार्मिक व्यवस्था का जानी चाहिए। मम विद्यालय का कमचारी वगैरह ममस्था के प्रति गजब हा जायगा तथा इससे शास्त्र निम्न हनु अपनाए गये जायगा व विद्यालय में गहायक सिद्ध होगा। नामांकन प्रथमा व्यय व्यवस्था माध्यम व विशयण के आधार पर इन सुराशय का कम करने के बाय वो प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण से, पथवर्षीय यात्रा के अन्तगत शय तथा वृद्धि राय का समाप्ति करने के लिए विविध लक्ष्य निर्धारित स्थि जान चाहिए तथा मम क्षेत्र में प्राथमिक प्रयत्नों का एक स्पष्ट एवं निश्चित स्थि निर्देश मा लिया जाना चाहिए।

५६ प्रौढ़ निरक्षरता का परिममाणन

प्रौढ़ निरक्षरता का परिममाणन करने के लिए एन 20 वर्षीय तमिक कार्यक्रम अपनाया जाना। आगामा दस वर्षों तक अनिवार्यता का मन्ता में और अधिक् वर्ष वृद्धि में जान गये के लिए 11 11 आयु वर्ग के उन बालक।

के लिए अश्वत्थिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, जिन्होंने अथवा प्राथमिक स्तर की शिक्षा का पूरा नहीं किया है तथा जो अब विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सामान्य साक्षरता अभियानों का चयनित तथा सामान्य भाषा पर गठित करना होगा। चयनित पद्धति के अंतर्गत प्रौढों के उन विशिष्ट समूहों के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए जिन्हें आसानी से पहचानना नियमित और साक्षर बनने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। बड़े दृष्टि फार्मों तथा व्यापारिक औद्योगिक, सार्वजनिक तथा ऐसी ही अन्य बड़ी संस्थाओं के मालिकों के लिए यह अनिवार्य (आवश्यक हो तो बाबूत द्वारा) किया जाना चाहिए कि वे अपने यहाँ काम करने वाले सभी निरक्षर व्यक्तियों का उनका नियुक्ति नियम से तत्काल वकील के माध्यम से काम चलाने योग्य साक्षर बना देंगे। सरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक संस्थानों का इस विभाग में सुरक्षा पटल बनानी चाहिए और इस प्रकार नवृत्त प्रदान करना चाहिए। अपने कामचारियों का और विगलित निरक्षरों की, शिक्षा की योजना तैयार करना प्रत्येक विकास-योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आरम्भ की गयी सभी सरकारी योजनाओं में साक्षरता कार्यक्रम को आवश्यक तत्त्व माना जाना चाहिए। सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत निरक्षरता से लड़ने के लिए देश के सभी उपरम्भ शिक्षित पुरुषों तथा महिलाओं की एक संस्था तैयार की जानी चाहिए तथा उनका सुनिश्चित साक्षरता अभियानों में सहायता लिया जाना चाहिए। इसमें सभी शिक्षक, दानों तथा भाग्य सम्पादकों का सक्रिय योग्य है। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक, व्यावसायिक विद्यालयों के छात्र तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अथवा स्नातक स्तर के छात्रों से अनिवार्य राष्ट्रीय-स्तर पर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढों का साक्षर बनाने का कार्य लिया जाना चाहिए। सभी प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों में भाग ले और निरक्षरों का साक्षर बनायें। प्रत्येक नागरिक संस्था को सामाजिक जीवन के बँट स्वरूप बना दिया जाना चाहिए तथा उसे उत्तरदायीता से जोड़ा जाना चाहिए कि वह उस बँट के गिरावट सामाजिक जीवन से निरक्षरता को परिमार्जन कर दे और उस बँट सम्पूर्ण उत्तरदायित्व को मोटा जाना चाहिए कि वह एक निश्चित क्षेत्र से निरक्षरता का परिमार्जन करे।

९७ शिक्षा तथा जन-बल सम्बन्धी आवश्यकताएँ

माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में नामांकन में भी भार

मापदण्डों के समुक्त रूप पर आधारित होनी चाहिए। जनता द्वारा एमी शिना का माँग, नसगिर याम्यना के मण्डार का सर्पारील विनास, वादित गुलात्मक स्तर। मे सम्बंधित धुनि सुविधाया का उपनय कराने की समाज की क्षमता, तथा जन-जन-सम्बन्धों का आवश्यकताएँ आवश्यकताओं पर आधारित नित्य सुविधाया का विस्तार करने का समाज की क्षमता से यदि शिना व पुनर्नम नय निर्धारित हान हैं तो जनता की माध्यमिक एवं उच्च शिना सम्बन्धी माँग प्रथम उपनय नसगिर याम्यना के मण्डार की विकसित करने की आवश्यकता से शिना व अधिकतम नय निर्धारित होने हैं। इन उच्च तथा निम्न लम्बा व घाव का दूरी या उस विचार विमर्श के द्वारा समाज के जा सकता है जो शक्ति व्यवस्था व परिणामों की जन वल का आवश्यकताओं में सम्बद्ध करने का आवश्यकता में उत्पन्न होता है। इसमें स्पष्ट हो जायेगा कि दिन प्राथमिकताओं का अभाव है, दिन विभिन्न पाठ्य क्रमा का विभाग करना है तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न सामा तब सुविधाया का उपनय कराना है।

५५ माध्यमिक एवं उच्च शिना व निमित्त शक्ति सुविधाया की व्यवस्था तथा जा वल का अनुमानित आवश्यकताओं व आपता सम्बंध स्थापित करने हेतु हम (उक्त) सिफारिश का कुछ सामान्य प्रवर्तन व माप ही समझा जाता चाहिए। जन वल के सम्बंध में का गया अविवेकवाणा कम ही विद्युत दीप्त होती है क्योंकि यह विभिन्न सम्भावनाओं पर आधारित होती है। अतएव यह आवश्यक है कि आवश्यकताओं का अनुमान करने की पद्धति तथा अविवेकवाणी करने की तकनीक में भी निरन्तर सुधार किया जाता रहे। क्योंकि एवं राज्य सरकारों का नम शिना व निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि जन वल सम्बन्धी अविवेकवाणा सामान्यतया सरकारों के अभाव में स्थापना में अर्थ का जाता है। अतएव नित्य सुविधाया का विस्तार का प्रथम सम्बन्ध सुविधाया उपनय कराने का ही मौलिक हो जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि वादित जन वल व गुलात्मक पक्ष पर वल दिया जाय क्योंकि उपनय गुलात्मक स्तर का न बनाय गया व प्राथमिक उपनय ही व अन्तर्गत उपनय उच्च पाया हो पड़ेगा है। और भी जन वल का आवश्यकताओं में सुविधाया का व्यवस्था का निर्धारण करने का एक मात्र कारण नहीं हो सकती। का भी अन्तर्गत शिना वल में पूरा जा वल की आवश्यकताओं व अर्थ का अन्तर्गत मापदण्डों व आधार पर विवेक मंद निरन्तर व विचार करके किया होगा।

साध्य' छात्रों का प्रयोग देना है और 'साध्य' छात्रों का बाहर निराल देना है । इस स्तर पर चयन 'परीक्षण और निर्देशन' की ओर अधिक और 'निरसन' की ओर कम उभरता है । इसका मुख्य प्रयोजन यह होना चाहिए कि कोई छात्र अपनी उपरान्त तथा क्षमताओं के स्तर से अवगत हो जाय तथा वह यह निष्कर्ष ले सके कि उसने लिए विद्यार्थी छात्रों के बाहरी दुनिया में वापस करना निरन्तर होगा या नहीं किसी विशेष आवश्यकता के पाठ्यक्रम में भाग लेना या सामान्य शिक्षा का प्राप्त करने रहना । दूसरे शब्दों में इस स्तर पर चयन का अर्थ होगा परीक्षण और निर्देशन सेवाओं की सहायता के माध्यम में 'प्रारम्भ चयन' । माध्यमिक शिक्षा के विस्तार का चाहे कोई भी स्तर हो, लेकिन छात्रों का यह सुविधा सभी क्षेत्रों के सभी विद्यार्थियों में उपलब्ध होना चाहिए । किसी विशिष्ट क्षेत्र में चयन पद्धति का बढोतरता में अपनाय जाने की आवश्यकता है या नहीं इसका निष्कर्ष स्थायी आधार पर उस क्षेत्र की जन-जन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा (स्थिति) विस्तार के प्राप्त स्तर की ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए ।

92 उचित चयन की प्रक्रिया उपरान्त माध्यमिक स्तर में प्रारम्भ होगी । उपरान्त माध्यमिक (अथवा दूसरे गमक) स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्थानों की उपलब्ध सुविधाओं की रणनीति में निश्चित किया जाना चाहिए और तब विद्यार्थी साध्य आवश्यकताओं में से अधिक प्रत्याशित का चयन करेंगे । यह वास्तव में उस सीमा तक गहन होगा जिस सीमा तक उपरान्त माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण किया जा सकता है तथा छात्रों को उस ओर प्रवृत्त किया गया है अथवा माध्यमिक स्तर की शिक्षा समाप्त व्यक्तियों को नीचे के जितने अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं उसका करीब हो जो करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया तथा स्वतन्त्र शिक्षा की सुविधाओं की सभी व्यवस्था की जाती है तथा सामान्य भाग में यह भावना करना कि शिक्षा काय प्राप्त का मापन है न कि स्वयं काय ?

93 अथवा स्नातक स्तर पर चयन-पद्धति की वहीं अधिक बढोतरता से अपनाया होगा । इन दृष्टिकोणों में निम्नलिखित प्रायश्चित्त का कार्य-विनियम करना होगा

(1) यह स्पष्ट में प्रारम्भ होना है कि उचित स्तर बनाए रखे जाय ? यह आवश्यक है कि महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विभाग के सम्बन्धित उपलब्ध शिक्षक-वर्गों की संख्या का उपलब्ध अध्यापकों की संख्या तथा प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्धारित किया जाना चाहिए ।

विज्ञान तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सभी तक गहन पद्धति माते

नीर पर अपनायी जाती है। वही तब वाणिज्य के पाठ्यक्रम में भी इस पद्धति को अपनाया जान की आवश्यकता है। महाविद्यालय अथवा विश्व-विद्यालय के किसी विभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण हर मिनट में यह विश्वविद्यालय का हो करना चाहिए।

(11) परीक्षा प्रणाली में सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम के एक अंग-स्वरूप यह प्रस्तावित किया गया है कि विद्यालय शिक्षा के राज्य बाड द्वारा पितरित विद्यालय त्याग प्रमाण में प्रत्यापी के सफल अथवा असफल होने का कोई निर्धारण न हो, अपितु छात्र न विभिन्न विषयों में जो उपलब्धि प्राप्त की है उसका स्पष्ट उल्लेख हो। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के सम्बन्ध में उन्हें निर्धारित करें। अतएव छात्रों का अपना परीक्षा पर सुधार हो पुनः परीक्षा देने करने का व्यवस्थापित किया जाना चाहिए।

(12) उत्तम सुविधाओं की तुलना में जहाँ आवश्यकता की सम्भावना कम है, वही सामान्यतया अपना-पद्धति नहीं अपनायी जायगी। परन्तु यदि उत्तम शिक्षा स्थानों में आवेष्टकों की सम्भावना अधिक है तो गरमा अथवा सम्बन्धित विभाग का चाहिए कि योग्य प्रवेशावियों में से वह सर्वोत्तम छात्रों का चयन करें।

(13) अब तो कि कोई अच्छी चयन पद्धति नहीं विनियमित हो। अपनी तब तो परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रकाश का मुख्य आधार स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु परीक्षा में प्राप्त अंकों की स्वच्छताधारिता तथा उनकी अविश्वसनीयता में छात्रों का ज्ञान वाली क्षमता की इस सम्बन्धी अल्प सम्भावना तथा छात्रों की आवेष्टक सामाजिक रूप में पिछड़ी अवस्था पर उचित दृष्टिकोण बरत कर, इस तरह पूरा किया जाना चाहिए कि प्रवेशावियों की नैतिक प्रतिभा की सहा रूप से पहचाना जा सके। अतएव रूप में चयन करने समय छात्रों को उन विद्यालय समितियों तथा उम्मीदों उन क्षेत्रों में प्रयोगिता चाहिए तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनकी परीक्षा में जीब नया हुई है। अतएव-सम्बन्ध विश्वविद्यालयों की यह व्यवस्था और उनमें यह साहस भी होना चाहिए कि वह निर्धारित नियमों का निरन्तर रखें उन छात्रों का प्रवेश न करें जिनका प्रतिभा की पहचान तो करती नहीं है किन्तु जो प्रकाशनों की पूरा नहीं करत है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के निमित्त विद्यालय गुच्छ (School Clusters) के आधार पर छात्रों का पर्यवेक्षण करने की प्रस्तावित शिक्षा विधि का सुलभता सरलता में छात्रों का चयन करने के आधार

पर प्रयुक्त किया जा सकता है।

(८) प्रत्येक विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय प्रवेश बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए, जो प्रवेश से सम्बंधित सभी मामलों पर उसे सम्मति दे।

(९) उच्च शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में (प्रवेश सम्बंधी) उचित ध्यान पढ़ाने में उचित विकास करने के दृष्टिकोण से एक केन्द्रीय परीक्षण मण्डल स्थापित किया जाना चाहिए।

७४ स्नातकोत्तर स्तर पर ध्यान सर्वाधिक कठोरतापूर्वक करने होंगे, क्योंकि इस स्तर पर शिक्षा के स्तर का बनाये रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह यह क्षेत्र है जहाँ बीजारापण होता है तथा जो सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र की नष्ट भी कर सकता है उसका गुणार भी कर सकता है। उन्नाहरणाथ इस स्तर पर स्तरावनति हानि में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक प्राप्त करना दुर्लभ हो जायगा। इसमें विश्वविद्यालय-स्तर पर स्तरावनति होगी तथा परिणामस्वरूप माध्यमिक विद्यालयों के लिए अच्छे शिक्षक प्राप्त होना कठिन हो जायगा। परिणामतः माध्यमिक शिक्षा में स्तरावनति होगी और प्राथमिक विद्यालयों में लिए अच्छे शिक्षक मिलना कठिन हो जायगा। इस दुष्परिणाम का समाप्त करने का एक ही उपाय है कि स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के गुणारमय स्तर में गुणार दिया जाय। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कृषि विभाग उत्पादन जन प्रशासन तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकें।

७५ अन्तराष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वाध्याय

एक मात्र गुणराशित्व शिक्षा पर ही निर्भर रहने की वर्तमान नीति का निराकरण करने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक स्तर पर अन्तराष्ट्रिय तथा स्वराश्रित (Own time) शिक्षा को विनाश पमाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा गुणराशित्व शिक्षा के समान ही इन दोनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरे, इस समय ग्रीक तथा अन्तराष्ट्रिय शिक्षा प्रायः गुणराशित्व उन्नीत है। नतीजा हर सम्भव स्तर तक विस्तार दिया जाना चाहिए। इस द्वारा में एक मात्र गुणार करने का परिणाम यह होगा कि

—किसी शिक्षा के किसी स्तर को पूरा नहीं किया है वे उते पूरा कर लेंगे तथा यदि वे चाहें तो धन के स्तर की शिक्षा में प्रवेश कर लेंगे

—प्रत्येक शिक्षा के शिक्षा शिक्षा शिक्षा में करना सामान्य

कराकर अथवा बिना नामावन कराये भागे की शिता प्राप्त कर सकेगा,

—बाई भी वायवर्त्ता वायव्यता, क्षमता, ज्ञान तथा ध्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार एक कुशल वायवर्त्ता बनकर वह अधिक आम सम्द-धी अधिक अवसरों को प्राप्त कर सकेगा और

—शक्ति व्यक्ति अपने ज्ञान को सजीव बनाय रख सकेगा । परिणाम स्वरूप अपनी रुचि के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान के साथ वह कदम-मिन्नकर चल सकेगा ।

इस प्रकार के वायव्यता को जब शक्ति रूप से उन्नत तथा सम्पन्न दशा में भी विवर्धित किया जा रहा है तो मारत जैसे अछ विरहित तथा तरीय दश में तो विलुप्त हो उपेक्षित नहीं किया जा सकता । इन वायव्यता का वादायित करने का परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी के बाद जीवन में प्रवेश करना सरल हो जाएगा, राज्य पर होने वाले शिता के व्यय में 'यूनता' का जायेगी तथा शिता व्ययस्था में प्रभावित होकर बहुत बड़ी सम्पदा में व लाग शिता प्राप्त कर सकेंगे जो अधिक महत् के कारण निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, जिन का स्वयं को निश्चित करना चाहते हैं ।

96 पत्राचार पालक्यमा के विचार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, न केवल विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए, अपितु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों अध्यापकों, कृषि में उद्योगों में काम करने वाले तथा अन्य वायव्यतामा एवं अन्य कारिका के लिए भी जो सांस्कृतिक एवं मौखिक-सांस्कृतिक सूचना से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन के माध्यम में अपना जीवन सम्पन्न बनाना चाहते हैं । जो छात्र पत्राचार पालक्यमा को ग्रहण करें, उन्हें अध्यापकों से यत्न-श्रद्धा मिलने के अवसर दिए जान चाहिए उन्हें साथ छात्रों की तरह ही समझा जाना चाहिए और जहाँ सम्भव हो उन्हें कुछ महाविद्यालयों में सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए, ताकि वे गृहस्थानों एवं अन्य मुविषाया का लाभ उठा सकें ।

97 विभिन्न स्तरों पर नामावन

आगामा 20 वर्षों में नामावन की समस्या एवं स्तर अथवा क्षेत्र से दूसरे स्तर तथा शायद ही नहीं, अपितु एक ही स्तर अथवा क्षेत्र में स्थान पर भी विद्यमान रहेंगे । मई 1950 से 1965 तक के (वास्तविक) तथा 1966 से 1975 तक के (वास्तविक) नामावन के आँकड़े परिशिष्ट—१ में दिए गये हैं ।

(i) निम्न प्राथमिक स्तर पर प्रवेशाधिया की संख्या सन् 1950 में 1 करोड़ 10 लाख से बढ़कर, 1960 में 3 करोड़ 70 लाख हो गयी इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि 19 प्रतिशत से बढ़कर तृतीय योजना में 8.2 प्रतिशत हो गयी। इस क्षेत्र में अब हम सतृप्ति बिन्दु तक पहुँचने वाले हैं। छात्र ही समाज वालन विद्यालयों में भर्ती कर लिए जायेंगे तथा भर्ती में हान वाली भागामी वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा शिक्षा में हान वालन क्षेत्र का काम पर निम्न करगी। जनसंख्या में प्रवेश-संख्या में हान वाली भागी वृद्धि की दर भर्ती की तुलना में बड़ी अधिक कम होगा। तथ्य तो यह है कि जब जन्म-दर घटने लगगी और शिक्षा में क्षय कम हान लगगी तो प्रवेश संख्या वस्तुतः घटने आरम्भ हो जायगा। सन् 1985 तक जन्म दर पर प्रवेशाधिया की संख्या लगभग 7 करोड़ 60 लाख हो जायगी अर्थात् 20 वर्षों में दुगुनी हो जायगी। यह काम मद्रास अथवा केरल जैसे राज्यों में तो सरलतापूर्वक निम्न जायगा क्योंकि वहाँ पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है। मध्य प्रदेश अथवा राजस्थान जैसे राज्यों में यह काम बहुत ही कठिन है। अब मुख्य समस्या तो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न वर्ग जातियाँ मुख्यतः जनजातियाँ में ही आत्मिकता का विकास का भर्ती करने का है।

(ii) उच्च प्राथमिक स्तर पर भी 10 वर्षों में प्रवेशाधिया की संख्या लगभग चौगुनी हो गया है—1950 में लगभग 30 लाख से बढ़कर यह संख्या 1960 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। भागामी 2 दशकों में विस्तार का परिणाम इसी का समान होगा अर्थात् प्रवेश-संख्या में चौगुनी वृद्धि करनी होगा, अर्थात् 1960 में एक करोड़ 20 लाख से बढ़कर यह संख्या 1980 में 1 करोड़ 80 लाख हो जायगी। जिनमें अथवा केरल जहाँ कुछ निम्न क्षेत्रों का दृष्टिकोण भी यह काम बहुत ही कठिन हो रहा है। विधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों का अनुपातन करने के दृष्टिकोण में वस्तुतः यह एक मात्र नाजक क्षेत्र है। जहाँ कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि अनिवार्य परिवारों का आत्मता का सिद्धि करने के लिए सामाजिक शिक्षा का विधान समान पर ध्यान देना होगा। 1980 तक जन्म प्रवेशाधिया की संख्या कुछ संख्या का 20 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है।

(iii) निम्न माध्यमिक स्तर पर भी स्थिति है, जहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर है। अब 15 वर्षों में प्रवेशाधिया की संख्या चौगुनी हो

गयी है—19०0 में 1 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 1965 में यह संख्या 6 करोड़ 10 लाख हो गयी है और सम्भावना है कि इस संख्या में 198० तक 2 करोड़ 40 लाख की और वृद्धि हो जायेगी। इस समय विकास प्रसमान है। स्थानांतरण आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ प्रयत्न करने हैं।

इस स्तर पर दो मुख्य कार्यक्रमों पर विशेष बल देना होगा—प्रथम है, एक विशाल पैमाने पर प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था। इस समय शायद ही कोई प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन 198० तक कुल प्रशिक्षणियों की संख्या में लगभग 20% छात्रों की प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था की जाना चाहिए। दूसरा कार्यक्रम यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश-संख्या में वृद्धि की जाय। इस समय इस क्षेत्र में प्रवेश-संख्या बहुत कम है। वास्तविकता तो यह है कि 19०0 में कुल प्रवेशियों की 3 1% से घटकर यह संख्या 196० में 27 प्रतिशत रह गयी है। अतएव 196० में प्रवेशियों की यह संख्या 1 लाख से बढ़कर 198० तक लगभग 4 करोड़ 80 लाख करनी होगी अर्थात् कुल प्रवेशियों का 20%।

(ii) गण 1० वर्षों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेशियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई है। यह संख्या वर्ष 19०0 में 2,82,000 थी और 196० में 10 लाख 10 हजार। विकास की यही गति आगामी दो दशकों तक तीव्र रहेगी और 198० तक प्रवेशियों की संख्या बढ़कर 70 लाख हो जायेगी। यह मुख्यतः इस प्रस्ताव के कारण है कि देश में समान भाषा में इस स्तर की शिक्षा की अवधि समान रूप से 2 वर्ष और बढ़ा दी जाय। इस समय यह अवधि करीब और उत्तर प्रदेश में ही दो वर्ष है। यदि प्रवेश के समय अनिवार्य पढ़ाई नहीं अपनाया जाती तो प्रवेशियों की संख्या इस समय 40% है इसमें 50% तक का वृद्धि की जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण शिक्षा की सुविधाओं का (जो इस समय प्रायः नगण्य है) अधिक उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि कुल प्रवेशियों की संख्या का लगभग 2०, प्रशिक्षण शिक्षा का ग्रहण कर सके।

(iii) स्नातकस्तर स्तर पर 19०0 में प्रवेशियों की संख्या 2 लाख 1० हजार थी, जो 1965 में बढ़कर 10 लाख हो गया है तथा आगामी दो दशकों में 1985 तक यह संख्या 30 लाख हो जायेगी। यदि प्रवेश में अनिवार्य पढ़ाई की नहीं अपनाया जाता तो 1985 तक इस संख्या में दुगुनी

वृद्धि भी हो सकती है। कुन प्रवेशार्थियों के लगभग 30% छात्रों के निमित्त शैक्षणिक शिक्षा सुविधाओं को जुटाया जाय। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले कुन प्रवेशार्थियों की समस्या की लगभग एक तिहाई समस्या तब बढ़ाना होगा।

(५) स्नातकोत्तर-स्तर पर सुविधाओं में बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता है। 19७0 में यह मर्यादा 19 हजार थी और 196७ में 1 लाख 8 हजार। 198७ तक यह मर्यादा और अधिक बढ़कर 9 लाख 60 हजार हो जायेगी। यह इसलिए बताया जा रहा है कि अगर माध्यमिक स्तर के छात्रों में से कुछ निश्चित छात्रों तथा छात्रों के प्रतिभाओं को स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में विशाल पैमाने पर हानि वाला विस्तार होगा तब तक उपर दिया जा चुका है कि परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान सम्बन्धी माध्यमों पर लगे जाने छात्रों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी। साथ ही उद्योग तथा नौकरियां में विकास के निमित्त भी तेजी से व्यक्ति का बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता होगी।

शिक्षा व्ययों का अनुमान 19७0 में 2 करोड़ 10 लाख व्यक्ति प्रवेश या घुसे थे अर्थात् कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत में कुछ बाधा कम, 1965 में यह संख्या बढ़कर 7 करोड़ हो गया है अर्थात् कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत। बताया भी जा रहा है कि 19७5 तक यह संख्या में और वृद्धि होगी तथा यह 17 करोड़ हो जायेगा अर्थात् कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत।

७८ शिक्षा तथा सेवायुक्ति

प्रधान शिक्षा व्ययों का अनुमान शिक्षा तथा सेवायुक्ति (एम्प्लॉयमेंट) में कोई भी गंभीर संकट नहीं है और न ही उनमें शिक्षा-व्ययों के परिणामों का अनुमान का आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमानित करने का प्रयत्न किया गया है। ऊपर का अनुमान का क्या है उसमें शिक्षा और सेवायुक्ति में कम से कम निश्चित अंतर का संकट तो स्थापित करने में महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यह भी बताया है कि इनमें शिक्षा में गंभीर संकट स्थापित करने तथा एक एकीकरण का निर्माण करने की शिक्षा में प्रयत्न किए जाएं और गांधीय विचारों में ही शिक्षा अनुमानों को ही कोई स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेता है उस स्नातक उपाधि-पत्र के माध्यम से सेवायुक्ति का प्रवेश भी दिया जाता है। इनके अन्तर्गत का व्यवस्थापन में सुधार होगा उनमें शिक्षा माहिर हो

जायगा तथा वे अनुभव करने लगेंगे कि देश को उनकी आवश्यकता है और यह उनकी प्रीति का कारण रहा है।

99 इस समस्या का सतत्प्रयत्न निम्न एकात्मिक ढंग से नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को न केवल तीन दिशाओं में अभियान चलाकर करना पड़ेगा बल्कि जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा तथा आर्थिक विकास। जन्म की दर को कम करने के लिए इस समय अधिक प्रसिद्ध (Cohort) की समस्या नहीं आती है (अर्थात् जो बालक जातिवाले 16 या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेते हैं वे इस वय में अधिक बन जाते हैं)। कुल जनसंख्या की 2 प्रतिशत समस्या अधिक बन जाती है। इसी स्थिति में जन्म उपनियमों को लागू होना ही है अर्थात् 60 प्रतिशत अधिक अभिवृद्धि रह जायेगी तथा केवल लगभग 40 प्रतिशत आर्थिक शिक्षा को समाप्त कर पायेंगे। इस 40 प्रतिशत में से लगभग लगभग 25 प्रतिशत 5 वय में अधिक अवधि तक विद्यालय में पढ़ पायेंगे, लगभग 8 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर चुके होंगे तथा केवल लगभग 1 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। इसका तात्पर्य है आर्थिक विकास की गति विफल होगी क्योंकि हमें इतनी धन की जरूरत है कि इस प्रसंग में आर्थिक विकास के लिए भी पर्याप्त नौकरियाँ नहीं होंगी। यदि इस स्थिति में सुधार करना है, तो यह परमावश्यक है कि निम्नलिखित प्रयासों को लेकर विकास की एक एकीकृत योजना का निर्माण किया जाय

—10 प्रथम 15 वर्षीय मुक्तिवाजित कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म-दर घटाना,

—आर्थिक विकास की तीव्रता से इस तरह पूरा करना कि प्रत्येक ऐसे युवक अपना ऐसी युवती के लिए नौकरी की व्यवस्था हो जो अधिक बनना चाहते हैं और

—युवक बालक तथा बालिकाओं का ऐसी शिक्षा प्रदान करना कि निश्चित रूप से करते हुए वे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में प्रभावशाली ढंग से योग दे सकें।

ऐसी योजनाओं की राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर आवश्यकता है। इन योजनाओं का निर्माण तथा इनको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय राज्य और स्थानीय सरकार का है। शिक्षा तथा सेवायुक्ति की समस्या का ऐसा विनाश योजनाओं के परिश्रेष्ठ में ही समझाया जा सकता है।

100 शिक्षा अवसरों का समन्वय

शिक्षा के महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि

शिक्षा अवसरों का हम तरह भवतरण किया जाय कि विद्ये हुए अवस्था सुविधाओं से वचित जातिवा के व्यक्ति शिक्षा के सहयोग से अपनी अवस्था को सुधार सकें। शिक्षा अवसरों का सम्पूर्ण समतरण सम्भवतया असाध्य है। अतः समस्या की जड़ यह है कि उन तथ्यों की मात्र निराकरण के सतत् प्रयत्न किए जाएं जो अमान्यता के विभिन्न स्था की जन्म देने की ओर प्रवृत्त हैं और ऐसे उपायों को अपनाने के प्रयत्न भी किए जाएं कि यदि इन बाधक तथ्यों की पूरी तरह से समाप्ति नहीं किया जा सके तो कम से कम उन्हें न्यूनतम तो कर दिया जाय। इस दृष्टिकोण से निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति, अंगणवाडी की शिक्षा देश के विभिन्न भागों में शक्ति विकास में, असतुनन में वसी तथा लड़कियों की शिक्षा अनुसूचित जातियां तथा परितणित जातियां से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विरगिन करना होगा।

101 निःशुल्क शिक्षा

हम को हम शिक्षा में प्रयत्न करना चाहिए कि सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो सके। अनुसूचित जाति के अतः सब प्राथमिक शिक्षा तथा पोषणी योजना के अंतर्गत अतः माध्यमिक शिक्षा का शिक्षण निःशुल्क हो सके कर दिया जाना चाहिए। इससे साथ साथ ही उच्चतर माध्यमिक तथा विज्ञान विद्यालय शिक्षा के साथ एक जम्मेदार छात्रों का निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए तथा यह है कि कुल प्रयत्न मन्त्रालय के 20 प्रतिशत छात्र निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकें।

102 पाठ्य पुस्तक तथा लगन सामग्री का निःशुल्क वितरण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ (त्रिन्तम विद्यालय समय में मिलने वाला भोजन भी सम्मिलित है) भी निःशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत माना जानी चाहिए। हरमन्त्र प्रयत्न किया जाना चाहिए कि पाठ्य-पुस्तक का मूल्य बहुत कम हो तथा अमा निःशुल्क हो। निःशुल्क किया जा चुका है मन्त्रालय छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था है तथा उनमें गुणवत्ता पर मन्त्रालय सुधार कार्यक्रम का सर्वोच्च ध्यान दे जाय। अतः अमा कार्यक्रम का—विद्यालय चिकित्सा सेवाएँ तथा विद्यालय द्वारा दिया जाने वाला भोजन भी—यथा यथा माध्यम उपलब्ध हो विश्वास किया जाना चाहिए।

103 छात्रवृत्तियाँ तथा छात्र-सहायता के अन्य प्रकार

छात्रवृत्ति तथा छात्र-सहायता के अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का निम्न निम्न प्रकार का विवरण दिया जाना चाहिए

(1) शिक्षा के विभिन्न स्तर पर छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ, कुल प्रवेश सख्या के अनुपात में उनकी सख्या लगभग निम्नलिखित प्रकार से हो

स्तर	कुल प्रवेशार्थियों के अनुपात में दो जाने वाली छात्रवृत्तियाँ	
	1975-76	1985-86
उच्च प्राथमिक	25	500
माध्यमिक (सामान्य)	500	1000
माध्यमिक (व्यावसायिक)	3000	5000
अपर स्नातक (कला एवं वाणिज्य)	1500	2500
अपर स्नातक (विज्ञान तथा व्यावसायिक)	3000	5000
स्नातकोत्तर	2500	5000

(ii) उच्च शिक्षा में तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हानी चाहिएँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति तथा ऋणा छात्रवृत्ति।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में विस्तार की आवश्यकता है तथा छात्रवृत्तियों का प्रापण एवं उनका शोधता से चुकारा करने के लिए इसमें प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिए। इन्हें अधिक में अधिक समतामूलक बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी छात्रवृत्तियाँ राज्य स्तर पर उन्नी तरह प्रदान की जानी चाहिएँ जिन तरह सभी प्रदान की जा रही हैं और गैर छात्रवृत्तियों का विद्यार्थी पुञ्ज (School Cluster) के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। अर्थात् छात्रों के सामाजिक एवं आर्थिक आधार में समानता के दृष्टिकोण से एक जस विद्यालय का एक पुञ्ज बनाया जाय तथा प्रत्येक विद्यालय पुञ्ज के श्रेष्ठतम छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिएँ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के पूरक स्वरूप में विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियाँ तथा ऋण छात्रवृत्तियाँ का कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। ऋण छात्रवृत्तियों की व्यवस्था राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए और इसे विज्ञान तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सेवायुक्ति एवं आय की अपेक्षाकृत अच्छी सम्भावनाएँ हैं। यदि कोई छात्र राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति प्राप्त करता है और गतिसंचालन अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश करता है, तो प्रति सेवा-वर्ष में ऋण का दायरा भी हमारा के लिए समूल करने में सहाय किया जाना चाहिए।

(iii) शिक्षा में अध्यापन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा-सम्पन्न छात्रों का छात्रवृत्ति दा मे सम्मर्पित एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम हाना चाहिए तथा लगभग

500 छात्रवृत्तियाँ प्रतिगण वितरित की जानी चाहिए ।

(11) छात्रवृत्ति का राशि इतनी होना चाहिए कि उससे ममी मर पूर हो जाए जग सुपरिवार रहने वाले छात्रा का शिक्षण-शुल्क तथा भ्रम निजी सब्जे, जमे पुस्तके आदि । जिन छात्रा का छात्रावासा म रहना पडे उह छात्रा एव भाजन-भार्याधी व्यय का बहन करन क लिए अतिरिक्त राशि ही जानी चाहिए ।

(४) सर्वोत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो सके गति लिए छात्रवृत्ति वायकर्म में इन दो अर्थ वायकर्मों का भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक स्तर पर अष्ट मस्यामा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था

(घ) एक एते वायव्ये वा विरामे जिमन अतगत छात्रवृत्ति प्राप्ति छात्र इन श्रेष्ठ गत्यामा न प्रवेश न करें ।

(११) उच्च शिक्षा व क्षत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करने का अधिनियम उत्तराखण्ड सरकार को बहल करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर यह उत्तराखण्ड राज्य सरकारों को बहल करना चाहिए जिन्हें भागामी दम क्यों तब अपने मम उद्देश्य में एक कदम पर यह संचालित कार्यक्रम में माध्यम में सहायता दी जानी चाहिए।

(११) छात्रों का सहायता देने सम्बन्धी अन्य तराफों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे अत्यन्त मानासिकता का सुविधाएँ छात्रायाम के रूप में कभी छात्रवृत्तियों विषय अध्ययन केन्द्रों का व्यवस्था और आयाम कृते तथा उपायन करने हुए मीमने का सुविधाएँ का भा सम्मिलित कर सके ।

101 घपग यात्रों के लिए निदा

एक लाख में एक उर्वरक काय हाता कि 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप
 तथा प्रत्यक्ष बाजार तथा मगन 5 प्रतिशत मानविर रूप में प्रविष्टि
 बाजार का 1946 पर निम्न नीचे की व्यवस्था का जाय । एकर माय-माय
 प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रविष्टि हटिवाए हटिवाए बाजार मानविर प्रत्यक्ष म
 प्रविष्टि तथा मानविर रूप में प्रत्यक्ष बाजार का निम्न के निम्न मा माग-माग
 प्रत्यक्ष (Services on Pilot Basis) का प्रविष्टि प्रिया जाय । प्रत्यक्ष
 प्रत्यक्ष का निम्न के निम्न प्रत्यक्ष म प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष प्रविष्टि तथा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष

का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत अथवा अलग अलग नियमित निदानया में अध्ययन कर सकें। इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण आधुनिक तथा विभिन्न अभिकरणों में तात्कालिक स्थापित करने की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

105 क्षेत्रीय असंतुलन

असंतुलन विकास की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में बहुत बड़ा अंतर है और जितना-जितना पर तात्कालिक अंतर और घटित होना है। इस असमानता का न समूहान में मिटा देना सम्भव हो और न वांछित है। फिर भी एक संतुलन कारा घटक (Balancing Factor) को आवश्यकता है अथवा सुनिश्चित एवं दोषपूर्ण प्रयत्न द्वारा कम विकसित क्षेत्रों का सहायन की जाय ताकि वे कम से कम एक निश्चित स्तर पर प्राप्त कर सकें जितना उनमें और अधिक विकसित क्षेत्रों में अधिक बढ़ी सीढ़ी न रहे। इस हेतु शिक्षा आयोगों तथा विभागों के निमित्त जिलों को मूल इकाई माना जाना चाहिए। एन ही राज्य के विभिन्न जिलों में शक्ति विकास के स्तर को समान करने के लिए सुनिश्चित एवं तेजोई नीति अपनाया जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में शक्ति विकास के स्तर में समानता लाने के लिए भारत सरकार का प्रयत्न करना चाहिए।

106 बालिकाओं की शिक्षा

यद्यपि गत कुछ वर्षों में बालिकाओं की शिक्षा वास्तव में शिक्षा की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रही है फिर भी उनमें बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरणार्थ 1965-66 में प्रत्येक नामांकित 100 बालिका के पौष्ट बालिकाओं का संख्या का प्रसार भी निम्न प्राथमिक स्तर पर 35 प्राथमिक स्तर पर 30, माध्यमिक स्तर पर 26 विश्वविद्यालय स्तर पर 23 तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (महाविद्यालय स्तर) में 14। प्राथमिक स्तर पर एक अंतर को समाप्त करने तथा अन्य स्तरों पर इसे कम करने का आवश्यकता है। महिला शिक्षा का राष्ट्रीय समिति ने जताया कि सिफारिशें की हैं महिला शिक्षा पर प्राणिकी कुछ वर्षों में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाया जाना चाहिए। दोना ही अंतर और राज्य में बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा को समान करने के लिए एक विविध योजनाओं को लागू।

107 जहाँ जनता की माँग हो और प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव हो, वहाँ माध्यमिक तथा श्रवण स्नातक स्तर की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था अलास की जाय। कक्षा मानवीय विषयों विज्ञान तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में छात्राओं को प्रवेश का उचित सुविधा हो। इससे अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राओं का उनके विशेष रुचि, जैसे गृहविज्ञान उपन्यास शिक्षा सामाजिक कार्य भ्रमण व्यापार प्रशासन तथा व्यवस्था आदि पाठ्यक्रमों का उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

108 शिक्षित महिलाओं को रोजगार दिलाने की मुख्य समस्या पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह की आयु सीमा में निरंतर वृद्धि होती रहने के कारण लगभग सभी अविवाहित एवं वय प्राप्त महिलाओं के लिए पूर्णकालिक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। ज्यों ज्यों परिवार नियोजन बढ़ता जा रहा है उन अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर जुटाने होंगे, जिनके बालक बड़े होते जा रहे हैं। शिक्षित महिला शक्ति (Woman Power) का उपयोग उठाया जाकर उनके लिए उचित माध्यम विकसित करने का साथ साथ अवसरों का रोजगार के अवसर सृजित किया जाना होगा ताकि महिलाएँ अपने घरों का दायजाल भी कर सकें और बाहर के बाहर व्यवसाय भी अपना सकें।

109 शिक्षा के हर स्तर तथा हर क्षेत्र में अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें अवसरों का रोजगार के अवसर भी बढ़ाया जाय। समस्या में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रमाणित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, अध्यापिकाओं का आवंटित करने हेतु प्रौढ महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार देना होगा तथा सामान्य अक्षांशों में अवसरों का आवंटन भी किया जाय।

110 पिछड़ी जातियों की शिक्षा

पिछड़ी जातियों का शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है। अब आवश्यकता यह है कि प्रशिक्षित जाति विकास के कार्यक्रमों का बहुत अधिक सीमा तक विस्तार किया जाय जिससे अक्षरज्ञ रोजगार के अधिकारियों के अवसर उपलब्ध कराने तथा सामाजिक धर्मार्थ के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करने पर काम किया जाय। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों में शिक्षा के विस्तार में जो आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ हैं उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत ही एकाग्र हावर प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर सुविधाएँ जुटानी होंगी तथा दूर-दूर बसे शाना में प्राथम विद्यालय खोलने होंगे। अध्यापक वहाँ की जनजातीय भाषा का अनिवार्य रूप से जानकार होना चाहिए। प्रथम दो वर्षों की विद्यालयी शिक्षा का माध्यम जनजाति भाषा होना चाहिए तथा इस काल में बच्चा का क्षेत्रीय भाषा में प्रौढता सिखा दी जाना चाहिए। तृतीय वर्ष में क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। विद्यालय में वाचक वहाँ की वातावरण एवं जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर विद्यालया, छात्रावास-सम्बन्धी सुविधाएँ तथा छात्रवृत्तियों में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी। उच्च शिक्षा में क्षेत्र में छात्रवृत्ति वाचक से सम्बन्धित प्रशासन की विवेचित करना होगा और उस अधिक कुशलतापूर्वक चलाना होगा। दोनों ही माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर विषय अध्यापन का व्यवस्था करना होगा।

जनजातियों की सेवा में अपने का समर्पित कर सकने वाले साधन की संख्या में वृद्धि करना परमावश्यक है। आरम्भिक अवस्था में तो इनमें से अधिकांश लोग जनजातियों के बाहर से होंगे, परन्तु प्रयत्न करना होगा कि स्वयं जनजातियों में से ही ऐसे व्यक्ति तैयार हों।

कुछ विशेष कार्यक्रम

111 सभा स्तरा वा व सत्री क्षेत्रा वा शिगा ने सम्बन्धित उक्त मामाय वायत्रमा व माय साय यह भी आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न क्षेत्रों में बुद्ध विशेष कार्यक्रम विरहित किए जायें ताकि देश के लिए आवश्यक शिगा व मूलभूत स्थापनाएं पूरा किया जा सकें। इनमें सम्मिलित हैं

—माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (वॉकिंगनाइजेशन)

—उन्नत माध्यमिक के बाद तथा मुख्य विश्वविद्यालय सम्पूर्ण विश्व विद्यालय व्यवस्था का सुगठन करना,

—विशाल तथा सार्वजनिक (जिगम न्यायिक तथा कृषि विज्ञानिकों की शिगा भी सम्मिलित है)

—भक्ति कौशल का पुनगठन,

—प्रौढ़ शिगा

—युव प्राथमिक शिगा,

—भक्ति मयन मोर,

—नैतिक शाप ।

इनमें विषय में आगे व पृष्ठों में विवरण दिया गया है ।

112 माध्यमिक शिगा का व्यावसायीकरण

संशोधित महत्त्वपूर्ण धारणाएं वायत्रमा में एक तो यह कि माध्यमिक शिगा का व्यावसायीकरण किया जाय—तब यह है कि 1986 तक विभिन्न माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत स्तरों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा सके । तथा सुनिश्चित हो कि देश का आवश्यकताओं में सम्बन्ध करता होगा । यह प्रश्न व्यावसायिकता क्या है कि कमपारी क्या है तथा कक्षात्मकता की ही शिगा प्राप्त है की तो वह सम्बन्धी वायत्रमाओं का हर क्षेत्र में अपना अपना अनुमान लगा । के लिए हस्तापूर्वक धारणा दिया जाय । अब हम सम्बन्धी धारणाओं व सम्बन्ध में नविनशाली करने में पूर्व धारणा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण व निष्पत्तियों की स्थापना यह

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन तथा चलेमान में चल रहे कार्यक्रमों में बाधित सुधार और प्राप्त सुविधाओं का विस्तार आदि सभी बातों का जन-मन सम्बन्धी आवश्यकताओं के विषय में मनीष्यवाणी करके समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

113 इस स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम कई क्षत्रों से सम्बन्धित हों। जहाँ कृषि उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य, विविधता तथा जन स्वास्थ्य गृह-व्यवस्था कला तथा हस्तकला सांख्यिक तथा राजगार का सुविधाएँ उपलब्ध कराना होना चाहिए। इन पाठ्य क्षत्रों में राजगार का समता बना कर देना भी होना चाहिए। इन पाठ्य राजगार में लगजान की क्षमता बना कर देना भी होना चाहिए। इन पाठ्य क्रमों का एक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी चाहिए जो विभिन्न स्तरों की सामान्य शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उदाहरणार्थ जो प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को पूरा करने से पहले ही विद्यालय छोड़ चुके हैं। इनका संगठन बहुत लचीला होना चाहिए। शिक्षा (Apprenticeship) आवाजिक, डेरिलीज पत्राचार तथा सन्निहित समय पाठ्यक्रमों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। शक्ति सत्यापन (सामान्य तथा व्यावसायिक) सुगमता काम तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान विभिन्न सत्यापन अथवा इन सबके सम्मिलित प्रयत्नों के माध्यम से उच्च पाठ्यक्रमों का विविधित किया जाना चाहिए।

114 कृषि शिक्षा

प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक स्तर पर कृषि में औपचारिक शिक्षा देने से सम्बन्धित प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुए हैं और सफलता प्राप्त होना भी तब तक बाईं आशा में नहीं है जब तक कि शिक्षित व्यक्तियों को एक तरीका द्वारा कृषि-कार्य के प्रति आकर्षित नहीं किया जाता जो कृषि को पर्याप्त रूप में कार्योत्पन्न के योग्य न बना दें और जब तक कि सामान्य क्षेत्र में कम से कम कुछ निविष्ट न्यूनतम सुविधाओं का व्यवस्था नहीं की जाती। अतएव यह स्पष्ट है कि निम्न मनीष्य म विद्यालय स्तर पर निम्न विषयों के आधार पर कृषि शिक्षा का विस्तार किया जाय।

(1) सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का विनियमित क्षेत्र के विद्यालयों में सम्मिलित है अतः कार्यक्रमों का कृषि का धार प्रवृत्त करना चाहिए। इससे लिए कृषि-सम्बन्धी शिक्षा विभिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, अतः सामान्य विज्ञान जो कि विज्ञान सामान्य विज्ञान गणित आदि

प्रचलित पाठ्यक्रमों का इस तरह धर्मस्थापना किया जाय कि उनमें धार्मिक वातावरण तथा कृषि विकास में ध्यानवाली समस्याओं का समावेश हो जाय। इस स्तर पर कृषि को कार्यानुभव का महत्वपूर्ण अंश बना देना भी सामान्य रहगा।

(ii) कक्षा 10 से पूर्व कृषि की औपचारिक शिक्षा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। प्रविष्टि में कृषि का व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सके, इसकी तयारी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि छात्रों का इस स्तर पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ गणितीय तथा विज्ञान की शिक्षा का विशेष ज्ञान करा दिया जाय।

(iii) कक्षा 10 के बाद कृषि की औपचारिक शिक्षा आरम्भ की जानी चाहिए और वह भी कृषि की पोलिटैकिनिक सम्स्याओं के माध्यम से। ये समस्याएँ एक प्रकार से बहुदृशीय समस्याएँ होंगी, जहाँ कृषि तथा तत्सम्बन्धी श्रमा के लिए आवश्यक बुगतताओं का प्रतिपादन किया जायगा तथा इनके पाठ्यक्रम के माध्यम से सत्र तीन वर्ष तक का विभिन्न अवधि वाला होगा। इनके अन्तर्गत पर्याप्त लघु-उत्पन्न की पूर्ति होगी चाहिए। परन्तु इनके पाठ्यक्रम बहुत ही व्यावहारिक तथा मुख्य रूप से सम्पूर्णता लिए हुए होने चाहिए। सामान्यतया इनका उद्देश्य कोई विभिन्न रोजगार दिखाना होना चाहिए किन्तु ऐसी सम्बन्धित व्यवस्था व्यवस्था होना चाहिए कि चाह ता कोई बहुत ही मर्यादीत धान प्रविष्टि व्यवस्था करके उच्च शिक्षा में सम्मिलित पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकें। इन पोलिटैकिनिक सम्स्याओं में विभिन्न रूप से युवा कृषकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महत्ताओं के लिए लक्षित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्राथमिक व्यवस्था एक बुगतता का दृष्टि में यह सम्स्याएँ बहुत विचारणीय होनी चाहिए जिनमें लगभग एक हजार छात्र प्रवेश कर सकें तथा जहाँ वहाँ भी सम्भव हो सके सम्स्याएँ कृषि विस्तारविधान के अन्तर्गत सत्योपयोग में विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

(iv) यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक अवस्था माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त (अथवा या कृषि पारितोषिक सम्स्याओं या विस्तारविधानों में विभिन्न शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे) अधिकाधिक सम्स्या में मुख्यतया आने पर कृषि कार्य की अन्तर्गत व्यवस्था बनायेगे। किन्तु ध्यानीय कुछ बातें हैं जो युवा कृषि की व्यवस्था के रूप में युवाओं के बीच में अधिकाधिक के साथ होंगे किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने में पूर्व ही विधान के अन्तर्गत या। ऐसे स्थितियों की आवश्यकता कृषि शिक्षा देने के विभिन्न प्रकार से

वायनमा जो मुद्रा बनाना होगा तथा प्रत्येक सामुदायिक विकास मण्डल में एक प्राथमिक प्रसार मंच का स्थापन किया जाना चाहिए। इन केन्द्रों पर वायन कमचारी वगैरह उन कृषकों की तुलना में व्यावहारिक ज्ञान में श्रेष्ठ होने चाहिए जिनका कि उन्हें शिक्षित करना है, उस क्षेत्र में सफेद कृषक इन केन्द्रों में परिचित रूप से जुड़े होने चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय की प्रसार सेवाओं में माध्यम में इन केन्द्रों को पर्यटन तथा अधिकाधिक महयोग मिलते रहना चाहिए। छासपाम में मुक्त कृषकों का चाहें छासवातिन चाहें महिला पाठ्यक्रम के आधार पर कृषि शिक्षा देने के निमित्त इन केन्द्रों का उपयोग किया जाना चाहिए।

115 उद्योग के लिए शिक्षा

उद्योग में वायन के छद्म कुशल तथा कुशल कारीगर तथा मध्यस्तराज मिश्रितों को प्रशिक्षण देने का चार मुख्य साधन हैं अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षण मन्थान (घाई टा घाई) कनिष्ठ तकनीकी विद्यालय तकनीकी उच्च विद्यालय, पानिपतिनिक तथा एपूरन्सिग एक्ट का अंतर्गत प्राप्त मुद्रियाण। इनके अलावा धीरे धीरे अल्प साधन हैं जैसे सामुदायिक विकास वायनमा का अंतर्गत विभिन्न कारीगर प्रशिक्षण केन्द्र गाँवों एवं ग्राम्य उद्योग समीप के अंतर्गत स्थापित हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र व्यापार विद्यालय (सरकारी तथा निजी) तथा बहुदलीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण। इन मन्थान प्रशिक्षण का अलावा वर्तमान समयकाल का एक अलग ऐसा माध्यम है जो काम पर गाँवों में जान का बाद काम करते करते सीखा है अथवा जो परम्परा में अब धारण पट्टी घष में पिता से पुत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त है। अथवा जो जो मुद्रियाण उपनगर हैं व आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं को मद् नजर रखते हुए अर्थात् हैं छोटे बड़े व गुणात्मकता का दृष्टिकोण में उप-स्तर की हैं।

116 औद्योगिक प्रशिक्षण मन्थानों का बहुत अधिक विस्तार करना होगा। उन छात्रों का निम्न अधिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा पूरा कर चुके हैं। इस दृष्टि में प्रथम धातु का नूनतम मोटा 14 वर्ष की उम्र पर विचार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण उद्योगों में जाना चाहिए कि वे कारखानों में उत्पादन कार्य प्राप्त करें तथा अन्य शक्ति मन्थानों में उत्पादन हेतु सामग्री का निर्माण करें।

117 कनिष्ठ तकनीकी विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया जाय अर्थात्

उन्हें तबनीरी उच्च विद्यालय की सेवा प्रदान का जानी चाहिए क्योंकि 'कनिष्ठ' शब्द का वाई तात्पर्य ही नहीं निकलता। वर्तमान तबनीरी उच्च विद्यालयों का नाम मात्र शब्द ही कुशल कारीगरों का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए जो दोना हा छात्रों तथा नियोजकों का आवश्यक कर सके तथा इन्हें सामान्य माध्यमिक शिक्षा का मजबूती में अर्पण किया जा सकता है। विवरण या इन्हें पाठ्यक्रम विद्यालयों के लिए प्रवेश योग्यता का सर्चोला तयारी स्थल में सम्मिलित जाय। पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप में आयोजित होना चाहिए तथा उपर्युक्त समय में अधिकतम उपयोग द्वारा इन पाठ्यक्रमों का इस प्रकार ■ व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि एपरेटिंगिंग एजेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके (इस एक का धाराओं में एसा संशोधन किया जाना चाहिए कि इन विद्यालयों द्वारा सफल पाठित छात्रों का नियुक्ति हो जा सके)। इन पाठ्यक्रमों का समाप्ति पर व्यापार प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष हो। विभिन्न पाठ्यक्रमों का आधार पर अवधि का घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध विद्यालयों में प्रायोगिक कार्य तथा व्यावहारिक विज्ञान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इन शिक्षणों के आधार पर पुनर्गठित करने तथा वर्तमान शिक्षा में सम्मिलित का गति का काम किया जाय कि परिणामस्वरूप तथा सामान्य शिक्षा की अवधि महत्व देना कि पत्रस्वरूप कुशल कारीगर तयार करने का दृष्टिकोण से वे तबनीरी उच्चविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सामान्य माध्यमिक विद्यालयों का तुलना में अवधि अच्छे वितरण मिले हो सके।

119 पाठ्यक्रमों में सम्मिलित विद्यार्थियों का विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो उनमें सम्मिलित की ऊँचाई है उस कम किया जाकर उनमें से २५ पाठ्यक्रमों का निर्धारित आधार पर अनिवार्य किया जाना चाहिए—

(1) वास्तविक वास्तविक शिक्षात्मक अवसरों दिया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य है कार्य (जैसे) का नियंत्रण करना तथा विभिन्न स्तरों पर कुशल कारीगरों का उत्पन्न एवं मिश्रित के उत्पन्नियों के बाद में आसानी प्राप्त करना। इन दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण रखते हुए पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। संशोधनों का सन्दर्भ निम्न श्रेणी के दृष्टिकोणों में सम्मिलित, कुशलता प्राप्त मिश्रित गणना करना है।

(11) प्रत्येक वर्ष का औद्योगिक अनुभव उत्पन्न, वर्धमान जाना

चाहिए घोर वह ना विशेषतः प्रशिक्षण के अन्तिम वष में इस प्रकार प्रशिक्षण का अधिनाधिक व्यावहारिक रूप दिया जाय। इस दृष्टिकोण से पालिटेक्निक मस्यामा को औद्योगिक क्षमता में ही आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा।

(111) कमचारी वर्ग में बनन में उचित मात्रा में वृद्धि का जानी चाहिए तथा तबनाकता का समाज तथा उद्योग में उच्च स्तर प्रदान किया जाना चाहिए, पत्रक रूप समय महसूस का जा रहा कभी को पूरा किया जा सके। अध्यापक इजानियरिंग महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त होने के साथ साथ अध्यापक व्यावहारिक अनुभव सम्पन्न भी हो। उद्योगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को शिक्षक बनाये जाने का अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए। पोलिटेक्निक के लिए शोध विद्यार्थियों का विस्तृत वायव्यता का आयोजन किया जाना चाहिए। पालिटेक्निक मस्यामा के शिक्षार्थी के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ-साथ शोध इजानियरिंग महाविद्यालयों तथा तबनीरी मस्यामा में विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण मस्यामा एवं उत्पादन अनुभव मस्यामा की नवीन ज्ञान दिया जा सके। आधारभूत विज्ञान के सम्बन्ध में भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिये।

(12) प्रत्येक पालिटेक्निक में माधन सम्पन्न मुख्यस्थित वायव्यतालाय तथा प्रयोगशाला होनी चाहिए तथा उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्रों में छात्रों का अध्यापन का हाथ में चलने वाला यंत्रा सामान्य यंत्रों द्वारा तथा कृत्रिम मशीन मशीन की मशीनता में या तो विज्ञान के लिए यंत्रों माध्यमिता विद्यार्थियों को सामान्य उपलब्ध करवाने के लिए उत्पादन कार्य करना चाहिए।

(13) उद्योगों के माध्यम में परीक्षा सत्यापन में तबनीकन प्राप्त होने तक घोर प्राप्त होने तक इसका लिए उचित प्रारम्भिक ज्ञान करत रहना चाहिए। तबनाकता के लिए प्रारम्भिक पाठ्यक्रम प्रारम्भिक रूप से पालिटेक्निक मस्यामा में दिया जा सके। तबनाक कर सकना है यद्यपि अधिक सकलता ना कारखाना में सहयोग में निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम (Sandwich type Course) को बड़ा मस्यामा में चलाये जाने पर हा निम्नता।

(14) मस्यामा पालिटेक्निक मस्यामा में महिलाओं का विशेष रुचि में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का विरगिन करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

(15) पालिटेक्निक मस्यामा में शिक्षण एवं रगिन निम्नता का

विशेषतः पालिटिनिनर मस्यामा न प्रथम दोष न शिक्षण म, अधिक
दृढतापूर्वक चलाया जाना चाहिए। तकनीकी न निमित्त पाठ्यक्रम म सीधा
गिर मनाविमान एक दृश्यस्था, मूल्य निर्धारण तथा अनुमानिततरण का
प्रारम्भिक ज्ञान दिया जाना चाहिए।

(111) जिन तकनीकी का विज्ञान उद्योग म बुद्धि दोष का अनुभव
प्राप्त है उनका विना बुद्धिन्दा पालिटिनिनर मस्यामों न स्नातकान्तर उपाधि
पाठ्यक्रमों को व्यवस्था का जाना चाहिए ताकि न उच्च स्थान के तैयारी
का योग्यता प्राप्त कर सकें।

119 धृति एक उद्योग विज्ञान पाठ्यक्रम का सम्बन्ध म जो विवेचन ऊपर
प्रस्तुत किए गए हैं उनका व्यापारिक विविधशीर्षिक, व्यापारिक तथा
सीधेगिर ज्ञानाओं तथा महिमाओं का विवेक रवि स सम्बन्धित क्षेत्र म
रोषर पाठ्यक्रम तदार विवेक ज्ञान का भी बहुत गुणवत्ता है। इसका पूरा
तर उपायोग दिया जाना चाहिए।

120 तैयारी उच्च विद्यालय कनिष्ठ तकनीकी विद्यालय पालिटिनिनर
तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम म दिया प्राप्त युवरा का प्राप्ताहित दिया
जाना चाहिए जिसका अर्थ न्यून छात्र छात्र उद्योग प्रारम्भ करें
अथवा दूसरा न साथ मिलकर छात्र समान न नगरान समायें या एमे
उद्योग या ऐसा गतिविधि म अर्थ प्राप्त का अर्थ करें जिनका वि
समान का व्यवस्था है।

21 उन्नत अध्ययन के क्षेत्र तथा प्रमुख विश्वविद्यालय

आजकाल विज्ञान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान व्यवस्था म न
न व्यवस्था विज्ञान एक व्यवस्था का अर्थ जाना न सी है कि जिन
विश्वविद्यालय का अर्थ स उन्नत विज्ञान न नगर म विज्ञान बुद्धि ज्ञान नह।
ह उन्नत विज्ञान तथा व्यवस्था विज्ञान का अर्थ स नह सहा सम्बन्ध
विज्ञान विज्ञान गुणवत्ता का दृष्टि म अध्ययन व्यवस्था नगर स

यह। सर्वाधिक छात्र किन्तु प्रभावशाली मांग है, जिसके द्वारा आरम्भ स्वरूप उच्च शिक्षा के स्तर में सवतापूर्ण सुधार किया जा सकता है। प्रथम शिक्षा के अथवा क्षेत्र में तथा जीवन के समस्त कर्मों में इसी तरह सुधार किया जा सकता है। 122 इस दृष्टिकोण में जिस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संकल्प बनाया जाना है एवं विस्तृत किया जाना है—यह उन्नत अध्ययन केन्द्रों का स्थापना। विश्वविद्यालयों की मांगों के उचित समाधानों द्वारा सहायता की जानी चाहिए कि वे पुनः विभागों में श्रेष्ठता प्राप्त करें, अपने और अनन्तता के उनका उन्नत अध्ययन केन्द्रों के स्तर पर विस्तार करें।

✓ जिस विश्वविद्यालय में विभाग का उन्नत केंद्र के लिए पुनर्गठन का आधार उत्त विभाग द्वारा प्रेषित किए गए कार्य की मांगों और उमरा स्तर, अथवा शिक्षण के क्षेत्र में उमे प्राप्त प्रथमा शोध क्षेत्रों में उमरा योगदान तथा भागी विनास का उमरा सम्भावनाएं होना चाहिए। (कर्म की पद्धति में तरह अपनाई जाना चाहिए कि उा विश्वविद्यालय तथा प्रगत समुदाय का शिक्षा सामान्य प्राप्त हो जाय। यदि आवश्यक हो तो उम विभाग का आरम्भ में एक सम्भावित केंद्र समझा जाय तथा आरम्भिक अवस्था में कर्मचारीयों तथा आवश्यक पुस्तकों एवं उपकरणों का जुटान के लिए पौंच पय सब विषय परीक्षित महोत्सव दी जा सकता है। प्रगत सहायकता होना आगामी पौंच वर्षों के लिए फिर से सहायता का स्वीकृत किया जा सकता है।

उन्नत केंद्र बनने करने का मुविधा निरन्तर मांग एवं प्रयत्नशील बने रहने पर होना जाना चाहिए। तान स पौंच वर्षों के बीच में कम से कम एक बार विज्ञानिक कमिटी का प्रयास उन्नत केंद्र का निराकरण करना चाहिए। इस विज्ञानिक कमिटी के सम्य मुविधान भारतीय तथा जहाँ सम्भव हो विदेशी विषय हो। यह कमिटी केंद्र के कार्यों का मूल्यांकन तथा पुनर्विनाशन करे।

123 किन्तु जतना हो पर्याप्त नहीं है। यदि श्रद्धा परिलक्ष्य संभाव्य है तो आशंका है कि उन्नत केंद्रों का इस मांगता में एक और शिक्षा का आरम्भ किया जाय तथा पौंच अवकाश विश्वविद्यालयों के साथ सम्बन्धित विषय में उन्नत अध्ययन केंद्रों का एक ऐसा पत्र तयार किया जाय जो एक दूसरे का सम्पुष्ट करें। कर्म के मांग करने पर हो तथा आवश्यकता परिलक्ष्य निमित्त हो सकता कि जिसमें प्रथम श्रेणी स्नातकस्तर काय तथा माध्यमिक विद्या जा सहयोग और समाज में कम से कम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

प्राप्त स्तर उपर्युक्त हो सकगा जो अन्तराष्ट्रीय स्तर के समतुल्य हो ।

124 इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय का भेषावा छात्र विशेष क्षमतावान् तथा होनहार अध्ययन तथा प्रयत्न श्रमा की सुविधाओं और उपकरण उपलब्ध कराये जायें व प्रयत्न किये जाने चाहिये।

(1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में अधिस्नातक और स्नातकान्तर स्तर की छात्रवृत्तियों प्रदान की जानी चाहिये जिससे प्रतिभावान् छात्रों को प्रवेश दिया जा सके । तत्समय प्राचीन छात्र वृत्तियाँ एक छात्रों का दो जायें जो उच्च कक्षा के छात्रों के दाहल के हों ।

(ii) इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक अध्ययन का प्राप्त करने के प्रयत्न सम्पन्न करने तथा छात्र तक ही सीमित न रहकर राष्ट्रव्यापी और एक तरह से विश्वव्यापी होना चाहिये । अथवा पद्धति नवीन होनी चाहिये । यहाँ आवश्यक है पुनः हुए प्रयोगों का अधिक बतन वृत्तियों प्रदान का जाना चाहिये तथा उन्हें छात्र प्रयोग अध्ययन प्रयोगों की सुविधा और व्यावसायिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की सम्भावनाओं के प्रति आसक्त किया जाना चाहिये । पत्राचार के समय उत्तरों में काम लिया जाना चाहिये तथा आवश्यक धन भी उपलब्ध होना चाहिये ताकि विविधता प्राप्त व्यक्तिगत को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा सके ।

(iii) प्रतिभावान् छात्रों तथा अध्ययन के एक समूह को पर्याप्त सुविधाओं तथा सहायता के साथ उन्हें उपलब्ध कराया जा सके तथा समानता से आवश्यक है । वास्तव में बहुत सी चीजें हैं जो छात्रों के लिये हैं क्योंकि महत्व का मादगी और उत्साहना को दिया जाना है न कि सम्पत्ति के लिये ।

124 11— मुख्य विश्वविद्यालय तथा उच्च अध्ययन के कक्षा सम्बद्ध अध्ययन का निर्माण करके उच्च शिक्षा के विकास में सम्पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । यह दृष्टिकोण में निर्माणित प्रयोग किये जाने चाहिये।

(1) विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त प्रतिभावान् छात्रों का विकास व्यक्तियों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक सम्पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिये । यहाँ से अधिस्नातक का एक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में भेजा जाए जहाँ उच्च अध्ययन प्राप्त किया जा सके । अगर निमित्त विश्वविद्यालय प्रदान अध्ययन एक के लिये विद्यार्थी प्रोत्साहित करे ।

(ii) शिक्षा के माध्यम से छात्र व्यक्तिगत के नियुक्ति या सुविधाजनक करने के दृष्टिकोण में विश्वविद्यालय प्रदान अध्ययन का एक मात्रता के अध्ययन द्वारा सम्पन्न किया जा सके । यह छात्रवृत्तियों

तेन स्तरों पर प्रश्न की जानी चाहिए—व्याख्याता, रोडस तथा प्राध्यापक (प्राफेसर)। यद्यप्यवृत्तियाँ उन विषय साम्यता सम्पन्न व्यक्तियों की हो जानी चाहिए जो अथवा इस व्यवसाय में न था पायें तथा एक व्यक्तियों की विश्वविद्यालय के विभाग में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नम्रान का ध्यान रखा जाय कि उनका नियुक्ति यथा सम्भव साधन स्यामी पदा पर ही हो।

(iii) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों का इस बात के लिए प्रागतिविधियाँ जानी चाहिए कि क्या गति सम्भव है ध्यान नये अध्यापकों का पूर्व ध्यान करें तथा उन्हें मुख्य विश्वविद्यालय अधिका उन्नत अध्ययन के कक्षा के सम्पर्क में कुछ समय तक रहें ताकि वे व्यावसायिक बड़ासरी प्राप्त कर सकें।

124 बो—मुख्य विश्वविद्यालयों के स्तर की उन्नत करने की इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धन्य उपायों के अलावा निम्न प्रकार से भी सहयोग दिया जाना चाहिए —

(1) पाठ्य के विवरण क्षेत्रों के लिए उन्नत अध्ययन के कक्षा के सदस्या सम्प्राप्ति केन्द्रों के सदस्या प्रमुख विश्वविद्यालयों के विभागों तथा विश्व सम्बद्ध महाविद्यालयों के बीच अन्तर्विश्वविद्यालयी सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) उन्नत अध्ययन के कक्षा में महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रम के निम्न अध्ययन विश्वविद्यालयों अधिका सम्बद्ध महाविद्यालयों के वैधानिकों तथा हाथीकार विद्वानों का मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

125 मधीन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय

क्षेत्रों के कुछ कक्षा स्थापित करने के प्रयत्न उच्च शिक्षा में स्तर सुधार के सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। किन्तु यथा सम्भव धन परिणाम प्राप्त करने के लिए तथा इन कक्षाओं में उत्पन्न श्रद्धा का धन उच्च शिक्षा का सम्प्राप्ति तक फैलाने के लिए दो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का प्रावधान है मुख्यतः नये विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना—संशोधित रहना तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय व्यवस्था का सुदृढ़ करना।

126 नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करने समय उच्च शिक्षासम्पन्न हाथीकार का बहुत बड़ा भाग में धनराशि की तथा प्रागतिविधियों का प्रावधान होता है—इन नये की पूर्ति बहुत गहन है और तथा निम्न

न गचालन पर अधिकार निभर करता है। अतएव यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय व्यवस्था का उच्च प्राथमिकता देकर मुद्रित किया जाय। वक्त वमा तरह भारतीय विश्वविद्यालय अपने बहुविध उत्तरदायित्व का ठीक तरह से निभा सकेंगे। इस दृष्टिकोण से जिन कुछ महत्वपूर्ण वाक्यमाला का विकसित किया जाना है उनका विवरण इस प्रकार है

129 विश्वविद्यालय स्वाधीनता

सबप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता तो यह है कि विश्व-विद्यालयों का स्वाधीनता को समस्त रूप में स्थापित किया जाय। इसका मूलभूत आधार यह है कि देश प्रथम मता की राजनीति के दबाव भयका विचारों का प्रतिबद्धता में स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता की सत्य की लाज बूझ सकती है तथा अपने अध्यापकों और छात्रों में स्वतंत्र चिन्तन एवं स्वतंत्र विचार विमर्श की धारणा पनपा सकती है। स्वतंत्र समाज के विकास के लिए यह अनिवार्य है। इस प्रकार की स्वाधीनता के तीन क्षण हैं (1) छात्रों का अपने (2) शिक्षकों की उपरि तथा नियुक्ति और (3) पाठ्यविषय, शिक्षण विधि तथा अनुसंधान का समसामान्य एवं दोषों का निर्धारण। यह सत्य है कि यह स्वाधीनता एक बड़े मन्दम में ही लगी जा सकती है अर्थात् राष्ट्र के प्रति और सम्पूर्ण रूप से मानवजाति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। लेकिन तब तो यह और भी आवश्यक है कि समाज प्रवृत्तियों तथा प्रथाओं का विकास किया जाय जो विश्वविद्यालय की स्वाधीनता के प्रति तथा समाज का उत्तम प्रयत्न के प्रति योग्य कर सकें।

130 भारत में विश्वविद्यालय स्वाधीनता की बहुत अर्थों परम्परा रही है। लेकिन यह आवश्यकता है उसे मुद्रित करने एवं मुद्रित बनाने की। सभी सम्बन्धित पक्षों को विचारपूर्वक पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतविश्वविद्यालय परिषद् (I U B) को इस विषय में सतत सजग रहना है क्योंकि एमो स्वाधीनता कोई ऊपर से नहीं उतरती, यह तो विश्वविद्यालयों को स्वयं वांछ्य बन उठकर निरंतर कमाना होगा।

131 विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था

विश्वविद्यालय-स्वाधीनता तब तक वास्तविक और प्रभावशाली नहीं बन सकती जब तक कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों के साथ सममन्तरी और गुप्तगुप्त से काम न लें तथा उन्हें पर्याप्त धार्मिक महायन्त्र न दें, और जब तक कि महायन्त्र में प्राप्ति राशि का व्यय करने के नियम सरल नहीं बना दिए जाय। विश्वविद्यालयों का राज्यों द्वारा दा जान जाना धार्मिक महायन्त्र

का भवधन महायता (दण्डि परिणिष्ट चार) यवस्था के आधार पर पुनर्गठित किया जाना सम्भवतः अवश्य है। हमारे अनिश्चित यह भा होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में जनता के समर्थन साधना जवाबदारी न करना पड़े। उनका दण्ड प्रणाली अथवा उनके वित्तीय मामलों में तो जन चर्चा के विषय है और न ही दण्डन राजनानि के शिखर है और इस दृष्टि से यह वादित ही है कि उनका विभाव विनाश मस्त अथवा विधान समझा के समझ में रखा जाय। केन्द्रिय विश्वविद्यालय कानून में प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों के जीव हूँ तब दण्डिया मजदूर में प्रवेशित किया जाय चाहिए तथा समझ-जीव प्रतिबन्धन के माध्यमि विद्वित के विनाय जान चाहिए। इस पद्धति से सरकार के। इस बात का आवश्यक अवसर मिल जाता है कि उनका वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वातंत्र्य में अनुचित हस्तक्षेप किया बिना यह सुधार तथा निरीक्षण हूँ विद्वित के और से फायदावाही कर सकें। उन राज्य विश्व विद्यालयों के सम्बन्ध में भा एका ही व्यवस्था का अपनाया जा सकता है, जहाँ पत्र से हा कोई एका व्यवस्था नहीं है।

132 उपकुलपति के कार्य तथा उसकी नियुक्ति

विश्व विश्वविद्यालय में उपकुलपति का स्थिति है। होता है जिसमें छात्रों का जाता है कि वह विश्वविद्यालय में शिक्षा स्वतंत्रता तथा अक्षरी व्यवस्था के निष्ठाता का प्रतिष्ठा है। विद्वता तथा गण्य की राज के प्रति विश्वविद्यालय का प्रतिबन्धन के लिए वह उत्तरदायी होता है और विश्वविद्यालय के वायव्यार्थिता का वह इस तरह उपस्थित कर सकता है कि शिक्षा-व्यय का अपना तमाम निर्विधिवा में उसका निरन्तर सम्योग मिलता रहे। उपकुलपति सामान्यतः एक प्रख्यात विद्यापीठी या विद्वान् व्यक्ति होता चाहिए, जिस पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव भी हो।

उपकुलपति की है। इसका निर्णय स्वयं विश्वविद्यालय का करता चाहिए। विद्वान् विद्या विश्वविद्यालय में प्रवेशित व्यवस्था का अथवा उमारे हूँ परिस्थिति के का अपनाया जा सकता है। उपकुलपति का ध्यान करने के निमित्त पदा समिति के माध्यम से एकाधिकता तथा विद्वता के लिए प्रस्तावता है। यदि उनमें से कोई माध्य विश्वविद्यालय में सम्बद्ध है तो उसका उक्त समिति का माध्य बनने में कोई रोक नहीं माना चाहिए मन्त्र यह विश्वविद्यालय का वास्तविक सम्बन्ध है।

उपकुलपति का कामकाज वर्ष वर्ष होता चाहिए और उस पर ही विश्वविद्यालय में इस वर्ष का कार्य सम्पन्न किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय के कुशल मचानन हेतु उपकुलपति का पर्याप्त गम्भीरता हो जानी चाहिये।

1.39 विश्वविद्यालय के भीतर स्वाधीनता

विश्वविद्यालय स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन या सांस्कृतिक शिक्षा का आधार पर पुनर्गठन किया जाय तब शिक्षा के अर्थों में अध्यापक और छात्रों के बीच उचित भावना बनने तक इस प्रकार मोचे में ऊपर तक विचारों का आदान प्रदान सम्भव हो सके। यह उद्देश्य का प्राप्ति के लिए निम्नलिखित तराफें अपनाय जाने चाहिये

(1) विश्वविद्यालय के उन विभागों का जो अधिक मात्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों का अधिक मात्रा में प्रत्यावाशित की जाना चाहिये। प्रत्येक विभाग की विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समस्त व्यवस्था-मिति हो, जिसमें सभी अध्यापक, कुछ रीढ़स तथा अध्यापक दल द्वारा निर्वाचित कुछ व्याख्याता सम्मिलित हों। प्रत्येक उपमंत्र में इनकी बैठक कम से कम एक बार अवश्य हो तब विभाग के शक्ति कायमता प्रमाणित तथा पुनर्गठन की आवश्यकताओं, कर्तव्यों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के प्रत्यावाशित प्राप्ति पर विचार विमर्श किया जा सके। इनकी कार्यवाही मन्त्रालय तथा गवर्नर के परिपत्र के मन्त्रियों के प्रसारित की जाय। एक ही प्रत्येक विभाग के मासिक कार्य सम्बन्धी पर्याप्त गहनता होना चाहिये। जहाँ विज्ञान विभाग बड़े हैं वहाँ विभागाध्यक्ष की महामन्त्र प्रत्यापक तथा रीढ़स में से ही कोई एक उप विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाय। विश्वविद्यालय काम परिपत्र के अनुमति में विभागाध्यक्ष उपविभागाध्यक्ष को कुछ निर्धारित कार्य सौंप दें।

(ii) यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों की स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता का स्वाधीन प्रशासन की जाय तथा बचक की दृष्टि से उन्हें एक निश्चित मामला के भीतर प्रान्त में एक अधिक स्वतन्त्रता दी जाय कि उनका उपयोग प्रशासनिक स्वाधीनता के आधारों के नियंत्रण में किया जा सके।

(iii) विश्वविद्यालय का एक एक समष्टि समुदाय समझा जाना चाहिये जिसमें अध्यापक वरिष्ठ विद्यार्थी हैं जो एक ही विद्यार्थी तथा प्रशासनिक उक्त होने का गुणवत्ता के लिए हैं। अध्यापक छात्र और प्रशासन के बीच में कोई झगड़ाने वाली प्रक्रिया में बसा जाना चाहिये। प्रत्येक विभाग और विश्वविद्यालय में विचार विमर्श और जहाँ जहाँ सम्भव हो इनकी सामान्य समझौते तथा कठिनाइयों के निराकरण हेतु अध्यापकों तथा छात्रों

को समुपन ममिनिया बनायो जाना चाहिए । उपबुनपनि अथवा प्रधानाचार्य, जो भी मस्या व अध्ययन हा व इन ममिनिया व कार्यो स पूरगत अवगत रह । सस्थाध्यायी व अध्ययनता म एक और वत्राय समिति हा । जिसक मस्या अध्यापक वग तथा छात्रा व प्रतिनिधि हा । यदि इस प्रकार की कार्य व्यवस्था ठीक तरह स चलन लगना है तो कम स कम बहुत बड़ी मस्या म तमा छाटी आनातो म हन हा जान वाना उन समस्याया का निराकरण ता हा जायगा, जो उचित अवसर पर ध्यान न दिय जान व कारण बहुतो उत्पन्न करतो है और जो कालांतर म बहुधा अनुशामन व लिए भयकर गतरा साबित हो सती है । इसम अध्यापक तथा छात्रा व बीच नय अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुये तब नया विश्वास पनपगा । विश्वविद्यालय प्रशासन म भाग लेन व लिए छात्रा का उत्साहित करन तथा विश्वविद्यालय व दनित कार्य म उन्हें अपने उत्तरदायित्व का महसूस करवान व लिए छात्रा (अधिस्तातक छात्र मा) व प्रतिनिधियों का मासित्विक परिषद् तथा विश्वविद्यालय पायालय स सम्बन्ध दिया जाना चाहिए ।

1.1.1 विश्वविद्यालय के लिए कानून

इस प्रतिवेदन म तथा आन्ध्र विधान व प्रतिवेदन (Report of the 'Model Act') म विश्वविद्यालयों का मुद्दा बतान तथा उनके प्रशासन का पुनर्गठित करन व लिए जो सुझाव दिय गये हैं उनका प्रभावशाली रूप म कार्यान्वित करन व लिए आवश्यक है कि भारत म विश्वविद्यालयों के निमित्त वर्तमान कानून का अतिरिक्त पुनर्विचारन दिया जाय तथा उसम आवश्यकताानुसार संशोधन दित जाए । इस निशा म निशा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पालन करती चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निशा मन्त्रालय राज्य सरकार तथा सर्वोपत विश्वविद्यालयों व साथ निरन्तर विचार विमर्श करन व लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था ईजा की जानी चाहिए । विश्वविद्यालयों म सम्बन्धित कोई भी नया कानून निरन्तर विचार विमर्श व साथ ही प्रमाणा दिया जाना चाहिए ।

1.1.2 प्रशासनिक कानूनो बहुत अतिर सीमा तक उत्पन्न हो गयी है तथा विश्वविद्यालयों व निगम आयोगों म जो सुझाव पगे दिय गये हैं उनका कारण उनका व मन्त्रा म विश्वविद्यालयों का अति बटुपा दूषित हुआ है । यह टाक है कि मार्गिक व मोरिस अधिकांश की सुरक्षा होना चाहिए लेकिन यह म आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों का स्वाधानता बना रहे और उनका सम्पत्ति निरन्तर बढ़ता रहे । विश्वविद्यालयों म सम्बन्धित है कि सम्पत्ति

रापनाम तथा मुद्रा का नाम निपटारा के लिए उचित परम्पराएँ विकसित की जाएँ। अतएव चाहे तो भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करें कि वह उन प्रवृत्तियों का पुनर्विचार करें जो विश्वविद्यालयों तथा छात्र संस्थानों से सम्बंधित मामलों पर न्याय न्यायालयों के लिए म स्पष्ट दृष्टिगत है तथा न्यायालय में बात की सम्भावना पर भी विचार करें कि क्या कोई ऐसी उचित नीति निर्धारित की जा सकती है जिससे कि विश्वविद्यालयों की स्वाधीनता बन रहने में तथा उच्च शिक्षा के उचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहे।

196 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

इस समय शिक्षा का जो ढाँचा है, उसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा कई तरह की विभक्त है उनका आपस में तो कोई सम्बन्ध ही है और न उनमें किसी प्रकार का सामान्य प्रदान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगभग 60 विश्वविद्यालयों से सम्बंधित है तथा उनका विकास के लिए अपने पास उच्च शिक्षा में उनकी महत्त्वता करता है जो शिक्षा उन भारत सरकार से इनके लिए प्राप्त हुई है। इसका अलावा कृषि विश्वविद्यालय है जो हमारी भी भूमि अनुदान महाविद्यालय सम्बंधी मिश्रण से प्रेरणा प्राप्त करता है। इस मिश्रण में गणना में हमारी भी व्यावसायिक शिक्षा तथा कृषि उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कृषि शिक्षा विस्तार सेवाई तथा साधकाय का समुक्त कर देने पर बल देना इन कृषि विश्व विद्यालयों की मुख्य विशेषता है। इन विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा तथा साध के विकास की महायत्नाय अपने स्वयं के प्राकृति एवं सामाजिक विज्ञानों के विभाग भी गाने दिये हैं। गडकपुर बानपुर, दिल्ली, मंगल धर्म स्थानों पर तकनीकी संस्थान भी हैं जो गणना के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' है तथा शिक्षा उपाधि वितरण का अधिकार भी प्राप्त है। कृषि विश्वविद्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का जमान कृषि मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से तथा अधिनियमों के अंतर्गत महायत्नाय प्रदान कर दी जाती है। बिना शिक्षा के शिक्षा के साथ महायत्नाय स्वायत्त मंत्रालय प्रदान करता है। यह भी कहा जाता था कि विश्वविद्यालयों पर शिक्षा शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सीमित हो है। इस प्रकार आयोग में सामान्य बनाए रखने के प्रभावशाली प्रदानों के अलावा यह-एक-एक-एक शिक्षा व्यवस्था हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संस्थाप है।

1137 वांछनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस व्यवसायिक पक्ष से सम्बन्धित तथा उसकी सम्पूर्ण समस्याओं के निराकरण में पर्याप्त रूप में सम्मिलित होना चाहिए। यह कई कारणों से आवश्यक है और उनमें से मुख्य कारण यह है कि आज के विश्व में कोई भी शिक्षा सम्पूर्ण रूप में निरन्तर नहीं हो सकती, यदि वह अक्षिप्त जीवन का मुख्यधारा में अन्तर्गत है। वृत्ति तरंगों की तथा चिरित्वा विज्ञान एवं शिक्षा तथा सम्पूर्ण हा वायव्य अक्षिप्त व इस विस्तृत धारा में जुड़े हुए हैं। तथा यह एक दूसरे का सम्बन्धित तथा आवश्यकताओं में सम्मिलित भाग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ना समस्त सर्वाधिक भाषा सम्मिलित है हा, अनुमानित वेदाङ्ग में भा इस अनुदान की अधिक विस्तृत रूप में प्रयुक्त करना होगा। अविद्यमान वास्तविक तथा आर्थिक यहाँ में हा वायव्य जहाँ विभिन्न शिक्षाएँ आपस में मिलती हैं। इस सम्मिलन में यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि उक्त मायना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण की धाराओं के अनुसृत ही है जिनकी रचना ही इस तरह में की गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में कार्य करें। अतः उच्च शिक्षा के निमित्त सम्मिलित समिति की शिक्षा शिक्षा का अनुमानित किया जाना आवश्यक है जिनमें यह कहा गया है कि समस्त प्रकार का उच्च शिक्षा का एक सम्पूर्ण स्काई बना जाना चाहिए कि व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा में मिलाया जा सके तथा वहीं शिक्षा जा सकता और यह आवश्यक है कि वृत्ति अन्तर्निष्ठ तथा चिरित्वा आर्थिक मुक्त सभी प्रकार का उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वायव्य का मुख्य धारा है। यह वह अन्तिम शिक्षा है जिन तरफ हम बढ़ना चाहिए।

1138 यदि कुछ कारणों से अन्तर्गत समाज में उठाया जा सके तो यह वांछित है कि वृत्ति अन्तर्निष्ठ तथा चिरित्वा शिक्षा के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह के वृत्ति सम्मिलन का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उनमें आर्थिक प्रभावपूर्ण सामर्थ्य स्थापित करने के लिए शिक्षा नवीन व्यवस्था का जन्म लिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह के सम्मिलन का मुख्य धारा स्थापित किया जाना है। यह आवश्यक नहीं है तथा यह स्थापितता प्राप्त सम्मिलन के रूप में स्थापित करने पर भी सम्मिलन का पूर्ति का जा सकता है। यह सम्मिलन धारा क्षमता के विज्ञान वसाधकों तथा सम्मिलन का मुख्य धारा जो चाहिए। वे एक प्रकार के लगे हुए तथा सम्मिलन सम्मिलन जो चाहिए कि वे वसाध विचार विमर्श करने तथा वायव्य का अन्तर्निष्ठ विचार करें। वे सम्मिलन का प्रधान को शिक्षा या धारा क्षम

का बाद विश्वविद्यालय के ज्ञानिक हाना चाहिए। इन सगठना का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह हा काम करना चाहिए अर्थात् सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा उन्हें एक मुश्किल अधिक सहायता दी जानी चाहिए। इन सगठना का स्वतन्त्रता हाना चाहिए कि इस राशि का विश्वविद्यालयों में उनकी आवश्यकता तथा विकास के कार्यक्रमों में अनुसूचित वितरित कर सके। सामाजिक बनाए रखने हेतु यह वांछित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह के उन सगठना के कुछ सदस्य एक दूसरे में हाना चाहिए। इससे अनिश्चित कार्यक्रमों का पुनर्विस्थापन करने तथा उनमें सामाजिक बनाए रखने हेतु इन चारों सगठना के अध्यक्ष समय-समय पर विचार विमर्श करते रहने चाहिए।

139 (घ) उच्च शिक्षा हेतु मन्त्रालय मन्त्रालयों का समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि पूर्णकालिक उपकुलपतियों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य बनाना वांछित नहीं है। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान विधायक में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं। यह वांछित प्रस्ताव नहीं है और न यह उचित ही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्च प्रख्यात एवं शिक्षण की सेवाओं का लाभ न मिल सके बल्कि इसमें कि वह उपकुलपति भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संख्या 12 में 15 के बीच का हाना चाहिए। इनमें से एक निहाई में अधिक सरकारी अधिकारी नहीं हाना चाहिए। कम से कम एक निहाई राज्य विश्वविद्यालयों से हाना चाहिए जिसमें कि उपकुलपतियों के भी शामिल होने की सम्भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। उच्च मध्य शिक्षा विभाग विभाजित हाना चाहिए। अधिक संख्या में लोग इस सम्बन्धित हो गये इससे निष्पत्ति यह किया जा सकता है कि उच्च शिक्षा की वर्तमान समस्याओं पर ध्यान की तीन वर्षों के लिए आय तथा दो बार से अधिक कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष न रह सके।

140 (घा) आयोग के समस्त उपस्थित समस्याओं की विभाजना तथा संस्था का हलियात रखने हुए यह आवश्यक है कि उन बहुत बड़ी मात्रा में धर्मोत्पत्ति करायी जाय ताकि यह उनका प्रभावपूर्ण तरीके में निर्वाह कर सक। आयोग ने तीन विभाग योजनाओं का अध्ययन किया है और इन प्रतिवेदन में तीन योजनाओं का सुझाव गया है उनका हलियात रखने हुए यह स्पष्ट है कि अनुसूचित मात्रा में जो आवेदन किया गया है वह विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का आधारभूत विकास कार्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव वर्तमान आवेदन राशि में कहीं अधिक अनिवार्य करने हानी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निम्नलिखित कार्यों के लिए ता मुख्य रूप से अधिक धन का आवश्यकता होगी ही

- उन्नत अध्ययन के क्षेत्रों तथा मुख्य विश्वविद्यालयों का विकास
- बुद्धि युक्ति विश्वविद्यालयों में शिक्षापीठ का विकास
- ज्ञानकोषों तथा अनुसंधान का विकास,
- ग्रन्थालय स्थित विश्वविद्यालयों के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना
- केन्द्रीय औद्योगिक समन्वय का स्थापना और
- प्राधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्य का विकास ।

140 नव प्रतिवेदन में की गयी विचारों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधायक 1976 का पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा उनमें वांछित समायोजन किया जाना चाहिए । इस नये विधायक का अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर लिया जाना भी वांछित है ।

141 विज्ञान एवं तकनीकी

विज्ञान के विकास के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान में भी प्रगति होती है परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक होने लगता है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वेदन शिक्षा एवं अनुसंधान में पसा लगा देने मात्र से ही कोई देश स्वयं ही समृद्ध हो जायगा । तथा यह है कि इनके प्रतिफल भी घटित हो सकता है । विज्ञान शिक्षा तथा उच्च प्रकार के अनुसंधान के अन्त सम्बंधों का तात्पर्य यह है कि यदि उर्ध्व राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित किया जाय तो उत्पादन में वृद्धि होगी । अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप विज्ञान एवं भाषा के लिए और अधिक साधन एवं खोल उपलब्ध होने लगेंगे और इस प्रकार विज्ञान, तकनीकी ज्ञान तथा उत्पादन में अतिवृद्धि होगी । अतएव विज्ञान शिक्षा का गुणवत्ता में सामूहिकता तथा वृद्धि एवं उद्योग के विकास के निमित्त तकनीक अनुसंधान का प्राथमिकता देना शक्ति पुनर्गठन का मुख्य कार्यक्रम होगा । ऐसी प्रभावशाली एवं दूरदर्शी प्रयत्न मुख्यतः किए जाने चाहिये कि देश में उद्योग विभागों के अन्तर्गत विज्ञानों में अनुसंधान तथा उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक किया जा सक ।

142 विज्ञान शिक्षा

तीन-तीन के बंधमान माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा एवं शोध तथा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगामी दशकों में विज्ञान एवं तकनीक शिक्षा में अत्यधिक धन पर प्रयोजनार्थी की महत्ता में कई गुणा

वृद्धि करनी होगी। विभागाध्यक्ष म. प्रसाद आर्थिक विकास का दायता के अनुरूप विज्ञान शिक्षा एवं तबनाम ज्ञान के विकास को सम्बद्ध करने तथा विज्ञान व विकास के अन्तर्गत म. वर्तमान क्षेत्रीय अर्थ-तुलन का नम कर्तन का भी परम आवश्यकता है।

143 विज्ञान एवं गणित व कई उन्नत अध्ययन के दो का विकास किया जाना भी आवश्यक है। इनका अध्यापकवर्ग सर्वश्रेष्ठ एवं योग्य होना चाहिए और जहाँ वही सम्भव हो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिता व्यक्ति सम्मिलित किये जाने चाहिए। 71 या तीन वर्ष के लिए अनिवार्य अध्यापक का निश्चित अनुपात के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठित अध्यापक को सेवाका को उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व एक समित भारतीय समिति का गठन करना चाहिए। इस समय विज्ञान व वाय कर र. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिता भारतीय वैज्ञानिक तथा सुविख्यात विज्ञान वैज्ञानिकों का एक योजना व अन्तर्गत सामंजस्य किया जा सकता है।

144 अधिस्तानक तथा स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रमों में भी ही सामूल मूल परिवर्तन किया जाना भी आवश्यकता है। व्यावहारिक वाय त. ज्ञान विज्ञान एवं भूमि विज्ञान सम्बंधी परीक्षणन अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देना भी आवश्यकता है। भौतिक विज्ञान व म. अतिर. त. प्रायोगिक परीक्षा के अध्ययन में उचित महत्त्व बनाय रखा जाना भी आवश्यक है।

145 प्रत्येक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय व विज्ञान विभाग व कामगारणा मुगर्जित होगी चाहिए। छात्रों का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि व कामगारणा व व. का उपयोग करना समर्थ तथा प्रयोग गाना का आधारभूत तबनाम और अध्ययन का जानकारी प्राप्त करें। का. गाना का वही अधि. म. व. व. वाय करना चाहिए जमा कि धर्मो न. है। वा. न. है कि उ. म. वाय कर र. व्यक्ति भी इनका साधकानी तथा प. पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग कर सकें।

146 अन्तिमपरी अध्ययन का भी म. व. से प्रोत्साहित करना होगा यदि आवश्यकता के विना व अध्यापकवर्ग में भौतिक वैज्ञानिक (गणित भा) और जीव विज्ञान में अधि. र. र. व. वैज्ञानिकों का विशेष में सम्मिलित किया जाय तो यह बहुत ही लाभप्रद होगा। इस तरह भौतिक विज्ञान तथा गणित विभाग अवश्य ही सामंजस्य होगी, य. अनुसंधानप्रिय इ. वि. के मुख्य में रहे।

147 यत्नानिक अनुसंधान

यत्नानिक अनुसंधान तथा उमक विकास का प्रगति की निगाह में भी अधिकतर प्रयत्न नित्य ज्ञान की आवश्यकता है।

148 विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा तथा यत्नानिक अनुसंधान का सुनियोजित रूप में सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया जाना हमारी राष्ट्रीय नीति का सूत्रभूत तत्त्व होना चाहिए। शृङ्खलागत यत्नानिक तथा इंजीनियरिंग शिक्षा का बहुमूल्य तथा दुर्लभ पाठ्य होना है। उच्च विश्वविद्यालयों में स्थापित दिया जाना चाहिए जहाँ कि उनका गुणात्मक प्रभाव का सामान्यतः अधिकारिता प्राप्त उठाया जा सकता है। शोध-कार्य के निमित्त अनुसंधान का राशि में अधिकवृद्धि हो जाना चाहिए तथा दशाब्दी के अन्त तक किसी विश्वविद्यालय में हानि घात कुछ शर्तों का लगभग चौथाई भाग अनुसंधान पर खर्च किया जाना चाहिए।

149 शुद्ध (मूल आधारभूत) अनुसंधान का सामान्यतः महत्व देने वाले विश्वविद्यालयों का भी व्यावहारिक अनुसंधान एवं विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह संज्ञाका संस्थाओं में शुद्ध अनुसंधान कार्य का कम महत्व न देकर वे भी व्यावहारिक एवं औद्योगिक अनुसंधान-कार्य पर विशेष ध्यान दें।

150 प्रवृत्ति यह रही है कि यदि कोई प्रविश्वयन बनाया जाय तो अनुसंधान कार्य 'शुद्ध और अधिक शुद्ध' होना जाता है। भारत में विज्ञान-ज्ञान के लिए व्यावहारिक अनुसंधान के महत्व का दृष्टि से कम प्रचार का प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। इसका आवश्यक रूप में अर्थ यह है कि विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं में अथवा अनुसंधान कार्य में अल्प इंजीनियरिंग हो तथा अधिक शुद्ध यत्नानिक अनुसंधानात्मकता का अनुपात कम का दृष्टि में अधिक संस्थाओं में अथवा अल्प होना चाहिए। विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थाओं तथा उद्योगों के बीच-बारियों द्वारा आपस में विचार-विमर्श तथा अन्तर्गत स्थापित करने औद्योगिक अनुसंधान का समन्वय का सामूहिक रूप में हल खोज निकालना का भी आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में आवश्यक अन्तर्गत कम का अन्तर्गत प्रदान हो सकता है और हाँ भी चाहिए।

औद्योगिक प्रविष्टि में शिक्षा-प्रणाली में अल्प अन्तर्गत के परामर्श-कार्य के रूप में काम करें अथवा उच्च, उनका निर्माण भी बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में उद्योग प्रविष्टि तथा विश्वविद्यालय विभागों के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थाओं का स्थापना तथा भी और के अन्तर्गत

पर वे एक साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी सम्भव हो धीरे-धीरे सुविधाएँ उपलब्ध हो ता मारतवय में भी इस प्रकार के प्रयत्न विद्यमान हो सकते हैं।

1.1] मारत में ऐसा बहुत भी सम्भाव्य है जो विश्वविद्यालय की तरह का अनुसंधान-कार्य सामान्यतः करना है। लेकिन जिनका वायद्योत विश्वविद्यालय में बाहर हो है। प्रयत्न विद्यमान चाहिये कि वे विश्वविद्यालय में काम करें। यद्यपि कम से कम इतना तो हो ही भवना है कि वे विश्वविद्यालय में सम्निष्ठ सम्पन्न रहते हुए अपने कार्य का आग बढ़ाते रहें।

1.2 राष्ट्रीय विज्ञान नीति

सर्वोच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे वैज्ञानिक विषयों पर यथा सम्भव निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ सम्मति प्राप्त कर सकने के प्रति आग्रह रखें हो सकें। उनके लिये एक ऐसे सलाहकार मंडल का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में सम्मिलित प्रमुख अभिकर्ताओं के प्रधानों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी सदस्य होने चाहिये जो अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान तथा उच्च स्थािति प्राप्त होने के साथ साथ स्वयं के प्रति निष्ठावान उत्पन्न करने वाले भी हों। 30 वर्ष की आयुवाले कुछ प्रमुख युवक वैज्ञानिक भी इसमें सदस्य होने चाहिये। एक व्यक्ति का भी सम्मति अधिकारों के प्रधानों की सहाय में काम करनी जानी चाहिये। विश्वविद्यालयों, सरकारी अथवा गैर-सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों, उद्योगों तथा सामान्य जनता में से इन लोगों का चयन किया जा सकता है। हम मन्त्रालय मण्डल में बसने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकज्ञ भी नहीं अपितु अग्रणी एवं सामाजिक विज्ञानवेत्ताओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति भी जान चाहिये जिन्हें उद्योग एवं व्यवसाय सम्बंधी अनुभव प्राप्त हैं। मन्त्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति का उत्तम आधार पर पुनर्गठित करने के साथ-साथ उस एक प्रभावशाली सचिवालय उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा इस कार्य की जिम्मेदार बनने में सक्षम व्यक्तियों को इसमें साथ सम्मिलित किया जाना चाहिये। समिति के लिये भी जानें चाहिये कि वह टांग की तथा विश्वविद्यालयों की मुख्य वैज्ञानिक आवश्यकताओं का अनुमान लगा सके तथा सरकार की वैज्ञानिक नीति तथा विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध साधन के सम्बंध में सम्मति दे सके। राष्ट्रीय अनुसंधान नीति की स्थिति का पुनर्विचार भी हम समिति को निम्नरूप करने चाहिये।

1.3 कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय

प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना

जानी चाहिए। ऐसा करने के लिए ध्यतमान विश्वविद्यालयों में सज्जित विश्वविद्यालय का कृषि विश्वविद्यालय में रूपांतरित करने की सम्भावना में ध्यान में रखना चाहिए।

इस कृषि विश्वविद्यालय का कृषि सम्बन्धी परम्परागत विशेषताओं के अन्तर्गत सज्जित काय प्रारम्भ करने समय की आवश्यकताओं के अनुसृत प्रेरणादायकता का विस्तार निम्नतर करने के लिए। स्नातकोत्तर का शिक्षण व्यवस्था उपेक्षित क्षेत्रों का शिक्षा के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध बनाना इनके वरिष्ठ कार्य में सज्जित काय होना चाहिए। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस स्तर पर सर्वोच्च स्तर का भावनाय रखना होगा।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्यकृषि विभागों के दायित्वों में स्पष्ट रखा जाना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रमाण कायक्रमों का सम्पन्न करें।

151 प्रमाण के तौर पर यद्यपि कुछ छूट दी जानी चाहिए तथापि यह अनिवार्य है कि ऐसा कृषि विश्वविद्यालयों का किही एक में मन्त्रवर्णन निम्नता का मानकर बनना चाहिए जहाँ एक प्रांगण विश्वविद्यालयों पर्याप्त महा विद्यालय इन विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध न हो। निपुण छात्रों का आश्रय देने के लिए छात्रवृत्तियों का उत्तर ध्यरस्या (25% छात्रों का छात्रवृत्तियों) पर्याप्त आकार के मुख्यस्थित काम तथा कमचारी वगैरह का वेतन एवं विश्वविद्यालयों के कमचारियों के वेतन के समान होना चाहिए।

152-कृषि विश्वविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्येक विश्वविद्यालय जहाँ कि कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि मन्त्रालय है तथा जो कृषि अध्ययन की यज्ञाया देना चाहता है जो उच्च दृष्टिकोण महापता में जानी चाहिए तथा कृषि क्षेत्र में मुख्य धन उत्तर देना कार्य का कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य में पर्याप्त तात्त्विक होना चाहिए।

153 कृषि विश्वविद्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शक्ति सम्बन्ध शक्तिगत विषय जानी चाहिए। इन सम्बन्ध बनाने के लिए प्रत्येक काय क्रमों के अन्तर्गत मान्य और कमचारी-वगैरह का आकार प्रमाण दिया जा सकता है अध्ययन एवं अनुसंधान के समान कायक्रम ध्यतया जा सकता है। ऐसी ही का औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षणों तथा कुछ मुख्य विश्वविद्यालयों में कृषि विभाग गठित करने का सम्भावनाओं की भी जांच की जानी चाहिए।

154 ऊपर सुझाव एवं कृषि विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित विस्तार के लिए मन्त्र कृषि विश्वविद्यालय नहीं मान्य जानी चाहिए किन्तु वर्तमान कृषि महा

विद्यालयों में स्तर सम्बन्धी सुधार लाने के लिए एकाग्र प्रयत्न किए जाने चाहिए। भाग्यशाली कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए धार) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त रूप से इन कृषि महाविद्यालयों का हर एक क्षेत्र निरीक्षण करना चाहिए तथा एस महाविद्यालयों जिनका कि पर्याप्त ऊँचा स्तर नहीं है, उनका उच्च तकनीकी स्तर की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में रूपान्तरण किया जा सकता है या फिर उन्हें समन्वित किया जा सकता है।

158 इजीनियरों की शिक्षा

एक दस वर्षों में इजीनियरों की प्रशिक्षण में पर्याप्त प्रगति हुई है। इन चार दिशाओं में और भी प्रगति वांछित है (1) उद्योगों से अधिन के घनिष्ठ सम्पर्क (2) इजीनियरिंग संस्थाओं में व्यावहारिक कार्य पर विशेष धन देने की दृष्टि से सुधारमय सुधार, (3) वर्तमान संस्थाओं का गठन एक एकीकरण प्रोग्राम (4) इजीनियरिंग संस्थाओं मुख्यतः औद्योगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (आई आई टी) में अधिकाधिक समन्वय के आधार पर प्रवेश के घटकर प्रमाण करना।

159 प्रशिक्षण योजनाएँ आरम्भ करने के निमित्त उद्योगों का आत्माहित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाएँ उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उपदान देने की केन्द्रीय योजना का भी आरम्भ किया जा सकता है। गावजतिक क्षेत्र से सम्बंधित उद्योगों का इस कार्य के लिए बजट में धृक्क में प्रावधान किया जा सकता है। जो उद्योग अथवा उद्योग संगठन प्रशिक्षण सुविधाएँ देते हैं वहाँ उचित एक योग्य प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। औद्योगिक एक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कार्य का पुनर्विस्तार करने के लिए नियमित रूप में मिला रहना चाहिए।

उद्योग सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करने की शिक्षा में इजीनियरों अनुसंधान कार्य का अधिकाधिक अग्रसर किया जाना चाहिए तथा उद्योगों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्बंधी अनुसंधान कार्य का जहाँ आवश्यक हो वहाँ वर्षों का अर्थ में विभिन्न सत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग अनुसंधान कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। उद्योगों में डिजाइन दस्तावेजों का कार्य तथा व्यावहारिक विकास करने करने के आधार पर उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने की सुविधा भी दी जानी चाहिए।

160 निम्न बिन्दुओं के आधार पर इजीनियरों की शिक्षा में वहाँ अधिकाधिक सुधार करना होगा

(1) आधारभूत विज्ञानों के शिक्षण का सुदृढ किया जाना चाहिए

ताकि हमारे इजानियरो में मे मुख्यतः जो अनुमोदन विनास तथा तकनीकी
क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वे अधिकारिण नाम उठा सकें।

(11) पाठ्यक्रम के तामने वष में ही पूरागाना छात्र के लिए
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। उद्योगों के
महोपाय में इन कार्यक्रमों का मावधानी से निर्माण किया जाना चाहिए तथा
उनका उचित परियोजना किया जाना चाहिए एवं इन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति
के पूर्व ही पूरा किया जाना चाहिए।

जहाँ सम्भव हो शक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाने चाहिए। दोनो
ही निर्धारित पाठ्यक्रमों तथा अवकाश अवधि में छात्र को अध्यापक द्वारा
गतिवत् समस्याओं में उपयोगी उपकरणों पर भाष्य करने तथा उनकी
विशाल ज्ञान के साथ द्वारा कार्यकारी में किया जाना वाले अध्यापक को
अधिकाधिक उत्साहानुभव प्रदाना जा सकता है। अध्यापक (Project)
के रूप में उद्योगों का उपयोग सम्बन्धी समस्याएँ छात्रों को निराकरण हेतु
मौका जा सकती हैं। अध्यापक तथा विश्वविद्यालय विभागों को इस बात के
लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे उद्योगों में सप्ताह भर बिना
तथा अवकाश के जिन में उद्योगों में जाकर काम करें। अध्यापकों को
विद्यार्थियों में अध्यापक तथा उद्योगों के बीच व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित
करने के अधिकारिण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
में प्रवेश करने में वृद्धि के लिए उद्योगों में छात्रों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त
करना स्नातकोत्तर के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

(12) उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के दशवर्षीय
तथा लघुवर्षीय के लिए विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रमों में सामान्य अध्यापन
कराए हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त रूप में परिवर्तित किया जाय
तथा पाठ्यक्रम लघुवर्षीय के निर्माण हेतु बनमात्र तब नई समस्याओं में
बताव जाय या पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण रूप में नई किया जा जाय। उद्योगों
का अध्यापकों को आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए जिन प्रकार के विभाषणों
प्राप्त करने के लिए उन्हें उनका लिए निर्माण तथा में सम्बन्धी पाठ्यक्रम
सेवाएँ दिए जाने चाहिए तथा उनका लिए तब पूर्तिनामा भी किया जाने
सकता है।

(13) उद्योगों का आवश्यकताओं में अध्यापकों तथा तकनीकी
संस्थान अधिकाधिक सम्बन्धित रह सकें। यह निर्माण आवश्यक है कि उद्योगों द्वारा
दिए गए मावधानी में अनुसंधान कार्य निर्माण (Research design)
परिष्कारों का पाठ्यक्रमों का एक भाग माना जाए।

(१) विगपन समितियों के सलाह महाविर से पाठ्यक्रम में निरन्तर सहायन होत रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जड़ एकरूपता से बचा जा सके। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अवधि के सम्बन्ध में एकरूपता तान की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी अवधि चुनिन्दा क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार एक से दो वर्षों के बीच हो सकती है।

161 निकट भविष्य में नया संस्थापना अधिनियम बड़े पैमाने पर वनस्पति विभाग पर नहीं बरतित (क) वर्तमान संस्थापना को अधिनियम सोमा तन बढ़ाने, (ख) अधिनियम का दूर का समाप्त करने तथा जिज्ञासु में गुणात्मक सुधार करने, और (ग) मेवारन व्यक्तियों के लिए सेवावासीन पाठ्यक्रमों सम्बन्धी व्यवस्था करने पर विचार करने लिया जाना चाहिए।

162 इजानियरिंग महाविद्यालयों तथा मुख्यतः आई आई टाउन में प्रवेश सम्बन्धी अवसरों के समन्वय का नियमित करने की आवश्यकता है। प्रवेश का आधार केवल अवधि प्राप्ति का ही नहीं मानकर एकाग्र प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रवेशार्थियों का प्राथमिक तौर पर एक से अधिक क्षेत्रों में से चुनाव करने का सुविधा हो। तथा अनिवार्य छात्रों का योग्यता का उनकी वास्तविक उपलब्धि की गैरानुपेक्षा में तुलनात्मक दृष्टि में भाँका जाना चाहिए।

163 शक्तिशाली छात्रों का पुनर्गठन

गत वर्षों में देश के प्रत्येक भाग में शक्तिशाली छात्रों के पुनर्गठन तथा विद्यालय में महाविद्यालयों का कक्षाओं में अपनायत जान वाली गमन पद्धति के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। गुणात्मक सुधार सम्बन्धी जो ऊपर सुभाषित नियम हैं उनका दृढ़तः हूए पन बाँटने का काम हो आवश्यकता प्राप्त है। फिर भी शक्तिशाली छात्रों में कुछ परिवर्तन निम्नलिखित नामदायर होंगे, यदि इन्हें निम्नलिखित अधिनियम जान मान प्रस्तावित शक्तिशाली पुनर्गठन के कार्यक्रम के अर्थात् अग्रणी अवधि के रूप में कार्यवाही किया जाए।

164 नये शक्तिशाली छात्रों का स्वरूप हम प्रकार होना चाहिए

—एक से तीन वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा,

—सत्रार्थीय मामलों शिक्षा जिसमें तरह किमती किया जा सकता है प्राथमिक शिक्षा 7-11 वर्ष (निम्न प्राथमिक स्तर धार या पाँच वर्ष उच्च प्राथमिक ता 11 या 12 वर्ष) तथा निम्न माध्यमिक स्तर का शिक्षा तीन या दो वर्ष अवधि एक से तीन वर्ष का अग्रणी गतिविधि शिक्षा (आवश्यकता पाठ्यक्रम में प्रवेश का शिक्षा पुनर्गठन का 20, हा)

—उच्चतर माध्यमिक स्तर का सामान्य शिक्षा दो वर्ष प्रथम एवं
म तीन वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा और

—उच्च शिक्षा स्तर—तीन वर्ष या अधिक प्रथम स्नातक उपाधि के
लिए तथा दूसरी प्रथम अनुसंधान उपाधियों के लिए विभिन्न
प्रवधि के पाठ्यक्रम ।

यहना कक्षा में प्रवेश की आयु सामान्य छ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।
अथ कक्षा में प्रवेश आयु सामान्य निर्धारित करने की कार्य आवश्यकता
नहीं है ।

165 शक्ति ढींच के पुनर्गठन के इस कार्यक्रम का तीन और से प्रारम्भ
करना होगा । प्रथम है देश के सभी हिस्सों में दसवर्षीय विद्यालय व्यवस्था
प्रारम्भ करना । इस सम्बन्ध में केवल भूखंड तथा उत्तर प्रदेश में कोई समस्या
उत्पन्न नहीं होगी । जिन राज्यों में (माध्यमिक अथवा नागालैंड बिहार
गुजरात मणिपुर महाराष्ट्र और उज्जयिनी) इस समय विद्यालय स्थापना प्रमाण-पत्र
प्राप्त करने का अधि 11 या 12 वर्ष के सभी पाठ्यक्रम को मुख्यवर्षिक
करना होगा तबिन नये ढींच का अपनाया जा सके और इस प्रकार विद्यालय
शिक्षा की अवधि दस वर्ष हो जाय । इन राज्यों में जहाँ कि माध्यमिक शिक्षा
आयोग का गिफारिजों के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति अधिन
प्रचलन में है वहाँ निम्न तरीके अपनाये जायेंगे

(i) एक लिए प्रत्येक माध्यमिक स्तर के विद्यालय का उच्चतर
माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है । केवल अधि
विद्यालय तथा अधि कुल उच्च विद्यालय—कुल संख्या का लगभग एक
चौथाई—का उन्नत शिक्षा प्राप्त चाहिए । इस दृष्टि में सभी वर्तमान उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय के स्तर का पुनर्चिन्ता करने किया जाना चाहिए तथा जो
उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय का करने के योग्य न हो उन्हें उच्च
विद्यालय बना दिया जाना चाहिए ।

(ii) धारावाहिक पद्धति (Streaming) का त्याग किया जाना
चाहिए तथा नियमन कक्षा बार में कोई मुश्किल पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया
जाना चाहिए । कक्षा 9 व 10 प्रथम वर्षीय सामान्य शिक्षा तथा कक्षा
11 उच्चतर माध्यमिक स्तर का धारावाहिक शिक्षा चाहिए । कक्षा 11 में विभिन्न
विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का व्यवस्था की जाना चाहिए ।

(iii) कक्षा 12 के बाद एक बार परीक्षा देना जाना चाहिए और दूसरी
बार परीक्षा कक्षा 1 के बाद । 10 वर्षीय उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों
को एक ही बार परीक्षा देना में देना होगा । यही उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों के छात्रों के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए। व चाहें तो कक्षा 11 के बाद एक अंतिम परीक्षा दे दें अथवा दो सिस्मा में अर्पण कक्षा 10 और कक्षा 11 के बाद।

166 इस कार्यक्रम का दूसरा बिंदु यह है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा का विकास निम्न प्रकार से किया जाय

(1) उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालयी शिक्षा का भग घोषित किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हाथों में इसका प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाना चाहिए।

(ii) इस स्तर का शिक्षा विनियमन अधिकांशतः मन्त्रिपालिका में और बहुत ही कम मर्यादा में कुछ चुन चुन हुए विद्यालयों में कार्यक्रम की जानी चाहिए। अधिसूचित अधिकांश विद्यालयों की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-स्तर तक उन्नत किया जाने तथा विश्वविद्यालयों और बड़े महाविद्यालयों, मुख्यतः स्नातकोत्तर मन्त्रिपालिकाओं से इन उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं का समाप्त करने के प्रयत्न किये जान चाहिए। अतः केवल 20% माध्यमिक विद्यालयों तथा 30% महाविद्यालयों में ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो।

(iii) 10 से 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत कार्यक्रम द्वारा इस स्तर का शिक्षा की अवधि समान रूप से दो वर्ष बढ़ानी होगी।

167 विश्वविद्यालय स्तर पर मुख्य समस्या उत्तरप्रदेश में है जहाँ कि कला, विज्ञान और वाणिज्य में प्रथम स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तान बढ़ करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी 15 से 20 वर्ष की अवधि में कोई नैतिक कार्यक्रम अपनाया होगा।

168 इस पुनर्गठन के कार्य में स्तर उन्नत करने का सत्य निरन्तर सामने बने रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि अनेक छात्रों का प्रवेश देन तथा उपलब्ध सुविधाओं के अधिकाधिक समुचित उपयोग करने से कम वर्षीय विद्यालयों शिक्षा की समाप्ति पर ऐसा स्तर प्राप्त किया जा सके जो कि वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 11 वर्षीय शिक्षा के उपरान्त प्राप्त किया जा रहा है। परिलक्ष्य प्रथम स्नातक उपाधि की शिक्षा का स्तर उन्नत होगा, विशेषतः तब तो और भी जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि समान रूप से दो वर्ष की हो जायेगी। वस्तुतः मध्यम की प्रथम स्नातक उपाधि का स्तर वह होना चाहिए जो वर्तमान में स्नातकोत्तर उपाधि का स्तर है तब ही छात्र स्वयं को अनुसंधान कार्य के सार्वभौमिक रूप पर पहुँचा होगा। ऐसा होने पर हमारे देश का स्तर अन्तराष्ट्रीय स्तर के अनुकूल हो जायेगा, क्योंकि इस समय हमारे देश का

विज्ञान एवं वाणिज्य का स्नातकात्तर उपाधि का स्तर सामान्यतः विद्वानां व प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रथम स्नातक उपाधि व स्तर के समान है।

169 प्रौढ़ शिक्षा

निरक्षरता की समस्या तथा सभी लोगों में व सभी स्तर का शिक्षा व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण तथा स्वशिक्षण शिक्षा व विकास से सम्बंधित कार्यक्रमों का उत्तम रूप पर किया जा चुका है। प्रशिक्षण तथा स्वशिक्षण शिक्षा का विकास करने उन लोगों के लिए ही नहीं करना है जिन्हें औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना है बल्कि उन लोगों के लिए भी जो बिना कोई परीक्षा किए अपने ज्ञान और अपनी कुशलता में वृद्धि करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण आवश्यकता तो यह है कि कमचारियों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके कि वे अपने ज्ञान और अपनी कुशलता में वृद्धि कर सकें, कि जीवन में नूतन विज्ञान प्राप्त कर सकें तथा अपने व्यवसाय में प्रगति कर सकें। पुस्तकालय समाचार समिति द्वारा किए गये अनुमानों के अनुरूप पुस्तकालय सम्बंध मुद्रिकाओं में गुणार तथा उनका विस्तार करने की भी आवश्यकता है।

170 विश्वविद्यालयों तथा समाज के बीच घनिष्ठ सम्बंध विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि प्राधुनिक विश्व में समाज तथा विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। इनके विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और समाज में घनिष्ठ सम्बंध हो। स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं का सम्मीरतापूर्वक अध्ययन करावाले अभिवर्तन की तरह ही विश्वविद्यालयों का कार्य करना चाहिए ताकि सरकार अपना प्रयत्न निम्न समूहों पर करने पर इन समस्याओं के सम्बंध में उचित सम्मति प्राप्त कर सके उनमें निम्न लें सके। इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परीक्षाओं के सम्बंध में ही नहीं ध्यान देना चाहिए कि वे किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। कमचारियों का समावेश शिक्षा के लिए या पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम बनाने तथा शिक्षण के लिए जाने चाहिये। व्यवस्था की सामान्य शिक्षा में सम्बंधित कार्यक्रम या नए दृष्टि में बना सकते हैं कि जनसाधारण तब शिक्षा-योग के साथ दृष्टिकोण की एकता तथा सामान्य शिक्षा बन सके। ध्यान दिया जाना है कि सामान्य-नैतिक-योग का बहुत बड़ा ध्यान उन शिक्षण स्तर का है जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने योग्य हो नहीं है। किन्तु हम नेता-योग के प्रगतिशील प्रयत्न ध्यान प्रकार के दृष्टिकोण पर ही हमें काम करना चाहिये। यह ध्यान है कि विश्वविद्यालय एवं विभिन्न प्रकार-कार्यक्रम प्रदान किए इन नेता योग में राष्ट्र में विकास में सम्बंधित मानव सम्पदाओं के

प्रति समझ उत्पन्न हो सके ।

171 इन तथा ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालयों का पर्याप्त व्ययस्था उपलब्ध होना चाहिए । इसके लिए उपकुलपति की अध्यक्षता में एक प्रौढ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो नीति निर्धारण करे, कार्यक्रम बनाये तथा विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर उनका कार्यान्वित करे । बोर्ड द्वारा स्थापित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारी वृत्त का व्यवस्था भी होनी चाहिए । हम यहाँ भी अनुभव करते हैं कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों को प्रौढ शिक्षा के विभाग विकसित करने चाहिए । शिक्षकों तथा विशेषज्ञों का प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र का प्रशिक्षण देना शिक्षा समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान के विभागों के सहयोग से प्रौढ शिक्षा का समस्त समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसंधानकार्य को कार्यान्वित करना, उसका निर्देशन करना इन विभागों का सदैव होना चाहिए ।

172 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, सदैव यह रहे कि 1966 तक हमें 3 5 वर्ष के 5 प्रतिशत बालकों का प्रवेश दिया जाय । ऐसी शिक्षा के विनाश हेतु कम सर्वांगीण पद्धतियों पर विशेष बल देने का आवश्यकता है, ये पद्धतियाँ चाहे मद्रास में चल रही पद्धति के अनुरूप हों चाहे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए बाल केंद्रों के रूप में हों ।

राज्य का चाहिए कि वह जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए विनाश केन्द्रों की स्थापना करे, पूर्व प्राथमिक अध्ययन का प्रतिनिधित्व करे, साथ कार्यक्रम अपनाए तथा आवश्यक माहिरता तैयार करवाए । साधारण तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का सम्बन्ध निम्नी प्रणाली के लिए छाड़ दिया जाना चाहिए, चाहे तो राज्य उन्हें समन्वय के आधार पर प्राथमिक सहायता दे सके है ।

173 शैक्षिक भवन

विद्यालय भवन की समस्या पर शोध ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । हम सम्बन्ध में अपनायी गयी नीति बहुधा असंगत रही है । यद्यपि कृषिों का छाया में विद्यालय के छात्रों का व्यवहारिक रूप में प्रभाव देने के बहुधा प्रयत्न हुए हैं किन्तु इन्होंने साथ-साथ भवन योजनाओं के निर्माण के अन्तर्गत मूल्यवान तथा ऐंग्रेजी पाठ्यक्रम सम्बन्धित भवन भी प्रमुक्तता प्राप्त करते रहे हैं । प्राथमिक शिक्षा केंद्रों, निर्माण की सामग्री कम करने तथा

शास्त्रता में भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में हमारा दृष्टि तथ्यात्मक होने आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कामचम भवनाय जान का सुभाव है

(1) अधिक मात्रा में आवंटन—विद्यालय भवनों का वनमान धमन्तापजनक स्थिति का दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि धर्मात्मिक विद्यालय भवना की भूतला की पूर्ति की जाय तथा नये प्रवर्गाधियों के लिए अतिरिक्त भवन बनाय जायें।

(11) कन्द्रीय तथा राज्य बजट में विद्यालय भवना के निर्माण हेतु आवंटित राशि में अतिरिक्त की जाना चाहिए तथा अन्य सामाजिक साधनों का समन्वय के आधार पर अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। निजी विद्यालयों का भवन निर्माण हेतु अलग तथा अनुमान राशि उधारता पूर्वक स्वीकृत की जाना चाहिए।

(111) कीमत में कमी—विद्यालय भवन निर्माण की योजना तथा प्राप्त स्थान के उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी का व्यावहारिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

(12) भवन निर्माण में प्रयुक्त हानिकारक परम्पारिक सामग्री के अभाव तथा उनकी बढ़ा हुई कीमतों का स्थिति में सुनिश्चित बन्ध निर्माणों की विद्यालय भवन व्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया जाना चाहिए।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में भवन—ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु स्थानीय प्रयत्नों तथा अन्य उपायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय के कन्द्रीय (Nucleus) पद्धति के सुभाव का सामाजिक अनुगमन किया जाना का विकारित का जानी है।

(14) नगर क्षेत्रों में भवन—इस क्षेत्र में बनने वाले भवनों में स्थानीय उपायों सामग्री के उपयोग द्वारा भवन निर्माण समाप्ति पर की जायें। कुछ विचार प्रकार का सजावट को दृष्टि देना तथा कारीगरों की दृष्टि में कुछ निम्न धरणा के निर्मित भवनों के उपयोग द्वारा भवन निर्माण में हानि घटाने के साथ ही भवन की जानी चाहिए। जहाँ वही सम्भव हो बन्ध प्रयोगों की वृद्धि के लिए जानें तथा निर्माण को विकसित सामग्री का परम भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाय।

(15) शीघ्र भवन निर्माण—विद्यालय भवनों सम्बन्धी सुविधा की शीघ्र पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ प्रयासों का तथा नगर क्षेत्रों में सम्पत्तिधियों तथा परिवारों का भवन निर्माण काय होता या स्थिति है।

(viii) विद्यालय भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने तथा उसे निर्देशित करने हेतु प्रत्येक राज्य में सावजनिक निर्माण विभागों तथा एक शक्ति भवन विकास मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए जो शिक्षा विभाग के निर्यात सम्पर्क में रहकर कार्य करेंगे। ये प्रस्तावित मण्डल उन क्षेत्रों में होने वाले भवन निर्माण का स्तर सम्बन्धी विवरण तयार करेंगे ताकि बारम्बार में होने वाले उत्पादन की तरह आवश्यक उपकरणों को अधिक मात्रा में तयार किया जा सके। राज्य मण्डलों के कार्यक्रमों में आवश्यक ताल मेल बनाये रखने हेतु इसी तरह के द्वारा स्तर पर एक भवन विकास मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए।

(ix) राजकीय भवनों के निर्माण में होने वाले वित्तम्ब की राशियाँ एक शक्ति भवन निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निर्माण विभाग में एक पृथक् इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। बाद में शक्ति भवन सामाजिक समिति (नगरसमितियाँ) की स्थापना की जा सकती है ताकि औद्योगिक आधार पर बने भवनों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

(x) शक्ति भवन विकास मण्डल द्वारा अपनाय गये कम गतिविधि साधनों की जानकारी निजी संस्थाओं को भी दी जानी चाहिए तथा इन संस्थाओं का अधिकतम व्यय सीमा के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए।

174 शक्ति अनुसंधान

शक्ति अनुसंधान को विकसित करने तथा अनुसंधान कार्य का शक्ति नीति निर्धारण व शिक्षा के आधार पर लोगों में प्रभावपूर्ण तरीके से सम्बद्ध करने के निमित्त शास्त्र उपाय नियोजित किये जाने चाहिये। इस दृष्टि में निम्नीय विषय कार्यक्रमों का विकास किये जाने का आवश्यकता है।

(i) राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान एक प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत एक प्रयोग (Documentation) तथा विवरण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए।

(ii) अन्तर्मुखित विषयों में शक्ति अनुसंधान कार्य का दस्तावेज बनाने के लिए विचारित किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि मनुष्य प्रशिक्षण महाविद्यालय किसी न किसी प्रकार का पाठ्य-कार्य करें किन्तु कार्य के हाथ-काय करें साथ नहीं, ऐसा करने में अनुसंधान कार्य का प्रयोजन में बाधा पड़ती है। शिक्षापीठों (Schools of Education) का यह विशेष शक्ति है कि वे अध्ययन विभागों के महाविद्यालय में शक्ति अनुसंधान कार्य में महती समिष्टि करें।

(iii) यह वास्तविक है कि शक्ति विचार एवं अनुसंधान का विकास करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान मस्यान जमी ही एक राष्ट्रीय शिक्षा मस्यान का स्थापना का जाय जिसके मध्य प्रमुख शिक्षाशास्त्री हों। यह मस्यान प्रावश्य रूप से गैर सरकारी व्यावसायिक संगठन होना चाहिए, किंतु इस भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए।

(iv) अनुसंधान में प्रगति हेतु शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक शक्ति अनुसंधान परिषद् की स्थापना का जाना चाहिए।

(v) अनुसंधान काय प्राप्त सूचनाओं के वर्गीकरण तथा आवृत्ति के विवक्षित एवं उन पर विचार विमर्श हेतु शिक्षित प्रशिक्षण लिये जाने की तीव्र आवश्यकता है।

(vi) राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सस्यान तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का दायित्व होना चाहिए कि शक्ति अनुसंधान एवं विद्यालय में प्रचलित सम्प्रदाय के मध्य गहरी खाई को गमाते करें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग का भाग ले प्रयत्न करने होंगे।

(vii) शक्ति अनुसंधान पर ज्ञान बात कुछ समय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करनी होगी तब यह है कि राज्य द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का 1 प्रतिशत अनुसंधान काय पर खर्च किया जाए।

शैक्षिक आयोजना, प्रशासन तथा वित्त

175 यदि पूर्वगामी अध्याया में उल्लिखित शैक्षिक पुनर्गठन के विषात काम्रम का सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित किया जाना है तो आवश्यक है कि —

—शैक्षिक आयोजना में सुधार किया जाय

—केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन किया जाय।

—शिक्षा के विकास में मयासम्भव अधिक साधनों का उपलब्ध किया जाय और जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका मितव्ययता के आधार पर सदुपयोग किया जाय, और

—हड़तापूर्वक एवं दीर्घकालिक समय तक क्रियान्वित करने के लिए कोई काम्रम अपनाया जाय।

नए प्रतिष्ठान अध्याय में इन काम्रमों पर कुछ विस्तार से चर्चा की जायेगी।

176 शैक्षिक आयोजना

शैक्षिक आयोजना की सफलता के लिए निम्न बिन्दु अनिवार्य हैं

(i) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का कोई एक ऐसा विभाजित ढाँचा हो जिसके अंतर्गत स्थानात्मक मिश्रताओं के आधार पर सामञ्जस्य स्थापित करते हुए राज्य सरकारें तथा स्थानीय अधिकारी अपनी ही कोई योजना बना सकें और उसे कार्यान्वित कर सकें।

(ii) 20 वर्षों की अवधि में विभक्त शिक्षा के सम्भावित विकास की सम्पूर्ण राशिकालिक योजना बनायी जाय। उक्त सम्भावित योजना को दृष्टि में रखते हुए तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर शिक्षा विकास की पंच वार्षिक तथा वार्षिक योजनाएँ बनायी जा सकती हैं। शिक्षा आयोग द्वारा तैयार की गयी योजना के आधार पर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का रूपरेखा तथा शिक्षा के सम्भावित विकास का सम्पूर्ण एवं दीर्घकालिक योजना तैयार की जा सकेगी।

177 भारत की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अधिकाधिक महत्वपूर्ण अपनी प्रत्येक

निरणय लिय जान का प्रचलन है। स्थानीय स्तर पर शक्ति का याचना के निमित्त कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है। कई बार इसका परिणाम यह होता है कि स्थानीय परिस्थितियों का नजरान्नाज कर लिया जाता है और इस प्रकार राज्य की पहचान करने की क्षमता हो समाप्त हो जाती है। अतएव यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राज्य तथा स्थानीय अर्थात् तीनों स्तरों पर प्राथमिकता क्रम का प्रयोजन हो। प्रत्येक स्तर का अर्थ एवं प्रभावशाली प्राथमिक शिक्षा का मुद्रिका माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक स्तर शिक्षा एवं अनुसंधान अथवा कृषि एवं उद्योग की शिक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता इन अर्थों में प्रदान की जाए कि उनके सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिये जाए व उन्हें तथा राज्यों में विचार विमर्श करके ही लिए जाएँ और जब एक बार निर्णय ले लिया जायगा प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य हो जाता चाहिए कि वह उनका प्रभावपूर्ण तरीके से हड़तापूर्वक निष्पादित करे। अन्य दूसरे मामलों में जिनकी समस्या बड़ी अधिक होगी, राज्यस्तरीय प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए अर्थात् प्रत्येक राज्य का स्वतन्त्रता है ताकि स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वह उनके अनुसंधान लिये निर्णय ले सके। इनके अन्तर्गत ऐसा समस्याएँ भी सम्मिलित हैं जहाँ कि माध्यमिक शिक्षा निष्पन्न की जाए अथवा नहीं। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर अवस्था स्थापित करने का कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यालयों में मुद्रिका प्रयोग करना तथा अध्यापकों पर न किये जानेवाले अध्ययन के स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय लेने चाहिए। सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों में स्थानीय प्राथमिकताओं का आधार पर कोई व्यवस्था अपनाई जाए। जिला एवं विद्यालय स्तर पर राज्य सरकारें उचित अधिकारियों की एसी शक्तियों प्रदान कर सकती हैं कि वे प्रयासपूर्वक शक्तियों की माताओं का मातृ मीटर एके स्वतन्त्र निर्णय ले सके जो कि स्थानीय परिस्थितियों का लक्ष्य अनुसंधान हों। इन मामलों में एक दिन में दूसरे दिने अथवा एक विद्यालय में दूसरे विद्यालय में शिक्षा का प्रकार का समानता बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती चाहिए।

178 प्रथम तीन पक्षधरों मातृताओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये कार्यों का पुनर्विचार करने के लिए है कि कुछ क्षेत्रों में मातृता की महत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(i) मातृता एवं अन्य पर आवश्यकता से अधिक ध्यान

मातृता तथा अन्य मातृताओं के मातृता के मातृता पर आवश्यकता का

अधिक बल दिया जाता रहा है। यह सत्य है कि विस्तार की बहुत ही आवश्यकता थी, विस्तार होता भी रहेगा। किंतु इस पक्ष की आवश्यकता में अधिक महत्व दिये जाने का परिणाम यह हुआ है कि गुणात्मकता जमा महत्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित हो रहा। इसी तरह, व्यय के लक्ष्य की पूर्ति पर अधिक ध्यान दिये जाने के परिणामस्वरूप प्राथमिकताओं के क्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा अपव्यय बढ़ा है। अतः समस्या की उसकी सम्पूर्णता में समझे जाने तथा सामान्य व मुख्यतः गुणात्मक सुधार से सम्बन्धित उद्देश्यों के विना स्वस्वरूप को विकसित करने की आवश्यकता है।

२ सगठित प्रयत्नों की आवश्यकता तथा चयनित पद्धति को अपनाना

प्रथम तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं में सामान्य नीति यह रही कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम अवश्य अपनाया जाये। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भी अल्प साधन उपलब्ध थे वे सब विभिन्न क्षेत्रों में बिखर गये। इस नीति में अप्रवश्य निहित है। अतएव अब यह आवश्यक हो गया है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। जैसे अध्यापकों की योग्यता में सुधार, कृषि शिक्षा का विकास, समस्त बालकों के लिए श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, निरक्षरता का समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, मुख्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, स्नातकोत्तर शिक्षा का विकास एवं उत्तम सुधार, छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि तथा प्रत्येक स्तर पर लगभग दस प्रतिशत संस्थाओं में गुणात्मक विप्लव की सर्वोच्च सीमा।

३ उन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान जिनमें निपुणता तथा कठिन श्रम की आवश्यकता है

आन्तरिक व्यय सम्बन्धी सदियों की पूर्ति पर जो बल दिया जाता रहा है उसका परिणाम यह हुआ है कि वे कार्यक्रम अवश्य कार्यान्वित कर दिये गये हैं जिनमें व्यय करना सामान्य है, अर्थात् भवन निर्माण अथवा नामांकन में वृद्धि। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ऐसे कई कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें अधिक वित्तीय साधन की अपेक्षा सुविचारित प्रयत्न, सगठन, निपुणता तथा कठोर श्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यक्रमों में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

- विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण का माध्यम बनाय जाने के लिए प्राधुनिक भारतीय भाषाओं में आवश्यक साहित्य का उत्पादन,
- गणितीय अनुसंधान,
- परीक्षा पद्धति में सुधार,

- विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण एवं अध्ययन उपकरणों का निर्माण,
- शिक्षण एवं शिक्षा विभागों के अधिकारियों का सवारत प्रशिक्षण,
- परिवीक्षणों का तकनीक में सुधार
- स्थानीय समाज एवं अभिभावकों के सम्बन्धों में सुधार,
- प्रतिभासम्पन्न छात्रों के निमित्त निश्चय तथा सम्पन्नता प्रदान करने का व्यवस्था तथा पिछड़े हुए एवं भ्रष्ट विकसित छात्रों को विशेष सहायता ।

इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । ध्यान देने का बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि वित्तीय साधन सीमित हैं अधिक पूँजी को लागत वाले कार्यक्रमों की अपेक्षा इस प्रकार के कम खर्च वाले कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने पर कहीं अधिक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

170 नियंत्रण अधिकारण

शिक्षण प्रशासन का मुख्य मस्यौदा यह है कि केन्द्र राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त सरकारों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का किस प्रकार निर्धारित किया जाए । शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों का है अतएव स्वायत्त रूप से उनका स्थान मुख्य है । किन्तु इसमें दो प्रकार के परिवर्तन किये जाने का आवश्यकता है । एक तर्क तो राज्य सरकारों का विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी दायित्व को स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर वहन करना होगा क्योंकि विद्यालयों के शिक्षण प्रशासन का स्थानीय प्राधिकरण है यथासम्भव नियंत्रण का सम्पन्न होना चाहिए । अतः शिक्षा स्तर पर उक्त विधिवत निर्मित स्थानीय प्राधिकरणों को गौर दिया जाना चाहिए । दूसरा धार उक्त शिक्षा के क्षेत्र उन्हें विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार से मिलकर दायित्व वहन करना होगा । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि

—विद्यालय शिक्षा मुख्य रूप से राज्य एवं स्थानीय माफे पर और

—उच्च शिक्षा केन्द्र एवं राज्य के माफे पर निर्भर करना है ।

यह एक आधारभूत विधान है जिसमें अधिक ध्यायोजना एवं प्रशासन के अन्तर्गत आयोगों के अधिकारण एवं विश्वविद्यालयों के साथ राज्य मन्त्रालय के विभाग का निर्माण होना चाहिए ।

180 केन्द्रीय सरकार के कार्य

परिधान में जो स्थान शिक्षा को प्राप्त है वह भारत के विभागों के लिए सर्वोच्च है । प्राधान्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकारों पर तब अधिकार देना चाहिये जब तक कि वे अपने क्षेत्रों में अधिकारों का उपयोग कर सकें । वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा उपरि

मम्मव है उन प्रयोगों में स्वतन्त्रता तथा सचीतापन बनाये रखना आज की सर्वाधिक आवश्यकता है। अतएव शिक्षा के विकास तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की दिशा में भविष्य के वर्तमान प्रावधानों का मुक्त चर उपमाग किया जाना चाहिए।

181 केन्द्रीय सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि कानूनी एवं तकनीकी क्षेत्रों में संस्थाएँ स्थापित करने के अतिरिक्त वह सामाजिक विज्ञानों में विशेषणता प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना करे। सामाजिक विज्ञानों में मानव विषय तथा शिक्षण विज्ञान भी सम्मिलित है। ये संस्थाएँ विश्वविद्यालयों के पण्डित सम्पद में स्थापित की जानी चाहिए तथा ये विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के अतिरिक्त अलग-स्वरूप होनी चाहिए।

182 केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी केन्द्र शिक्षा का विकास कर सकता है, मुख्यतः दिल्ली में जहाँ कि दूसरे क्षेत्रों के लिए आदेश स्वल्प संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है।

183 निपुणता प्राप्त व्यक्तियों को केन्द्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए तथा सभी मामलों में सम्मति एक महयोग दत्त के उद्देश्य में देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की शर्तों राज्य सरकारों का उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

184 केन्द्रीय एक केन्द्र संचालित क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के माध्यम से केन्द्र को शिक्षा के निमित्त वित्तीय दायित्व वहन करना चाहिए। इसी व्यवस्था के सहारे केन्द्र राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित तथा निर्देशित कर सकता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में अन्तर्गत जाने वाले कार्यक्रमों में से कुछ इस प्रकार हैं

- (i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम में विस्तार,
- (ii) पिछड़ी जातियों के निमित्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम में विस्तार,
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन,
- (iv) कृषि इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा शिक्षा का विभाग, और
- (v) अतिरिक्त अनुसंधान में उन्नति।

केन्द्र संचालित क्षेत्रों के लिए जिन कार्यक्रमों की सिफारिश की जाती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

- (i) शिक्षा प्रशिक्षण,
- (ii) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ,
- (iii) राज्य शिक्षा संस्थानों का विभाग,

परिणति-5

शैक्षिक व्यय

सारणी सरया-1

भारत म कुल शक्षित व्यय 1950-51 स 1965-66 तक

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66 अनुमानित
1 सभी स्तरों म कुल शक्षित व्यय (दल लाग व्ययों म)	1 441	1,897	3 114	6,000
2 वृद्धि का गुणकारी	100	166	301	524
3 प्रति व्यक्ति शक्षित व्यय (र)	3.2	4.8	7.8	12.1
4 वृद्धि का गुणकारी	100	150	241	372
5 कुल राष्ट्रीय धाय (प्रचलित मूल्या क धायार पर) (दल लाग व्ययों म)	95 300	99,800	141,100	210,000
6 वृद्धि का गुणकारी	100	105	115	220
7 प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय धाय (प्रचलित मूल्या क धायार पर)	266.5	250.0	325.6	421.1
8 वृद्धि का गुणकारी	100	96	122	159
9 राष्ट्रीय धाय क प्रतिगत व्यय कुल शक्षित व्यय	1.2	1.9	2.1	2.9
10 वृद्धि का गुणकारी	100	155	200	242
	प्रथम योगना	द्वितीय योगना	तृतीय योगना	चतुर्थ योगना
11 कुल शक्षित व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि 10 C/	127,	115,	117,	

सारणी सख्या -2
भारत में (विभिन्न) स्रोतों द्वारा शिक्षा पर व्यय
(1950 51 से 1965 66 तक)

1950 51 1955 56 1960 61 1965 66
अनुमानित

1	राजकीय				
(i)	कुल व्यय (000 रुपया में)	652,678	1 172 049	2,340,914	4,271,856
(ii)	वृद्धि का सूचकांक	100	179	359	655
(iii)	शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत	57.1	61.8	68.0	71.2
2	स्थानीय प्राधिकरण कोष				
(i)	कुल व्यय (000 रुपया में)	124 987	163 548	224,914	378 031
(ii)	वृद्धि का सूचकांक	100	131	180	302
(iii)	शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत	10.9	8.6	6.5	6.3
3	मुख्य				
(i)	कुल व्यय (000 रुपया में)	233,272	379 033	590,258	918 077
(ii)	वृद्धि का सूचकांक	100	162	253	394
(iii)	शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत	20.4	20.0	17.1	15.3
4	घर-घर				
(i)	कुल व्यय (000 रुपया में)	132 885	181,980	287,715	432,036
(ii)	वृद्धि का सूचकांक	100	137	217	325
(iii)	शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत	11.6	9.6	8.4	7.2
5	वृद्धि की योजना				
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पांचवां
	योजना	योजना	योजना	योजना	योजना
(i)	राजकीय कोष	12.4	14.8	12.8	13.3
(ii)	स्थानीय प्राधिकरण कोष	5.5	6.6	10.9	7.3
(iii)	मुख्य	10.3	9.2	9.2	9.6
(iv)	घर-घर	6.5	9.6	8.5	8.1
	योग				
	शिक्षा धान्य का प्रतिशत	पृ 471			

भारत में लक्ष्यों पर आधारित शिक्षा पर व्यय (1950-51 से 1965-66 तक)

संख्या	कुल व्यय (000 रु में)		कुल व्यय का प्रतिशत		वृद्धि का वार्षिक औसत दर
	1950-51	1965-66	1950-51	1965-66	
अ प्राथमिक स्तर					
1 प्रारम्भिक विद्यालय	1 198	11,000	0.1	0.2	10.0
2 निम्न प्राथमिक विद्यालय	364 813	1,220,500	31.9	20.3	8.4
3 उच्च प्राथमिक विद्यालय	76 990	717,500	6.7	12.0	16.0
योग (प्राथमिक स्तर)	443 031	1 949 000	38.7	32.5	10.4
ब माध्यमिक स्तर					
4 माध्यमिक विद्यालय	290 450	1,181,000	20.1	19.7	11.5
5 व्यावसायिक विद्यालय	36 944	250 000	3.2	4.2	13.6
6 विश्वविद्यालय	23,335	39 920	2.0	0.7	3.6
7 माध्यमिक/इंटरमिडियट शिक्षा बोर्ड	5,338	15 000	0.5	0.8	15.3
योग (द्वितीय स्तर)	296 067	1 515 920	25.9	25.3	11.5
क उच्च माध्यमिक स्तर					
8 उच्च माध्यमिक विद्यालय	49,052	270 000	1.4	1.5	12.0
9 उच्च माध्यमिक विद्यालय	6 256	65,000	0.5	1.1	16.0
10 विज्ञान एवं कला महाविद्यालय	71 711	327,500	6.3	3.5	10.7
11 व्यावसायिक शिक्षा का महाविद्यालय	42 191	350 000	3.7	5.8	15.1
12 विशिष्ट शिक्षा का महाविद्यालय	2 221	17 500	0.2	0.3	11.7
योग (तृतीय स्तर)	171 410	1 030 000	15.0	17.2	12.7
13 (योग प्राथमिक)	910 539	4 494 920	79.6	71.9	11.2
ख सार्वजनिक स्तर					
14 निम्नतम स्तर निर्माण	27,361	114 009	2.4	1.9	10.0
15 मध्यम	99 270	666 055	8.7	11.1	13.5
16 उच्च माध्यमिक स्तर निर्माण	31 456	420 035	3.0	7.0	18.1
17 छात्रावास	18 261	95 463	1.6	1.6	11.7
18 शिक्षक	53 928	207 518	1.7	3.5	9.5
19 योग सार्वजनिक	237 276	1 503 080	20.4	25.1	13.2
20 सर्व योग	1 143 822	6 000 000	100.0	100.0	11.7

सारिणी सख्या-4
कुल शैक्षिक व्यय
(1965-85)

	1965-66	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86
1 1965-66 के मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय आय-वृद्धि में प्रतिवर्ष 6% बढ़ातरी का अनुमान (एक दस साल में)	210 000	231,000	376 000	503 000	673 000
2 वृद्धि का गुणकारक	100	131	179	240	300
3 अनुमानित जन संख्या (दस साल का सख्या में) (Projection) मध्यम स्तर का बहिर्वेशन	495	560	630	695	748
4 वृद्धि का गुणकारक	100	113	127	140	151
5 जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर राष्ट्रीय आय (एक दस साल में)	424	402	597	724	900
6 वृद्धि का गुणकारक	100	118	141	171	212
7 कुल शैक्षिक व्यय (नाना रूपों में) वृद्धि में प्रतिवर्ष 10% बढ़ातरी का अनुमान)	6 000	9 163	15,562	25 013	40 364
8 वृद्धि का गुणकारक	100	161	259	418	673
9 राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल शैक्षिक व्यय का प्रतिशत	2.9	3.4	4.1	5.0	6.0
10 वृद्धि का गुणकारक	100	117	141	172	217
11 प्रति व्यक्ति शैक्षिक व्यय (एक दस साल में)	12.1	17.3	24.7	36.1	44.0
12 वृद्धि का गुणकारक	100	143	204	293	446

सारणी सत्या-5

भारत में लक्ष्यों पर आधारित शैक्षिक व्यय

(1975-76 और 1985-86)

सत्य	शुद्ध व्यय (000 रु म)		शुद्ध व्यय का प्रतिशत	
	1975-76	1985-86	1975-76	1985-86

प्राथमिक

ग्राम प्राथमिक	236 956	488 531	15	12
निम्न प्राथमिक	3 719,220	6 129 616	211	152
उच्च प्राथमिक	2 111 567	5 110 287	158	127
निम्न माध्यमिक	2 132 310	7,072 678	156	175
उच्च माध्यमिक	1 312,336	3,613 519	84	90

निम्न उच्च

विद्यालय	389 050	1 611 360	25	10
समयवृत्ति	301 680	1 190 210	19	37

योग (विद्यालय)

	10 873 119	25 579 121	699	691
--	------------	------------	-----	-----

ग्राम स्नातक	1 892,766	1 238 963	122	10
स्नातक स्तर	1,121 200	1 013 400	72	100
समयवृत्ति	628 200	2 116 200	10	60

ग्राम उच्च शिक्षा	3 615 166	10,698 563	231	265
-------------------	-----------	------------	-----	-----

ग्रोस शिक्षा	77 810	403 610	05	10
--------------	--------	---------	----	----

योग (ग्राम स्तर)	11 596 093	36 681 621	938	909
------------------	------------	------------	-----	-----

ग्रोस

विद्यालय शिक्षा	359 050	1 008 590	25	23
उच्च शिक्षा	376 559	2 673 496	37	66

सारिणी सख्या-6
प्रति छात्र औसत वार्षिक लागत
(1950 51 से 1985 86 तक)

वर्ष	प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय	प्रति छात्र औसत छात्र संख्या	गैर-मध्यमशिक्षण लागत का छात्र औसत से अनुपात	औसत वार्षिक लागत		
				मध्यमशिक्षण लागत के कारण	गैर-मध्यमशिक्षण लागत के कारण	योग
				रु	रु	रु
पूव प्राथमिक शिक्षा						
1950-51	914	25	51 3	37	19	55
1965 66	1,000	31	56 3	35	20	55
1975 76	1 800	40	50 0	50	25	74
1985 86	2,500	40	50 0	69	34	103
निम्न प्राथमिक शिक्षा						
1950 51	545	34	24 6	16	4	20
1965-66	1 046	38	11 1	27	3	30
1975 76	1,800	50	20 2	43	9	52
1985 86	2 500	45	19 6	67	18	80
उच्च प्राथमिक शिक्षा						
1950 51	682	24	32 0	28	9	37
1965 66	1 087	31	12 4	40	5	45
1975 76	2 100	35	20 0	73	14	87
1985 86	2 875	35	20 0	99	20	119
निम्न माध्यमिक शिक्षा (साधारण)						
1950 51	1 258	25	44 8	50	23	73
1965 66	1,959	25	37 0	78	29	107
1975 76	3,150	25	33 3	152	51	203
1985 86	4,150	25	33 3	201	67	268
निम्न-माध्यमिक शिक्षा (व्यावसायिक)						
1950-51	1,705	16	86 8	106	92	197
1965 66	2,887	15	100 0	208	208	417
1975 76	—	—	—	—	—	500
1985-86	—	—	—	—	—	600
उच्च माध्यमिक शिक्षा (साधारण)						
1975 76	1 500	20	33 3	272	91	363
1985 86	5,500	20	33 3	333	111	444
उच्च माध्यमिक शिक्षा (व्यावसायिक)						
1975-76	—	—	—	—	—	700
1985-86	—	—	—	—	—	800

सारणी सभ्या-7

उच्च शिक्षा मे प्रति छात्र औसत वार्षिक लागत

(1950-51 से 1985-86 तक)

संस्था का प्रकार	प्रति प्रध्यापक औसत वार्षिक वेतन	प्रति प्रध्यापक छात्र संख्या	औसत प्रध्यापकीय लागत का प्रध्यापकीय लागत से अनुपात	औसत वार्षिक लागत		
				प्रध्यापकीय लागत के कारण	औसत प्रध्यापकीय लागत के कारण	योग
	रु			रु	रु	रु
मध्य-स्नातक						
(अ) कला एवं वाणिज्य						
1950-51	2,696	20	73.7	133	98	231
1965-66	1,000	20	63.8	200	128	328
1975-76	6,000	15	66.7	140	293	733
1985-86	7,500	15	66.7	500	367	917
(ब) विज्ञान एवं स्वास्थ्यविज्ञान						
1950-51	3,948	11	118.1	357	422	779
1965-66	6,110	11	100.0	581	583	1,167
1975-76	—	—	—	—	—	1,500
1985-86	—	—	—	—	—	2,000
स्नातकोत्तर						
(अ) कला एवं वाणिज्य						
1975-76	10,000	8	118	1,375	1,625	3,000
1985-86	12,000	8	118	1,650	1,950	3,600
(ब) विज्ञान एवं स्वास्थ्यविज्ञान						
1975-76	—	—	—	—	—	5,000
1985-86	—	—	—	—	—	6,000

